असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

23 फरवरी, 2024

सप्तदश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 23 फरवरी, 2024 ई0
एकादश सत्र — 04 फाल्गुन, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । अब उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा ।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-10 के तहत उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना है । उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । सभी प्रस्ताव एक ही माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव के संबंध में प्राप्त हुए हैं । जो प्रस्ताव है उसे मैं क्रमवार सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूं :

क्र0संख्या	प्रस्तावक का नाम	अनुमोदनकर्त्ता का नाम	प्रस्ताव
1.	श्री विजय कुमार सिन्हा स०वि०स०	श्री प्रेम कुमार स०वि०स०	श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स० के पक्ष में
2.	श्री विजय कुमार चौधरी स०वि०स०	श्री सुनील कुमार स०वि०स०	श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स० के पक्ष में ।
3.	श्री श्रवण कुमार स०वि०स०	श्री जनक सिंह स०वि०स०	श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स० के पक्ष में ।
4.	श्री जीतन राम मांझी स०वि०स०	श्री अनिल कुमार स०वि०स०	श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स० के पक्ष में ।
5.	श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव स०वि०स०	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह स०वि०स०	श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स० के पक्ष में ।
6.	श्री सुमित कुमार सिंह स०वि०स०	श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव स०वि०स०	श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स० के पक्ष में ।
7.	श्री अरूण कुमार सिन्हा स०वि०स०	श्री बिजय सिंह स०वि०स०	श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स० के पक्ष में ।
8.	श्री तारकिशोर प्रसाद स०वि०स०	श्रीमती लेशी सिंह स०वि०स०	श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स० के पक्ष में ।
9.	श्री पंकज कुमार मिश्र	श्री रत्नेश सादा	श्री नरेन्द्र नारायण यादव,

	स०वि०स०	स०वि०स०	स०वि०स० के पक्ष में ।
10.	श्री मो0 जमा खान	श्री सुधांशु शेखर	श्री नरेन्द्र नारायण यादव,
	स०वि०स०	स०वि०स०	स०वि०स० के पक्ष में ।
11.	श्री ललित नारायण मंडल	श्री रामविलास कामत	श्री नरेन्द्र नारायण यादव,
	स०वि०स०	स०वि०स०	स०वि०स० के पक्ष में ।

माननीय सदस्यगण, सभी प्रस्ताव नियमानुकूल हैं । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी का प्रस्ताव प्रथम है इसलिए मैं इन्हें प्राथमिकता देता हूं । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0 बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जायं ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका अनुमोदन करता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0 बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जायें ।''

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0 सर्वसम्मति से बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव जी को बिहार विधान सभा के 19वें उपाध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं । मधेपुरा के आलमनगर क्षेत्र से नरेन्द्र यादव जी निर्वाचित होते रहे हैं । वे वर्ष 1995 से, जब से हम सदन में आये हैं, दोनों साथ-साथ सदन में आये हैं, तब से लगातार इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं । नरेन्द्र बाबू काफी विनम्र और मृदुभाषी व्यक्ति हैं । वे जनता के बीच से आये हैं । विधान सभा के सदस्य बनने के पहले वे पंचायत समिति आलमनगर के प्रमुख के पद पर भी कार्यरत रहे हैं । बिहार के ग्रासरूट से निकल कर आये हुए नरेन्द्र बाबू राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रहे हैं । जन नायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में राजनीति में पदार्पण करने वाले नरेन्द्र बाबू हमेशा जनता से जुड़े रहे हैं । कई राजनीतिक घटनाक्रमों में बदलाव हुए परंतु आलम नगर की जनता ने हमेशा नरेन्द्र बाबू के प्रति ही विश्वास दिखाया है ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और इस नये उत्तरदायित्व का निर्वहन वे कुशलतापूर्वक करेंगे ।

पुनः मैं श्री नरेन्द्र नारायण यादव जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं ।

माननीय मुख्यमंत्री ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : महोदय, मैं भी उनको हार्दिक बधाई देता हूं । सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं, मैं भी उनको हार्दिक बधाई देता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नरेन्द्र यादव लंबे समय से, 1995 से बिहार विधान सभा के सदस्य के तौर पर, मंत्री के तौर पर और अब पूरे विधान सभा को उपाध्यक्ष के तौर पर इनका मार्गदर्शन मिलेगा । वे एक लंबे समय से राजनीतिक जीवन में अपनी शालिनता के लिए जाने जाते हैं । सरल व्यक्तित्व इनका है, लोगों के बीच में सरल व्यक्तित्व के तौर पर अपने क्षेत्र में भी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं । मैं उन्हें पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई भी देता हूं और शुभकामना भी करता हूं कि आगे विधान सभा को पूर्ण रूप से इनका मार्गदर्शन मिलता रहे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन जी ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, आज इनका निर्वाचन हुआ है । मैं इनको राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बहुत बधाई देता हूं । जिस तरह से इनके व्यवहार से हमलोग प्रभावित हैं, ये मृदुभाषी जिस तरह से रहे हैं, जिस तरह से सरल रहे हैं बहुत-बहुत इनको बधाई । बहुत शुभकामनाएं देते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय के सर्वसम्मत चुनाव के लिए मैं सदन का भी आभारी हूं, साथ-साथ मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं । महोदय, वे सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, उनका सहज स्वभाव है । मुझे आशा है कि उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होकर वे निष्पक्ष भाव से, जो प्रतिपक्ष के माननीय विधायकों का सवाल है उनके प्रति निष्पक्ष भाव से विचार व्यक्त करेंगे और विचार व्यक्त करने की अनुमति देंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद । शुक्रिया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय नरेन्द्र बाबू आज उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं । मैं इनको दिल की गहराई से,

पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको धन्यवाद और शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे सदन को एक साथ लेकर चलेंगे और स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा जायेगा । धन्यवाद । शुभकामना । फिर से धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी ।

श्री अजय कुमार : महोदय, श्री नरेन्द्र नारायण यादव जी बहुत पुराने सदस्य हैं और इनके बारे में जब मेरे पिता जी विधायक थे तो उनसे इनके बारे में जानकारी मिलती थी । मैं भी जब सदन में आया तो मैं इनको बड़े गौर से देखते रहता था । इतने अनुशासित शायद ही कोई सदस्य आपको इस सदन में मिलेंगे कि जब एक बार सीट पर आ गये तो फिर इधर-उधर बिना हाउस के खत्म हुए निकलते नहीं हैं । इसलिए मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि इनका पूरा अनुभव इस सदन को मिलेगा, एक सदस्य के रूप में मिला है और फिर अब एक उपाध्यक्ष के रूप में भी मिलेगा ।

मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी उपाध्यक्ष के लिए जो, हम पूरे सदन की ओर से श्री नरेन्द्र नारायण यादव जी जो सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के लिए चुने गये हैं । हम अपने दल की ओर से और पूरे विपक्ष की ओर से उन्हें आश्वस्त करता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर बिना भेदभाव के विधान सभा का संचालन ये करेंगे । इन्हीं उम्मीद के साथ अपने दिल की गहराई से ढ़ेर सारी शुभकामनाएं । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान जी ।

श्री अखतरूल ईमान : जनाबे स्पीकर साहब, मैं अपने दिल की गहराइयों से मोअज्जज रूकने असेम्बली के जनाबे नरेन्द्र नारायण यादव साहेब के डिप्टी स्पीकर बनने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं । बहुत पहले से इनको देखा है । वैसे वजीर को देखा है, अपने और गैर की कोई तमीज नहीं सबको अपना समझते रहे हैं । हमें उम्मीद है कि इस कुर्सी पर भी बैठकर वे एक मिशाली किरदार निभायेंगे और आज के इस राजनीतिक जवालियाफ्ता दौर में जबकि राजनीति में मर्यादाएं टूट रही हैं, ऐसे वक्त में हमारे दरमयान में ऐसे लीडरों का होना बड़ी बात है । हम इनकी लंबी आयु की भी दुआ करते हैं और इनके तजुर्बा से सदन को नई रौशनी मिले हम इसकी उम्मीद करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री महेश्वर हजारी ।

श्री महेश्वर हजारी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ है । मैं आदरणीय समाजवादी नेता श्री नरेन्द्र नारायण

यादव जी को धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि इनके कार्यकाल में सदन शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा और पक्ष-विपक्ष सबको लेकर ये चलेंगे । आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय नरेन्द्र बाबू जैसे व्यक्तित्व जो समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं

..क्रमशः..

टर्न-2/हेमन्त/23.02.2024

श्री महेश्वर हजारी(क्रमशः) और इनका इस पद पर पदधारण होने से सदन की गरिमा बढ़ेगी । इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री भाई वीरेन्द्र जी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उपाध्यक्ष के पद पर माननीय आदरणीय नरेन्द्र नारायण यादव जी का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ । माननीय अध्यक्ष का और माननीय उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति से इस सदन में निर्वाचन हुआ है, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इनका लंबा इतिहास रहा है और अनुभव रहा है, उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा और हमें इन पर पूरा भरोसा है । ये मृदुभाषी व्यक्ति हैं और नियम-कानून से चलने वाले हैं । मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और इनके मार्गदर्शन में हम लोग सदन को चलाने का काम करेंगे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र नारायण यादव जी ।

उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं एवं मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन से मैं यहां तक पहुंचा हूं । मैं माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट बाबू के प्रति एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय विजय बाबू के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और माननीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय बिजेन्द्र बाबू के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं । महोदय, मुझे इस पद पर आसीन करने वाले सभी प्रस्तावक एवं अनुमोदनकर्ता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं । मैं इस सदन में सभी दलों के नेतागण के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे सर्वसम्मति से इस पद पर चुनने का कार्य किया है । मैं पूर्व उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी साहब के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं पुनः आप सबों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं ।

महोदय, मुझे इस वक्त पंच परमेश्वर की एक पंक्ति याद आती है जिसमें कहा गया था कि- ''पंच न तो किसी का दोस्त होता है, न दुश्मन होता है और पंच के मुंह से जो वाणी निकलती है, वह खुदा के मुंह से वाणी निकलती है।'' मैं आसन पर रहकर पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुनकर, दोनों को साथ लेकर सदन की कार्यवाही को बढ़ाने का काम करूंगा और मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि सार्थक बहस हो, जनता की समस्या उठे, सरकार उसका निराकरण करे, यह मेरी इच्छा रहेगी । महोदय, संत कबीर की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि -

''ऐसी वाणी बोलिये, मन का आपा खोए,
औरों को शीतल लगे, आपहुं शीतल होए ।''

इतना ही कहकर मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

<u>प्रश्नोत्तर काल</u>

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

अमरेन्द्र जी का प्रश्न है । श्री अरूण शंकर प्रसाद जी प्राधिकृत हैं ।

(व्यवधान)

कार्यस्थगन दिया है न, तो बैठिये न ? आप जानते ही हैं कि हम पढ़वा देंगे आपको, तो बैठिये । क्यों घबरा रहे हैं ?

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-22, श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र सं0-194, आरा)</u>

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री(लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत ड्रग रेसिस्टेंट टीबी मरीजों के पहचान एवं इलाज के लिए जांच उपकरण की उपलब्धता/अनुरक्षण, दवा की उपलब्धता, जांच हेतु रसायन, जांच किट (Truenat Chip/CBNAAT Cartridge आदि) केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है ।

राज्य में Truenat Chip की कमी होने पर केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में माह मई, 2023 में 50,000 Truenat Chip का क्रय BMSICL के माध्यम से क्रय कर जांच हेतु जिलों को Truenat Chip आपूर्ति की गयी है ।

वर्ष 2023 में CBNAAT मशीन द्वारा 154117 एवं Truenat मशीन द्वारा 77657 सम्भावित ड्रग रेसिस्टेंट टीबी मरीजों के बलगम की जांच की गयी है।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नांकित विषय में केवल इतना है कि जो यह किट है वह छः महीने से, कहना है कि उपलब्ध नहीं है, लेकिन उत्तर बड़ा लंबा-चौड़ा

दिया गया है । महोदय, लेकिन यह विषय स्पष्ट नहीं किया गया है कि 2023 के अंतिम छमाही में यह किट उपलब्ध थी कि नहीं । बस इतना ही उत्तर देना है, माननीय मंत्री जी से यही जानना चाह रहा हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि 50,000 किट उपलब्ध थी । यदि माननीय सदस्य ने अपनी चिंता जाहिर की कि पिछले 6 महीने में कितनी उपलब्ध थी, इसकी मैं समीक्षा कराकर उपलब्ध करा दूंगा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-23, श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र सं0-219, गोह)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-24, श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र सं0-194, आरा)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री(लिखित उत्तर) : अनिबंधित न्यासों में से जिन न्यासों के निबंधन का आवेदन बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्राप्त होता है, उन आवेदनों पर नियमानुकूल कार्रवाई के उपरांत उन न्यासों को निबंधन करने की प्रक्रिया सतत जारी है ।

इसके अतिरिक्त भी बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा जनप्रतिनिधियों, स्थानीय प्रशासन से भी उनके क्षेत्र में अवस्थित मठ-मंदिरों के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की जाती है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत उक्त मठ-मंदिरों के निबंधन हेतु नियमानुकूल अधिनियम की धारा-34 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत समीक्षोपरांत कार्रवाई की जाती है ।

जहां तक मठ-मंदिरों की भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का प्रश्न है, उक्त के संबंध में आवेदन प्राप्त होने के उपरांत इस हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास न्यायाधिकरण में मठ-मंदिरों की अवैध कब्जा की गयी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु वाद संस्थित करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

साथ ही, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद एवं सरकार के स्तर से भी समय-समय पर मठ-मंदिरों की भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को पत्र लिखा जाता है ।

अध्यक्ष : अरूण शंकर जी, पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, अतिक्रमण मुक्त कराने और निबंधन से संबंधित यह प्रश्न है और दोनों विषयों का उत्तर इसमें स्पष्ट नहीं आया है । महोदय, मैं माननीय मंत्री

जी से जानना चाहता हूं कि जो मठ-मंदिर निबंधित नहीं हैं, उसको कब तक सर्वेक्षण कराकर, चूंकि 1905 के बाद इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है, मठ-मंदिरों की भूमि का, तो 1905 के बाद अब इसका सर्वेक्षण जो प्रारंभ है, उस सर्वेक्षण को कब तक पूरा कराकर मठ-मंदिरों की जमीन का निबंधन कराकर और उसके स्वामित्व में जो भूमि है और वह अतिक्रमित है, उसको कब तक खाली करवा लेंगे।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, विधि विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वेक्षण का कार्य राजस्व विभाग के द्वारा कराया जाता है और उनके द्वारा यह सर्वेक्षण का कार्य चलाया जा रहा है । जैसे ही सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जाता है, तो इसका मिलान कराकर इसको तीन महीने के समय के अंतराल में इसको पूर्ण किया जायेगा ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय,..

अध्यक्ष : हो ही गया । माननीय मंत्री जी तीन महीने का इतना निश्चित समय दे रहे हैं । इतने बेहतर जवाब के बाद क्या पूरक है ? बैठिये आप ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : मंत्री जी को धन्यवाद इसके लिए कि तीन महीने में यह महत्वपूर्ण काम अगर पूरा हो जाय तो इस राज्य का बहुत भला होगा ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री ललन कुमार ।

तारांकित प्रश्न संख्या-743, श्री ललन कुमार(क्षेत्र सं0-154, पीरपैंती(अ0जा0))

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री(लिखित उत्तर) : (1), (2) एवं (3) केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के वर्तमान मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदलने का निर्णय लिया गया है । जिसे वर्ष 2025 तक पूरा किया जाना है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के वितरण कम्पनी द्वारा बिलिंग एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से एवं रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाईजी का चयन फ्रेंचाईजी स्कीम के तहत सीमित अवधि के लिए किया जाता है । निविदा में निहित शर्तों के तहत एजेंसी को एवं फ्रेंचाईजी स्कीम के तहत आर0आर0एफ0 को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है । बिलिंग एजेंसी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एम0आर0सी0 के माध्यम से बिलिंग एवं कलेक्शन कार्यों को क्रियान्वयन करता है । एम0आर0सी0 के पारिश्रमिक का भुगतान एजेंसी द्वारा किया जाता है । इलेक्ट्रिक सप्लाई कोड की कंडिका 8.6(C) में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का प्रावधान है।

स्मार्ट मीटर अधिष्ठापित क्षेत्रों में बिलिंग एजेंसी एवं आर0आर0एफ0 द्वारा उपभोक्ता का मीटर रिचार्ज करने पर अनुमोदित दर से कमीशन का भुगतान किया जाता है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मुद्रित है । हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि इन्होंने जवाब में कहा है कि स्मार्ट मीटर जहां-जहां लग चुके हैं, तो एजेंसी को जो बिलिंग होगा, रिचार्ज जो करेगा, उनसे उनको कमीशन जायेगा मीटर रीडर को और मीटर रीडर स्मार्ट मीटर लगने से बेरोजगार हो रहे हैं, उनके सामने रोजगार संकट है । यह कमीशन कैसे जायेगा, क्या तरीका है उनको कमीशन जाने का ? क्योंकि स्मार्ट मीटर रिचार्ज घर बैठे होता है, ऑनलाईन भी होता है, एजेंसी भी करती है, लेकिन जो मीटर रीडर बेरोजगार हो रहे हैं स्मार्ट मीटर लगने से, उनको कमीशन कैसे पहुंचेगा, यह जरा स्पष्ट कर दें सदन को ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अस्थायी तौर पर मीटर रीडर को नियुक्त किया गया था, चूंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है । एजेंसी को ही पांच साल के लिए ठेका दिया गया है, वह अपना अलग से चयन करता है, वह उसका जवाब है और वह अस्थायी था, चूंकि अब स्मार्ट मीटर लग रहा है । इसलिए उसकी नियुक्ति स्थायी तौर पर नहीं हुई थी, इनकी नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि मीटर रीडर, हजारों मीटर रीडर हैं, जिन्होंने अच्छी सेवा दी है, अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन विभाग को दिया है, उनके सामने अब रोजगार की समस्या खड़ी हो गयी है स्मार्ट मीटर लगने से । अब वह करेगा क्या ? सरकार सिर्फ ठेकेदारों का या संविदा पर एजेंसी के लिए तो नहीं है, सरकार युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए है । आज सरकार किसी को ठेका देकर, किसी एजेंसी को काम देकर अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकती, जवाबदेही तो है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वह अस्थायी कर्मचारी थे ।

श्री ललन कुमार : नहीं, वह अस्थायी नहीं थे । उनको मुश्किल से आठ हजार, दस हजार मिलता था, उसी से जीवनयापन किसी तरह से कर रहा था, उनके सामने काफी सुसाइडल स्थिति हो जायेगी, वह क्या करेगा ?

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री ललन कुमार : महोदय, पूरक हम यह कह रहे हैं कि आपकी जवाबदेही है कि उन युवाओं को अब कहीं दूसरे कामों में समायोजित किया जाय या जो उसका मीटर रिचार्ज का कमीशन जायेगा, ऐसी कोई पॉलिसी बनायें जिसके तहत उनको रिचार्ज का कमीशन जाय । उनसे विभाग में कोई काम लीजिये, हम यह चाह रहे हैं । इस पर सरकार स्पष्ट करे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इनकी माँग है, मैंने कहा अस्थायी तौर पर उसकी नियुक्ति की गयी थी, भुगतान भी किया जा चुका है । अब चूंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है तो जो एजेंसी काम कर रही है उसका उत्तरदायित्व है । अब सरकार के पास इस विषय में कोई विचाराधीन मामला नहीं है ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक है । हम यह कह रहे हैं कि इस तरह से हजारों युवा हैं । स्मार्ट मीटर के लगने से सड़क पर आ रहे हैं और आज सरकार एजेंसी के माथे उनको, हम क्या, अब इस देश में उदारीकरण और भूमंडलीकरण, निजीकरण के कारण ऐसी स्थिति, युवाएं सुसाइड करेंगे, सपरिवार सुसाईड कर रहे हैं । अब बेरोजगारों को....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये । भाषण मत दीजिये, पूरक पूछिये ।

श्री ललन कुमार : महोदय, पूरक यह है कि सरकार उनको ठेकेदार के भरोसे नहीं छोड़े, सरकार उनको कहीं पर समायोजित करे और सरकार समायोजित करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है ? सरकार हमको इस पर स्पष्ट बता दे क्योंकि सरकार सिर्फ ठेकेदारों की जिम्मेवारी लेकर नहीं बैठी है, रोजगारों की जिम्मेवारी....

अध्यक्ष : बैठिये । सरकार ने तो कहा ललन जी.....

(व्यवधान)

श्री ललन कुमार : नहीं महोदय, सरकार तो ठेकेदारों पर छोड़.....

अध्यक्ष : सुनिये, पहले बैठ जाइये । सरकार ने साफ कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है तो उसके बाद सवाल कहाँ खड़ा होता है ।

श्री ललन कुमार : नहीं महोदय, वह योजना, वह काम कर रहे...

अध्यक्ष : आपका तीन पूरक हो गया ।

श्री ललन कुमार : नहीं महोदय, एक पूरक बचा है । यह बता दें....

अध्यक्ष : तीन पूरक हो गया आपका । महा नंद जी, आप बोलिये ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, ये मीटर रीडर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, कई लोगों की तो उम्र भी खत्म हो गयी है । अब उन लोगों को निकाल देना, कुछ दिनों तक काम करवाना फिर निकाल कर बाहर कर देना । महोदय, यह कहीं से उचित नहीं है । इसलिए उनको समायोजन करने पर विचार सरकार करती है या नहीं ? जितना आउट सोर्सिंग के जरिये जो काम करवाया जा रहा है, उसमें भारी लूट हो रही है, महोदय । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार आउट सोर्सिंग बंद करे और उन लोगों को स्थायी नौकरी देने का काम करे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-744 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह, क्षेत्र संख्या-67, मनिहारी(अ॰ज॰जा॰))

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अंतर्गत लखनपुर पंचायत के डकरा यादव टोला वार्ड संख्या-4 में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 220 है । वार्ड संख्या-6 में अधिष्ठापित 63 के॰वि॰ए॰ के ट्रान्सफॉर्मर में वार्ड संख्या-4 में विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, जिसकी दूरी लगभग 01 किलोमीटर है । कनीय विद्युत अभियंता, अमदाबाद द्वारा कुछ उपभोक्ताओं के परिसर में वोल्टेज की जाँच की गई, जिसमें औसतन 218 वोल्ट पाया गया है ।

वार्ड संख्या-6 में पूर्व से अधिष्ठापित 63 के॰वी॰ए॰ ट्रान्सफॉर्मर की क्षमता विस्तार 100 के॰वी॰ए॰ के ट्रान्सफॉर्मर से कर लो-वोल्टेज की समस्या का समाधान कर दिया गया है । वर्तमान में वार्ड संख्या-4 एवं वार्ड संख्या-6 में विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, उत्तर में जो वार्ड नं॰-6 से वार्ड नं॰-4 की दूरी 01 किलोमीटर बतायी गयी है जो कि उचित नहीं है, सही नहीं है । इसकी दूरी 02 किलोमीटर से कम नहीं है । दूसरी बात है कि 15 दिन पहले वार्ड नं॰-6 में ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है जो कि दूरी दो किलोमीटर हो गयी, वहाँ ट्रांसफॉर्मर लगाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है आंशिक सुधार हुआ है । इसलिए अपेक्षित सुधार के लिए सरकार क्या उस वार्ड नं॰-6 में जो स्थापित ट्रांसफॉर्मर है, वह वार्ड नं॰-4 में स्थापित करना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री,

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, पूरी जाँच कर ली गयी है, सुनिश्चित है वहाँ, सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है । फिर भी अगर माननीय सदस्य को चिंता है तो फिर दिखवा लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो उसका सुधार कर दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-745 (श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, क्षेत्र संख्या-102, कुचायकोट)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-746 (श्री राहुल तिवारी, क्षेत्र संख्या-198, शाहपुर)

डॉ॰ प्रेम कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मृतक रितेश कुमार गुप्ता के पिता-श्री विनोद कुमार गुप्ता को चेक संख्या-087267, दिनांक-15.02.2024 द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि मो॰ 4.00 लाख (चार लाख) रुपये का भुगतान किया जा चुका है ।

श्री राहुल तिवारी : महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसमें मृतक के आश्रित परिवार को मुआवजा की राशि का भुगतान हो गया है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-747 (श्री पवन कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-155, कहलगाँव)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, 1 एवं 2-उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला के गोराडीह प्रखंड अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र कासील हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का भवन निर्माण हेतु स्वीकृत है परन्तु भूमि अतिक्रमण रहने के कारण भवन निर्माण कार्य वर्तमान में प्रारंभ नहीं हो सका है ।

सिविल सर्जन, भागलपुर के पत्रांक-614, दिनांक-18.04.2023 एवं पत्रांक-944, दिनांक-22.06.2023 के द्वारा अपर समाहर्त्ता, भागलपुर से भवन निर्माण हेतु किसी अन्य उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । भूमि उपलब्ध हो जाने पर भवन निर्माण कराने की प्रक्रिया प्रारंभ करा दी जायेगी ।

3-उपरोक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल-दो साल पूर्व स्वास्थ्य केन्द्र के लिए टेंडर हो गया है लेकिन जमीन अधिग्रहण नहीं हो रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सुदूर गाँव में बुढ़ी माताएं हैं, बुढ़े गार्जियन हैं, किसान परिवार हैं, उनको 15 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केन्द्र में जाना पड़ता है । इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि जमीन अधिग्रहण करा कर उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाता तो उस इलाके के लिए बहुत बढ़िया होता।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा और माननीय सदस्य की जो चिंता है कि वहाँ पर स्वास्थ्य उप केन्द्र तुरंत बने तो अतिक्रमण है, उसको हटवा कर और जिलाधिकारी से आग्रह कर कि तीन महीने के अंदर पूरे अतिक्रमण को हटाकर इस जगह पर कार्य प्रारंभ करायें ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़िया आश्वासन मिला है । इसलिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-748 (श्रीमती स्वर्णा सिंह, क्षेत्र संख्या-79, गौड़ाबौराम)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उप केन्द्र, सिरनियाँ अपने भवन में संचालित है । भवन में छोटे-मोटे मरम्मति की आवश्यकता है, जिसे शीघ्र ही करा लिया जायेगा । फलस्वरूप नये भवन निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर है परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि उप स्वास्थ्य केन्द्र, सिरनियाँ का भवन काफी जर्जर है । यह मरम्मत के लायक नहीं है तो इसको अगर तोड़कर नया भवन बनाने हेतु इस पर विचार किया जाय । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की जो चिंता है कि इसका भवन बहुत जर्जर है तो मैं इनके साथ ही एक टीम भेजता हूँ । यदि उसके फलाफल के बाद अगर विभाग को यह लगेगा कि इसके बावजूद बनाने की जरूरत है, वैसे हमारे रिपोर्ट के हिसाब से यह बताया गया है कि छोटे-मोटे मरम्मति का कार्य कराये जा सकते हैं लेकिन माननीय सदस्या संतुष्ट नहीं हैं तो मैं इनके साथ एक टीम भेजकर पूरी इसकी समीक्षा करा लेता हूँ, उसके बाद निर्णय लूंगा ।

अध्यक्ष : बहुत अच्छा ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : महोदय, धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-749 (श्री कुमार शैलेन्द्र, क्षेत्र संख्या-152, बिहपुर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नारायणपुर प्रखंड के चूहर पश्चिम पंचायत के वार्ड संख्या- 1 एवं 2 में नया बसावट बसा है । उपर्युक्त बसावटों में पूर्व से स्थापित विद्युत संरचना से इच्छुक व्यक्तियों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है । विद्युत संरचना के सुदृढ़ीकरण

हेतु आर॰डी॰एस॰एस॰ योजना अंतर्गत कार्य प्रगति पर है । विद्युत संरचना के सुदृढ़ीकरण का कार्य करने का लक्ष्य अप्रील, 2025 है ।

2- नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत जयपुर चूहर पश्चिम पंचायत के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु कुल 111 अद्द आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके विरुद्ध 87 अद्द कृषि विद्युत संबंध प्रदान कर दिए गए हैं । शेष आवेदकों को कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने हेतु आर॰डी॰एस॰एस॰ योजना के फीडर पृथ्ककरण अवयव के अंतर्गत विद्युत संरचना का निर्माण किया जा रहा है । साथ ही, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना फेज-2 के अंतर्गत विद्युत संरचना एवं कृषि विद्युत संबंध प्रदान किया जाना है । शेष आवेदकों को कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने हेतु दिसम्बर, 2024 लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

3- उत्तर उपर्युक्त खण्डों में सन्निहित है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है । महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब आया है कि यह बिल्कुल नया बसावट है और वहाँ पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है । महोदय, यह रिपोर्टिंग गलत है, एक बार जाँच करा ली जाय । वहाँ पर किसी तरह लोग तार अपना खींच कर जला रहा है । यह जो विभाग के लोगों ने दिया है कि वहाँ पूर्णरूपेन विद्युत आपूर्ति की जा रही है तो महोदय, वहाँ पर विद्युत आपूर्ति अपने से लोग बांस के द्वारा लाईन की तार खींच कर बिजली ले रहा है अभी भी। दूसरा में कहा जा रहा है कि आर॰डी॰एस॰एस॰ योजनांतर्गत कार्य प्रगति पर है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप तो उत्तर पढ़ रहे हैं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : नहीं, महोदय । उत्तर नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा बताना पड़ता है । महोदय, दूसरा कृषि विद्युत संबंधी प्रदान के लिए इन्होंने जो कृषक को लाईन कनेक्शन दिया जा रहा है, उसमें इन्होंने साफ लिखा है कि दिसम्बर, 2024 लक्ष्य निर्धारित है । महोदय, किसान, आजकल इतने आधुनिक युग में अब चाहते हैं । केवल मंत्री महोदय से हम जानना चाहते हैं कि क्या इतने दिन किसान इंतजार करेंगे जो दिसम्बर, 2024 लक्ष्य है ? मतलब कैसे वे अपना सिंचाई करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लगता है कि ठीक से इन्होंने उत्तर पढ़ा नहीं है । नये बसावट में ठीक है, अभी अस्थायी कनेक्शन से लोग विद्युत का उपभोग कर रहे हैं । आर॰डी॰एस॰एस॰ कार्यक्रम के तहत कार्रवाई चल रही है, उसको

स्थायी किया जायेगा । जहाँ तक किसान कनेक्शन का मामला है, मैं सभी माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि अभी आवेदन लिये जा रहे हैं, सभी लोग अप्लाई करें, उसके बाद कनेक्शन बारी-बारी से दिये जायेंगे ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, एक मिनट ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पहले उनका हो जाने दीजिये, उनका प्रश्न है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय मंत्री महोदय जी बहुत आश्वासन दिये हैं, केवल मंत्री महोदय आश्वस्त कर दें कि दिसम्बर, 2024, बहुत सारा आवेदन अप्लाई किया हुआ है और वे सिर्फ जल्दी से अधिकारी को कह दें कि किसान जो खेती, पटवन करना चाहते हैं.....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मुख्यमंत्री कृषि रोड मैप के तहत चार लाख सत्तर हजार किसानों को देना है तो कार्रवाई बारी-बारी से होगी, वक्त तो थोड़ा लगेगा लेकिन माननीय सदस्य अप्लाई करा दें, फर्स्ट फेज में इनका देने का प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष : जल्दी करा दिया जायेगा, आपका हो गया । माननीय सदस्य अजय जी ।

श्री अजय कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना है कि कृषि (एग्रीकल्चर) फीडर के लिए या किसानों को कनेक्शन देने के लिए जो योजना ली गयी जिसके बारे में आप बता रहे हैं । क्या बिहार के किसानों को इसकी जानकारी है ? जहाँ तक मुझे पता है कि विभूतिपूर में....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय....

श्री अजय कुमार : महोदय, मेरा क्वेश्चन तो पूरा हो जाने दीजिये....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मेरी बात सुन तो लीजिये । आप माननीय सदस्य हैं, अखबार में भी विज्ञापन दे दिया जा चुका है । आप माननीय सदस्य भी सभी लोगों को बताइये और मदद कीजिये, हमारी यह अपेक्षा है ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मेरा सवाल तो पूरा हो जाने देते । मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना था कि जिस रूप में सरकार किसानों के प्रति गंभीर है, कितने किसान अखबार पढ़ते हैं ? क्या इसके लिए सरकार कोई स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार की योजना बना कर, सभी किसानों का कैम्प लगाकर करने का विचार रखती है या नहीं ? यह हमारा कहना है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, कैम्प का आयोजन किया जा रहा है और आपसे भी निवेदन है कि उसमें मदद कीजिये ।

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य भी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सभी का मदद करें ।

(व्यवधान)

लगाया जा रहा है यह कहा है उन्होंने । आपके यहाँ अभी नहीं गया होगा, पहुँच जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-750 (श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र संख्या-38, झंझारपुर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के आम लोगों को शव वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में कुल 73 शव वाहन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों में प्रतिनियुक्त एवं परिचालित है ।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1071 (12), दिनांक-04.10.2016 के द्वारा उक्त संदर्भ में निदेशित किया गया है कि शव वाहन के अन्य शव के परिवहन में व्यक्त होने अथवा शव वाहन खराब होने एवं आकस्मिकता की स्थिति में संबंधित सिविल सर्जन, उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का यह दायित्व होगा कि शव के परिवहन हेतु अन्य एम्बुलेंस अथवा किराये का वाहन उपलब्ध करायेंगे।

वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा जिला अस्पतालों में ही शव वाहन उपलब्ध कराये गये हैं । अनुमंडलीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में शव वाहन उपलब्ध कराने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूर्णतः मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ है । सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि पूरे बिहार में मात्र 73 शव वाहन हैं और वर्ष 2016 के एक सर्कुलर का जिक्र किया गया है जिसमें बताया गया है कि सिविल सर्जन को और वैसे संबंधित पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि अगर शव वाहन उपलब्ध नहीं है तो वे कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर उनको शव वाहन उपलब्ध कराना है । हम सब अपने क्षेत्र में आये दिन देखते हैं कि सड़क पर दुर्घटनाएँ होती हैं.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, वही पूछ रहा हूँ । तो सरकार ने यह कहा है कि पी॰एच॰सी॰ या सी॰एच॰सी॰ में यह देने की अभी वर्तमान में कोई योजना नहीं है । बहुत बड़ी संख्या में सी॰एच॰सी॰ और पी॰एच॰सी॰ हमलोगों के यहाँ कार्यरत है, अनुमंडल अस्पताल भी हैं । (क्रमशः)

टर्न-4/संगीता/23.02.2024

श्री नीतीश मिश्रा (क्रमशः) : मेरा आग्रह होगा क्योंकि जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो बहुत विचित्र स्थिति होती है शव को पोस्टमॉर्टम में ले जाने के लिए...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक यही है कि सरकार से मेरा आग्रह होगा कि आने वाले समय में जैसे हम एम्बुलेंस की व्यवस्था देते हैं या तो अनुमंडल अस्पताल तक हम एम्बुलेंस उपलब्ध करायें या इस सर्कुलर को 8 वर्ष के बाद समीक्षा करके पुनः एक निर्देश जारी हो कि जिन अनुमंडल अस्पतालों में शव-वाहन उपलब्ध नहीं हैं, वहां किराए पर लें, बड़ी संख्या में पदाधिकारी भी किराए के वाहन लेते हैं...

अध्यक्ष : यह आपका सुझाव है ?

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सुझाव भी है, आग्रह भी है और प्रश्न यह है कि आने वाले समय में सरकार योजना बनाना चाहेगी कि शव-वाहन अनुमंडल अस्पताल तक जरूर रहे अगर सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में कठिनाई है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है कि इसको नीचे लेवल तक अनुमंडल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसको उपलब्ध कराया जाय, इसकी समीक्षा कर लेता हूं, यदि इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार जरूर निर्णय लेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-751 (श्री अखतरूल ईमान, क्षेत्र संख्या-56, अमौर)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- आंशिक स्वीकारात्मक ।

जिला पदाधिकारी, पूर्णियां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पूर्णियां जिला अन्तर्गत अमौर प्रखंड के बरबट्टा पंचायत के वार्ड नं0-08 के ग्राम-बिजलिया में 10 घर (झोपड़ी) एवं वार्ड नं0-04 के ग्राम-हजरिया में 05 घर (झोपड़ी) परमान नदी के कटाव से प्रभावित हुआ है ।

2- प्रश्नगत मामले में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-198/आ0प्र0 दिनांक-21.02.2024 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, पूर्णियां को अधियाचित राशि उपलब्ध करा दी गयी है । प्रभावित परिवारों को अनुदान उपलब्ध करने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिए ।

श्री अखतरूल ईमान : जी, सर । मैं शुक्रगुजार हूं कि माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है लेकिन मैं यह जानना चाह रहा हूं कि बाध्यता है हमारी कि हम अपने एक प्रश्न में बहुत ज्यादा गांव का तसकरा नहीं कर सकते । हमने इसमें बिजलिया का और हजरिया का मामला उठाया है लेकिन मेरे दोनों प्रखंडों में जिस तरह से मामला लंगड़ा टोली का है, रसेली, सिरसी, बनगामा, सिमलबाड़ी, क्या इन सभी गांवों की समीक्षा किए हैं ? वर्ष 2023 और उससे पहले जिन लोगों के घर कटे हैं, उनको राशि नहीं मिली है, क्या उनकी समीक्षा करते हुए तमाम लोगों को चूंकि सरकार संवेदनशील है, गंभीर मंत्री जी हमारे हैं और सर, एक शब्द कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है और हमारे यहां दोनों प्रखंड में लगभग 2500 लोग अब तक वंचित हैं, माननीय मंत्री उसको कब तक दिलायेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया गया है और राशि भुगतान कर दी गई है और प्रभावित परिवारों को क्षति की राशि प्रति झोपड़ी 8000 रुपये की दर से भुगतान दिनांक-22.02.2024 को कर दिया गया है । महोदय, इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो चर्चा की है वह प्रश्न में है नहीं, वे अलग से लिखकर दे दें, अभी जांच कराकर निश्चित तौर पर प्रावधान के तहत मुआवजा दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, एक सवाल है कि उसमें पक्का के कुछ मकान भी हैं, पक्का मकान वालों को भी झोपड़ी का पैसा दिया जा रहा है...

अध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजिए न, जो होगा सरकार के नियम के अनुसार मिलेगा ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : जो प्रावधान होगा, आप लिखकर मुझे दे दें, हम जांच करवाकर प्रदान करवा देंगे ।

श्री अखतरूल ईमान : ठीक है, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री रामवृक्ष सदा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-752 (श्री रामवृक्ष सदा, क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-753 (श्री समीर कुमार महासेठ, क्षेत्र संख्या-36, मधुबनी)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- आंशिक स्वीकारात्मक ।

2- अस्वीकारात्मक ।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बाढ़ या अतिवृष्टि की पूर्व तैयारी मार्च माह से ही शुरू हो जाती है । सभी संबंधित विभाग यथा-कृषि, पशुपालन, जल संसाधन, पथ निर्माण आदि के साथ बाढ़ पूर्व कार्य योजना एवं तैयारी की समीक्षा बैठक नियमित रूप से लगातार की जाती है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में ससमय त्वरित कार्रवाई की जा सके ।

3- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रशिक्षित कार्मिक/विशेषज्ञ के सहयोग से मधुबनी जिला के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया है । प्रासंगिक जिला आपदा प्रबंधन योजना में मधुबनी जिला के सभी विधान सभा क्षेत्र के आपदाओं का एसेसमेंट कर Action Plan तैयार किया गया है । किसी भी आपदा के समय उक्त तैयार Action Plan के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई की जाती है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, जवाब आया हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग । उत्तर पढ़ दीजिए इनका ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, उत्तर खंड-1...

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, जवाब आया हुआ है ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप पूरक पूछिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मेरा यह कहना है कि स्पेसिफिक मधुबनी जिला के लिए हमने पूछा था और निश्चित तौर पर आपदा के मामले में वहां पर जो हमारे चिन्हित हैं, पंडौल दो ब्लॉक है हमारा, दोनों में लगभग 700 से 800 एकड़ जमीन ज्यादा अतिवृष्टि से हमेशा जलप्लावित रहता है । मुख्य कारण है बगल में एन0एच0 गया है, और बगल में रेलवे ने एक ट्रैक अपना बना दिया है शेड तो नैचुरल पानी निकल ही नहीं पाता है, थोड़ा भी पानी आता है तो 700 से 800 एकड़ जमीन जलप्लावित रहता है कुछ नहीं हो पाता है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : तो वही स्थायी समाधान के लिए सरकार क्या विचार कर रही है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रशिक्षित कार्मिक/विशेषज्ञ के सहयोग से मधुबनी जिला के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया है । प्रासंगिक जिला आपदा प्रबंधन योजना में मधुबनी जिला के सभी विधान सभा क्षेत्र के आपदाओं का एसेसमेंट कर Action Plan तैयार किया

गया है । किसी भी आपदा के समय उक्त तैयार Action Plan के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, चूंकि संरक्षण चाहिए, लगातार 5 वर्षों से...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : 5 वर्षों से लगे हुए हैं, पूरक यही है कि हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पंडौल विधान सभा क्षेत्र में 600 से 700 एकड़ जमीन, थोड़ा भी पानी होता है तो जलप्लावित होता है उसका स्थायी समाधान करवायें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी उसको दिखवा लीजिए ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय...

श्री समीर कुमार महासेठ : कब तक करेंगे, यह बतायें ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, हम अधिकारियों की टीम भेजकर जांच करा देते हैं और समाधान करा दिया जाएगा ।

श्री समीर कुमार महासेठ : चूंकि डी0एम0 की रिपोर्ट आयी है, हर एक बार समीक्षा की जाती है, हर एक बार पानी रहता है । दैट्स द रिजन हमने कहा...

अध्यक्ष : समीर महासेठ जी ऐसा नहीं कहिए, इसके पहले आप ही थे, ऐसा नहीं कहिए । श्री पवन कुमार यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-754 (श्री पवन कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-155, कहलगांव)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- आंशिक स्वीकारात्मक ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत हाई मास्ट लाइट अधिष्ठापन की योजना मार्गदर्शिका में सम्मिलित नहीं है । उल्लेखनीय है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय सांसद से उनकी अनुमान्यता राशि के अधीन प्राप्त अनुशंसा के आलोक में हाई मास्ट लाइट अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है ।

3- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिए ।

श्री पवन कुमार यादव : आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत हाई मास्ट लाइट अधिष्ठापन योजना मार्गदर्शिका में शामिल किया जाय तो क्षेत्र की जनता को काफी लाभ होगा, क्योंकि हम जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में जाते हैं...

अध्यक्ष : पवन जी पूरक पूछिए ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय महोदय, ये चाहते हैं कि कम से कम यहां सदन से यह पारित हो जाए कि माननीय विधायक भी कहीं सार्वजनिक जगह पर हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए हो जाए । इससे क्षेत्र की जनता को काफी अच्छा रहेगा ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए पवन जी ।

श्री पवन कुमार यादव : आग्रह और निवेदन है सदन से कि ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, सरकार द्वारा, पंचायती राज के द्वारा, पंचायत विभाग के द्वारा हर चौक-चौराहे पर किया जा रहा है इसलिए माननीय विधायक के...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पहले सुन तो लीजिए न । उत्तर तो सुनिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय विधायक के फंड में करने का कोई औचित्य नहीं है लेकिन माननीय सदस्य की जब मांग है तो इसपर विचार करेंगे, देखेंगे ।

अध्यक्ष : सरकार विचार करेगी ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय महोदय जी, ये सभी माननीय विधायकों के लिए बहुत बढ़िया होगा क्योंकि जनता जाने पर घेरती है और कहती है कि देखिए सार्वजनिक जगह पर लाईट नहीं है ।

अध्यक्ष : पवन जी, सरकार इस पर विचार करेगी, कहा है सरकार ने ।

श्री पवन कुमार यादव : जी धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-755 (श्री केदार प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र संख्या-93, कुढ़नी)</u>

अध्यक्ष : आपको उत्तर मिला है ?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : नहीं महोदय, किसी कारणवश उत्तर नहीं मिल पाया है ।

अध्यक्ष : नहीं देख पाए हैं । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समाहर्ता, मुजफ्फरपुर से भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन की मांग विभागीय पत्रांक-137(10) दिनांक-23.02.2024 द्वारा की गई है । भूमि उपलब्धता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर इस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण राशि उपलब्धता के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में कराया जाएगा ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में होगा ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, खरौनाडीह से शहर 30 किलोमीटर है और कुढ़नी सी0एच0सी0 वहां से 30 किलोमीटर दूर है, वहां की जनता को काफी दिक्कत होता है...

अध्यक्ष : सरकार तो कह रही है...

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि जितना जल्द हो करा दें ।

अध्यक्ष : एक महीना बाद अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : धन्यवाद, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-756 (श्री सुधांशु शेखर, क्षेत्र संख्या-31, हरलाखी)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : 1- स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प सं0-472 (1) दिनांक-05.07.2023 के द्वारा विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के क्रम में इन्टर्नशिप हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इन्टर्नशिप की सुविधा प्रदान की गयी हे । विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों को इन्टर्नशिप के दौरान छात्रवृत्ति दिये जाने का भी प्रावधान है ।

2- स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-01/विविध-64/2021-472(1) स्वा0, पटना दिनांक-05.07.2023 के आलोक में पी0एम0सी0एच0, पटना में भी विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है ।

3- उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री सुधांशु शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूं । ये भुगतान कब तक कर दिया जाएगा, एक समय सीमा निर्धारित कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि भुगतान किया जा रहा है यदि कोई स्पेसिफिक इनको जानकारी हो तो उपलब्ध करा देंगे, उसकी तुरंत समीक्षा करके उपलब्ध करवा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सुधांशु शेखर : धन्यवाद मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-757 (श्री आबिदुर रहमान, क्षेत्र संख्या-49, अररिया)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- स्वीकारात्मक ।

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-2597 दिनांक-23 जून, 2022 द्वारा श्री अजहरूल हक 5127/भोजपुर, सहायक अभियंता को कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान करते हुए उनकी सेवा योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराया गया ।

उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2835, दिनांक-30 जून, 2022 द्वारा श्री अजहरूल हक, सहायक अभियंता को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, अररिया में कार्यपालक अभियंता के उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिया गया है ।

श्री अजहरूल हक कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध निविदा के डी0पी0आर0 में व्यापक पैमाने पर अनियमितता तथा बहुत सारे योजनाओं का डी0पी0आर0 गलत मंशा से तैयार कर निविदा करने से संबंधित माननीय सदस्य का ही परिवाद पत्र विभाग में प्राप्त है । जिसके आलोक में विभाग स्तर से नियमानुसार कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

2- योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता का पद सहायक अभियंता से प्रोन्नति का पद है । सहायक अभियंता की नियुक्ति 2022 में हुई है । फलतः योजना एवं विकास विभाग में कार्यपालक अभियंताओं की सेवा अन्य कार्य विभागों से प्राप्त की जाती है । तत्पश्चात् इस विभाग से पदस्थापन की कार्रवाई की जाती है ।

श्री आबिदुर रहमान : जी पूछता हूं ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिए ।

श्री आबिदुर रहमान : सर, यह उत्तर सही नहीं है । हमने सहायक अभियंता को सिर्फ अररिया में ही क्यों पोस्टिंग किया गया जबकि वहां कार्यपालक अभियंता पूरे बिहार में कहीं नहीं है सिर्फ वहां पर सहायक अभियंता को बहाल कर दिया गया, लोगों को काम कराने में काफी दिक्कत हो रही है, वह चोर नहीं बल्कि वह डाकू है उसको निकाल कर देखा जाय, मुख्यमंत्री जी को लिखकर दिया गया है और बिजेन्द्र बाबू जी को भी लिखकर दिया गया है कोई सुनवाई आज तक नहीं हो रही है, 3 साल से उसपर...

अध्यक्ष : बैठ जाइए । माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, दिया जा चुका है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है...

श्री आबिदुर रहमान : ठीक है, तो उसको हटाया जाय सर...

अध्यक्ष : बैठा जाय, बैठा जाय । माननीय मंत्री जी, योजना एवं विकास विभाग।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः ठीक है।

श्री आबिदुर रहमान : कब तक हटाया जाएगा हुजूर उसे ?

अध्यक्ष : हो गया न । हटाने का काम सरकार करती है हम थोड़े ही करते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-758 (श्री दिलीप राय, क्षेत्र संख्या-26, सुरसंड)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- आंशिक स्वीकारात्मक ।

सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुरसंड प्रखंड के कुम्मा प्रचायत के वार्ड संख्या-08 एवं वार्ड संख्या-02 11 KV उधाउर फीडर से जुड़े हैं, जिनके जर्जर एवं कम क्षमता के तार को बदलने का कार्य (आर0डी0एस0एस0) Revamped Distribution Sector Scheme के Modernisation अन्तर्गत प्रस्तावित है । इसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिए दिलीप जी ।

श्री दिलीप राय : सर, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग । उत्तर पढ़ दीजिए, उनको उत्तर नहीं मिला है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुरसंड प्रखंड के कुम्मा पंचायत के वार्ड संख्या-08 एवं वार्ड संख्या-02 11 KV साउथ फीडर से जुड़े हैं, जिनके जर्जर एवं कम क्षमता के तार को बदलने का कार्य (आर0डी0एस0एस0) के Modernisation अन्तर्गत प्रस्तावित है । इसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है । कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष : श्री अजय यादव ।

टर्न-5/सुरज/23.02.2024

तारांकित प्रश्न संख्या-759 (श्री अजय यादव, क्षेत्र संख्या-233, अतरी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-760 (डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता, क्षेत्र संख्या-118, छपरा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-761 (श्री उमाकांत सिंह, क्षेत्र संख्या-7, चनपटिया)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मंझौलिया प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरिसवा पूर्णरूपेण संचालित है । वहां एक एम0बी0बी0एस0 एवं एक यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी तथा अन्य कर्मियों द्वारा 24X7 प्रसव एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में चरणबद्ध तरीके से चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जाना है । तदनुसार इस केन्द्र के चहारदीवारी का निर्माण कार्य भी यथाशीघ्र प्रारंभ किया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये । उत्तर मिल गया है न आपको ।

श्री उमाकांत सिंह : महोदय, उत्तर तो मिला है लेकिन वह भवन जर्जर है, 60 साल पहले वह भवन बना है और छत फट-फट कर गिर रहा है । पहले डॉक्टर भी नहीं बैठते थे तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करके वहां डॉक्टर को बैठाया और उत्तर आया है कि वहां भवन बहुत बढ़िया है । चहारदीवारी तो वहां है ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है 20 किलोमीटर के अंदर में दूसरा वहां कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है । तिरवाह इलाका है वह और उतना दूर 20 किलोमीटर में चारों तरफ कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है । तो वहां भवन बनवा दिया जाय और माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि वहां चहारदीवारी करवा दिया जाय ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है वह स्वाभाविक है । हमलोगों ने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि चहारदीवारी नहीं है लेकिन इसको चरणबद्ध ढंग से हमलोग करायेंगे । इस पर माननीय सदस्य की चिंता है कि वहां की बिल्डिंग भी जर्जर है तो इनके साथ ही एक टीम भेजकर इसकी पूरी समीक्षा करा लेता हूं ।

श्री उमाकांत सिंह : बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भवन जल्दी ही बन जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-762 (श्री तारकिशोर प्रसाद, क्षेत्र संख्या-63, कटिहार)

अध्यक्ष : उत्तर आपको नहीं मिला है क्या ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : नहीं ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री :(लिखित उत्तर) माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि जमीन उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय स्तर पर अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया है, परंतु जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया ।

3. वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सदर प्रखंड कटिहार को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोखरिया (कटिहार) में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां 24 घंटे सेवा उपलब्ध करायी जा रही है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कटिहार सदर इसके पूर्व विधायक कोष से निर्मित भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी के भवन में लंबे अरसे तक चल रहा था लेकिन बाद में उस भवन को भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी को सौंप दिया गया और जो सामुदायिक चिकित्सा है और अन्य जो कई मुख्यालय स्तर पर चिकित्सीय सुविधाएं हैं उससे कटिहार सदर के लोग वंचित हैं और प्रखंड परिसर में पर्याप्त परती जमीन है । थोड़ा सा इच्छाशक्ति अगर स्थानीय जिला प्रशासन का बन जायेगा तो जमीन पर्याप्त क्षेत्रफल में वहां उपलब्ध हो जायेगा और उसको बनाने के लिये त्वरित कार्रवाई एक निश्चित अवधि में कराने का आग्रह है ।

अध्यक्ष : तारकिशोर जी आपके यहां जिला अस्पताल है न ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : नहीं, वहां से दूर है । प्रखंड...

अध्यक्ष : हम जो पूछ रहे हैं कि जिला अस्पताल है न ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : हां, जिला अस्पताल है ।

अध्यक्ष : सरकार का एक निर्णय था कि जिस सदर में, जिस जिला हेडक्वार्टर में जिला अस्पताल है, वहां के सदर प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न खोल करके...

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय...

अध्यक्ष : सुन लीजिये, सुन लीजिये न तारकिशोर जी । पूरी बात सुनिये न, तो उसी प्रखंड के दूसरे ए0पी0एच0सी0 को पी0एच0सी0 में कन्वर्ट किया जाय, यह सरकार का निर्णय था । था कि नहीं था और निर्णय करने वाला मैं ही था इसलिये मुझे याद है । तो फिर आप क्यों खोलना चाहते हैं ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, आसन द्वारा शासन का जो परिपत्र है उसका उल्लेख किया गया है, इसके लिये हम धन्यवाद देते हैं । लेकिन महोदय वस्तुस्थिति यह है कि जिस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोखरिया संथाली में उसका स्थानांतरण किया गया है वह एक किनारे है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालय का काफी आवश्यक है क्योंकि सामुदायिक चिकित्सा और कई प्रकार के टीकाकरण हैं जहां से प्रशासनिक स्तर पर भी चिकित्सीय पदाधिकारी उसका संचालन करते हैं । एक अगर उसका अपना भवन नहीं रहेगा तो फिर दवा की जो सामग्री है वह भी पूरे प्रखंड स्तर पर...

अध्यक्ष : हो गया, पूरक पूछिये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अलग-अलग स्वास्थ्य उपकेन्द्र को और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भेजा भी जाता है और वहां से उसका अनुश्रवण भी होता है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : इसलिये आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि एक अवधि निश्चित करके कब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जमीन उपलब्ध कराकर भवन निर्माण प्रारंभ कराना चाहेंगे ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार तो तुरंत वहां निर्माण शुरू करना चाहती है । माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि सहयोग करें । जमीन उपलब्ध होता है तो अगले वित्तीय वर्ष में शुरू कर देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-763 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र संख्या-221, नवीनगर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-764 (मो0 आफाक आलम, क्षेत्र संख्या-58, कसबा)

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न आपको ?

मो0 आफाक आलम : नहीं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग । उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय...

अध्यक्ष : एक मिनट, प्रेम जी । माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, एक निर्णय था सरकार का पहले हम ध्यान दिला दें आपको, यह जनता के हित में था कि जिस हेडक्वार्टर में जिला अस्पताल या अनुमंडल अस्पताल है वहां का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उस प्रखंड के दूसरे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डायवर्ट कर दिया जाय, वहां भेज दिया जाय ताकि ग्रामीण इलाके को भी इसकी सुविधा मिले । एक बार उसको दिखवा लीजियेगा । बोलिये मंत्री जी ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, खण्ड-1. जिला पदाधिकारी, पूर्णिया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पोपरिया पोखर का कुल रकबा 28 एकड़ 29 डिसमिल है ।

खण्ड-2. पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटकीय दर्जा प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि पर्यटकों के लिये पर्यटकीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है ।

खण्ड-3. वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा पूर्णिया जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के पोपरिया पोखर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना नहीं है ।

मो0 आफाक आलम : महोदय, वहां 30 एकड़ की जमीन है और बाहर से काफी चिड़ियां भी आती है तो मेरा कहना है कि उसको पर्यटक स्थल बनाया जाय और अगर नहीं भी है तो उसको पर्यटक स्थल बनवाया जाय । मंत्री जी कब तक इसको पूरा करावायेंगे ?

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, मैं समीक्षा कर लेता हूं जाकर के । समीक्षा करने के बाद जो संभव होगा वह किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी तेज हैं, पुराने हैं, अनुभवी हैं करा लेंगे । बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-'क' 765 (श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, क्षेत्र संख्या-17, पिपरा)

अध्यक्ष : आपको उत्तर नहीं मिला है ?

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, इस प्रश्न को श्रम संसाधन विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, समय चाहिये ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-766 (श्रीमती गायत्री देवी, क्षेत्र संख्या-25, परिहार)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर): महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. यह मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये गायत्री देवी जी ।

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि बिहार सरकार के लेवल-7 में कार्यरत सभी कर्मी के पदनाम से पदाधिकारी शब्द अंकित कर दिया गया है तथा योजना एवं विकास विभाग के कनीय सांख्यिकी सहायक का पदनाम परिवर्तित कर अवर सांख्यिकी पदाधिकारी कर दिया गया है तो मैं मंत्री जी से पूछती हूं कि कनीय सांख्यिकी सहायक एवं सचिवालय सहायक के आधार पर योजना सहायक का पदनाम में पदाधिकारी योजना विस्तार पदाधिकारी योजना जांच अधिकारी करने पर विचार करेंगे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–767 (श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्र संख्या–100, बरौली)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–768 (श्री अली अशरफ सिद्दिकी, क्षेत्र संख्या–158, नाथनगर)

अध्यक्ष : बोलिये, आप तो मेरे पुराने मित्र हैं ।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : महोदय, हमको उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, खण्ड–1. स्वीकारात्मक है ।

2. कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, बेऊर दिनांक– 08.01.2024 एवं 05.02.2024 को पत्नी की चिकित्सा हेतु अवकाश पर थे ।

उक्त कारणवश उस तिथि में उपभोक्ताओं का फोन रिसिव नहीं कर सके ।

3. अस्वीकारात्मक ।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : महोदय, वह हमेशा रिप्लाई नहीं करते हैं इसलिये हमने स्पेसिफिक डेट दिया है, उसके अलावा भी डेट है मेरे पास जिसमें वह रिप्लाई नहीं किये हैं । इसकी व्यवस्था की जाय ताकि कंज्यूमर का वह फोन अटेंड करें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–769 (श्री मोती लाल प्रसाद, क्षेत्र संख्या–23, रीगा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न–6/राहुल/23.02.2024

तारांकित प्रश्न संख्या–'ख' 770 (श्री राहुल तिवारी, क्षेत्र संख्या–198, शाहपुर)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, परिवहन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है ।

श्री राहुल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि किस नियम के तहत ट्रांसफर हुआ है ?

अध्यक्ष : जवाब ही नहीं आया है न । वह आयेगा तब पूछ लीजियेगा ।

श्री राहुल तिवारी : महोदय, ऐसा है...

अध्यक्ष : आयेगा तब पूछ लीजियेगा न क्यों हुआ ?

श्री राहुल तिवारी : महोदय, सरकार का नियम है कि जो व्यक्ति मर जाते हैं आपदा विभाग द्वारा उनको पैसा मिलता है । मेरा कहना है कि एक व्यक्ति मरने पर पैसा भुगतान हो गया...

अध्यक्ष : आज नहीं है न । जब आयेगा तब पूछ लीजियेगा ।

श्री राहुल तिवारी : वही जानना चाहते हैं कि किस नियम के तहत...

अध्यक्ष : उस समय पूछ लीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-'ग' 771 (श्री महबूब आलम, क्षेत्र संख्या-65, बलरामपुर)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री महबूब आलम : उत्तर नहीं आया है महोदय ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, फरवरी माह चल रहा है और मंत्री जी हमेशा जून वाली बात बोल रहे हैं ट्रांसफर हो गया ।

अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, आप बैठ जाइये । महबूब साहब पूरक पूछिये ।

श्री महबूब आलम : उत्तर नहीं आया है महोदय ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण कर दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-772 (श्रीमती रेखा देवी, क्षेत्र संख्या-189, मसौढ़ी (अ0जा0))

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-773 (श्री आलोक रंजन, क्षेत्र संख्या-75, सहरसा)

श्री आलोक रंजन : महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग ।

श्री आलोक रंजन : पर्यटन विभाग का है महोदय ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : पर्यटन से ट्रांसफर होकर आया है ।

अध्यक्ष : पर्यटन से ट्रांसफर होकर आया है । मैंने लघु जल संसाधन अपने मन से नहीं कहा है, ट्रांसफर होकर आया है इसलिए कह रहा हूं ।

श्री आलोक रंजन : अभी नहीं आया है सर ।

अध्यक्ष : अगली बार आयेगा । बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-774 (श्री अजय यादव, क्षेत्र संख्या-233, अतरी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–775 (श्री रणविजय साहू, क्षेत्र संख्या–135, मोरवा)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर): वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलांतर्गत ताजपुर प्रखंड के गोसपुर सरसौना में सीमेंट फैक्ट्री के समीप कृषि ट्रांसफॉर्मर तथा ताजपुर नगर परिषद् के वार्ड नं0–01 के इमली चौक स्थित जले/खराब ट्रांसफॉर्मर को बदल दिया गया है एवं विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है लेकिन हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो समस्तीपुर का ए0सी0 है और हमारे पूसा का जो एस0डी0ओ0 है, पिछले 6 महीने से लगातार मैं टेलिफोन के माध्यम से उसको सूचना दे रहा था कि ताजपुर नगर परिषद् है वहां की महान जनता नगर परिषद् का टैक्स चुकाती है लेकिन आप ट्रांसफॉर्मर चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं । महोदय, 5 बार मोबाईल पर व्हाट्सएप किया गया और आज जब हम सदन के माध्यम से...

अध्यक्ष : बदल गया न ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, बदल गया लेकिन हम जानना चाहते हैं...

अध्यक्ष : बदल गया तब क्या सवाल है ?

श्री रणविजय साहू : महोदय, मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि ऐसे दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष : बदल गया, ट्रांसफॉर्मर लग गया । देखिये, आप विधान सभा की ताकत का अंदाज करिये एक प्रश्न करते हैं और तुरंत एक्शन हो जाता है ।

श्री रणविजय साहू : महोदय,...

अध्यक्ष : लग गया न ? आपका जो प्रश्न था उसका समाधान हो गया । अगला प्रश्न करियेगा तो समाधान होगा । बैठिये ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, माननीय मंत्री जी ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम किये हैं हम उनको बधाई देते हैं लेकिन उनके पदाधिकारी सुनते नहीं हैं । एक विधायक की बात एस0डी0ओ0 नहीं सुने, एस0ई0 नहीं सुने यह बड़ा गंभीर मामला है...

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या–776 (श्री भीम कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या–219, गोह)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–777 (श्रीमती प्रतिमा कुमारी, क्षेत्र संख्या–127, राजापाकर (अ0जा0)

अध्यक्ष: उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारीः सर, उत्तर नहीं देखे हैं माननीय मंत्री उत्तर पढ़ दें।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः उत्तर तो दिया हुआ है।

अध्यक्षः नहीं मिला होगा, देखा नहीं होगा । उत्तर पढ दीजिये।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, महनार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्व0 मुकेश कुमार नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के देसरी पावर हाउस अंतर्गत दैनिक भत्ता पर कार्य नहीं करते थे । इसलिए कंपनी में कार्यरत कर्मी को मिलने वाला मुआवजा प्रावधानिक रूप से नहीं दिया जा सकता है । वर्तमान में संबंधित मामला जिसका कांड संख्या-144/22 है, न्यायालय में विचाराधीन है । माननीय न्यायालय के निर्णय के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिजली विभाग के एस0डी0ओ0 और अधिकारी जो जवाब देते हैं वह बिल्कुल गलत है चूंकि जब मुकेश कुमार सिंह जी की मृत्यु पोल से गिरकर हुई थी और आम आदमी बिना मतलब पोल पर नहीं चढ़ेगा ।

अध्यक्ष : आपने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न अभी न्यायालय में विचाराधीन है जो न्यायालय का निर्णय होगा उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करेगी, यह सरकार ने कहा है ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : महोदय, लेकिन मैं आपके माध्यम से...

अध्यक्ष : न्यायालय में विचाराधीन है तो कैसे हो सकता है ?

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : महोदय, लेकिन वैसे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-778 (श्री बागी कुमार वर्मा, क्षेत्र संख्या-215, कुर्था)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-779 (श्री छोटे लाल राय, क्षेत्र संख्या-121, परसा)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये ।

श्री छोटे लाल राय : उत्तर नहीं मिला है महोदय ।

अध्यक्ष : देखिये, आपको भरोसा नहीं था कि आपका उत्तर आयेगा लेकिन आप सबके सहयोग के कारण सदन के अंदर अधिकाधिक प्रश्न आ रहे हैं । आपका ही लाभ हो रहा है । ऐसे ही शांति बनाये रखिये और प्रश्नोत्तर काल में पूर्ण शांति के साथ काम करिये । उत्तर उसी में मुद्रित है । आप पूरक पूछिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (मुद्रित उत्तर) : (1), (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नावर्णित जिले के दरियापुर एवं परसा में लगभग 16 घंटे विद्युत की आपूर्ति कृषि कार्य हेतु की जा रही है । साथ ही, सरकार की सात निश्चय योजना के तहत कृषि विद्युत संबंध हेतु कैम्प लगाया जा रहा है । मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना फेज-2 की निविदा प्रक्रियाधीन है । एजेंसी चयन के पश्चात् आगे योजना के आकार के अनुरूप कार्य प्रारंभ किया जायेगा । इसे पूर्ण करने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026-27 है ।

श्री छोटे लाल राय : महोदय, यह मामला कृषि से संबंधित है और सरकार कह रही है कि हम कृषि पर बहुत ध्यान दे रहे हैं तो हमारी मांग है कि किसानों के लिए जो बचे हुए ट्रांसफॉर्मर और पोल हैं वह कब लगेंगे ? मेन मामला वह है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : एप्लीकेशन दिलवायें, कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : आवेदन दिलवा दीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-780 (श्री अजय कुमार, क्षेत्र संख्या-138, विभूतिपुर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर): आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार के पत्रांक-D.O. No. Z28016/1/2022-NHM-III/part-1 से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम, नियंत्रण एवं संक्रमण की जांच के लिए लैब तकनीशियनों (RTPCR LAB सहित) की सेवा को दिनांक-31 मार्च, 2024 तक विस्तारित कर दिया गया है । कोरोना वायरस (COVID-19) की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जरूरत के अनुसार वास्तविक मानव बल का आकलन कर अपने स्तर से लैब तकनीशियन की सेवा लेने के लिए संबंधित जिला/मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को निदेशित किया गया है । राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में किसी भी पद के विरुद्ध समायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

अध्यक्ष: उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री अजय कुमार : महोदय, कोरोना काल में लैब टैक्नीशियन जीवन को हाथ में लेकर के भयानक संक्रामक रोग में उन्होंने जांच की प्रक्रिया को पूरा किया था और मैंने सरकार से मांग किया था कि इसको आप समायोजित करें । सरकार ने जवाब दिया है कि मार्च, 2024 तक तो मेरा कहना है कि नौजवानों ने अपनी जिंदगी को हाथ में लेकर के इतनी गंभीर बीमारी का सामना करते हुए उसने कोविड के काल में काम किया है । सरकार से जवाब दिया गया है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल को

निर्देशित किया है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार निर्देशित किया है या कोई ठोस आश्वासन तो दे यह तो बताये कि यह कब तक हो सकता है ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने जवाब दिया है कि 31 मार्च, 2024 तक इसको विस्तारित कर दिया गया है और आगे के स्तर पर मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल में यदि जरूरत है तो इसको विस्तारित भी किया जायेगा ।

श्री अजय कुमार : महोदय,...

अध्यक्ष : ठीक है । हो गया, आपकी बात मान ली सरकार ।

श्री अजय कुमार : महोदय, 31 मार्च, 2024 तक क्या मतलब है...

अध्यक्ष : उसके बाद भी आवश्यकता होगी तो सरकार विचार करेगी, कह रही है सरकार । बैठिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या–781 (श्री मुकेश कुमार यादव, क्षेत्र संख्या–27, बाजपट्टी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–782 (श्री जय प्रकाश यादव, क्षेत्र संख्या–46, नरपतगंज)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर): वस्तुस्थिति यह है कि राज्य की सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में चहारदीवारी का निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से कराया जाना है । इसी क्रम में नरपतगंज प्रखंड की गोखलापुर पंचायत स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की चहारदीवारी का निर्माण कार्य भी विहित प्रक्रियानुसार कराया जायेगा ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । चरणबद्ध तरीके से चहारदीवारी बनाने का लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह घनी आबादी के बीच में है...

अध्यक्ष : देखिये बार–बार आप लोग अनुरोध करते हैं, जवाब देना सरकार की बाध्यता नहीं होगी । अगर पूरक पूछियेगा तो सरकार आपका जवाब दे सकती है । मैं आपकी मदद कर रहा हूं आप मदद लेना नहीं चाहते । मैं क्या करूं बताइये ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, वह घनी आबादी में बसा हुआ है और पूरा चारागाह बना हुआ है इसीलिए...

अध्यक्ष : पूछिये, क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री जय प्रकाश यादव : पूछना चाहते हैं कि समय–सीमा बता दें, जल्दी में उसको करवा दें ।

अध्यक्ष : ठीक है बैठिये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता को देखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में इसको करवाने का कार्य किया जायेगा ।

श्री जय प्रकाश यादव : ठीक है धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-783 (श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र संख्या-9, सिकटा)

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता:जी पूछता हूँ।

अध्यक्ष: उत्तर नहीं देखा है?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता: जी नहीं देखा है।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री,संसदीय कार्य विभाग उत्तर पढ़ दीजिये।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि संसदीय कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर मुख्य सचिव के स्तर से माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये पत्रों पर तत्परतापूर्वक समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश निर्गत है ।

2- संसदीय कार्य विभाग के पत्रांक संख्या-188, दिनांक 22.02.2024 द्वारा जल संसाधन विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग को उपरोक्त निर्देश के अनुपालन किये जाने हेतु निर्देश दिया गया है ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, अब तक हमने जो भी पत्र दिये किसी काम के लिए चाहे वह ग्रामीण कार्य विभाग हो, चाहे जल संसाधन विभाग हो या माननीय मंत्री जी का ग्रामीण विकास विभाग हो...

अध्यक्ष : संक्षिप्त में करिये । पूरक पूछिये, समय समाप्त हो रहा है ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, हम यही कहना चाहते हैं कि किसी का जवाब नहीं मिला है और न वह काम हुआ है तो संसदीय व्यवस्था में माननीय विधायकों का...

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि सरकार ने निर्देशित किया है और सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है कि ससमय जवाब मिले ।

टर्न-7/ मुकुल/23.02.2024

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पहले से कोई नियमन नहीं था, पहले से कोई निर्देशन जारी नहीं होता था । महोदय, हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि कोई काम है तो वह क्यों नहीं होता है या वह क्यों नहीं होगा इसका जवाब क्यों नहीं मिलता है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने जवाब में स्पष्ट रूप से दिया है और माननीय सदस्य से संबंधित जो पत्र दिया गया था, उस संदर्भ में पत्र को स्मारित किया है

उस सिलसिले में सरकार की तरफ से पुनः सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस संदर्भ शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करे ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, यह प्रश्न पिछली बार भी उठा था लेकिन किसी ने....

अध्यक्ष : जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं । अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 22 फरवरी, 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

श्री महबूब आलम, श्री अजय कुमार, श्री गोपाल रविदास, श्री रामबली सिंह यादव, श्री महा नंद सिंह, श्री सत्यदेव राम एवं श्री संदीप सौरभ और दूसरा श्री अजीत शर्मा । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद, मतदान एवं सरकार के उत्तर तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी का उपस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-172(3) एवं नियम-47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, इसे पढ़ने की इजाजत दी जाय ।

अध्यक्ष : महबूब साहब, आप क्या कह रहे हैं ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, हम यह कह रहे हैं कि इसे पढ़ने की इजाजत दी जाय ।

अध्यक्ष : महबूब जी, आप इतना लंबा-लंबा कार्य-स्थगन प्रस्ताव दे देते हैं तो हम कैसे पढ़ने की इजाजत दें आपको, छोटा-छोटा कार्य-स्थगन प्रस्ताव देंगे तो ही हम आपको पढ़ने की इजाजत देंगे ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, इसे पढ़ने की इजाजत दी जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । महबूब साहब, पढ़िए ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, पटना जिले के खाजेकलां थाना, मौजा-रानीपुर, थाना संख्या-19, खाता संख्या-627, सर्वे प्लॉट-1998, वार्ड संख्या-25, 29 एवं 46 में तीन सरकारी विद्यालयों के भवन निर्मित हैं, ये विद्यालय हैं- 1.प्राथमिक विद्यालय, उदरहमानपुर जोकि कन्या विद्यालय है । 2.मध्य विद्यालय, चौघड़ा और 3. मध्य विद्यालय कसबा करीमाबाद । पहला विद्यालय छात्राओं का है और बाकी दो विद्यालय में अधिकांश दलित-अतिपिछड़े समुदाय के छात्र पढ़ते हैं, पहला विद्यालय नगर निगम की जमीन पर है बाकी दो गैरमजरूआ जमीन पर । उक्त तीनों विद्यालय में एक 135 साल तो अन्य दो विद्यालय लगभग 100 साल पुराने हैं । वर्ष 2008 में ही सभी स्कूलों के भवन भी बन चुके हैं । भूमाफिया और शिक्षा विभाग के कुछेक अधिकारियों की मिलीभगत से इन तीनों स्कूलों का भवन तोड़कर जमींदोज करने का आदेश जारी कर दिया गया है और इन तीनों स्कूलों को अन्य स्कूलों के साथ टैग कर दिया गया है । हालत यह है कि मध्य विद्यालय चौघड़ा व मध्य विद्यालय कसबा करीमाबाद के स्कूलों के पास अभी 10-10 कमरे हैं, इन

दोनों विद्यालयों को 4-4 कमरों के स्कूलों के साथ टैग किया जा रहा है । इस पूरे प्रकरण की जानकारी पटना जिलाधिकारी को भी है, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी दिया है । यह शिक्षा विभाग में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा करता है । बच्चों से उनका स्कूल ही छीन लेने की कोशिश हो रही है ।

अतः अत्यंत लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन का कार्य स्थगित कर बहस की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइये । माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहा जायेगा कि वे इस विषय को देख लें और उसका समाधान निकालने की कोशिश करें । माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा जी ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी बात पूरी हो गई । माननीय शिक्षा मंत्री जी इस पूरी बात को समझकर उसका निदान क्या हो सकता है उसकी कोशिश करेंगे । माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा जी ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, राज्य में बेतहाशा बढ़ चुके अपराध पर नियंत्रण के उपायों पर चर्चा हो ।

उल्लेखनीय है कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो गये हैं । उनमें शासन के खौफ नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । दिन-दहाड़े लूट, डकैती, सामूहिक बलात्कार आदि आम हो चुके हैं । लोग त्रस्त और भयभीत हैं । राज्य के नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जिससे बेचैनी का माहौल है ।

अतः आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में बेतहाशा बढ़ चुके अपराध पर नियंत्रण के उपायों पर चर्चा हो ।

शून्यकाल की सूचनाएं

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अंजार नईमी ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखण्डाधीन नटूवापाड़ा पंचायत में पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क से भोरादेह एम0एम0जी0एस0वाई0 सड़क के बीच मुखिया रफीक के घर के पास मरियाधार में पुलिया निर्माण नहीं होने से लगभग 20 हजार लोगों की आवाजाही प्रभावित है ।

मैं लोक-हित में सरकार से पुलिया निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर क्षेत्रान्तर्गत चुने गये जनप्रतिनिधियों, यथा पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य एवं मुखिया को वर्ष 2016 से 2021 तक केवल 22 महीने का ही मानदेय का भुगतान हुआ है, शेष 44 महीने का मानदेय लम्बित है ।

मैं सरकार से लम्बित मानदेय का भुगतान शीघ्र कराने की मांग करता हूं ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, पी0एम0सी0एच0 में संविदा नियम के विरुद्ध अधीक्षक पद पर सेवानिवृत्त डॉ0 आई0एस0 ठाकुर को बहाल कर दिया गया है । डॉ0 ठाकुर के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है । अधीक्षक पद पर रहते जांच प्रभावित हो सकता है । तत्काल डॉ0 ठाकुर को अधीक्षक पद से हटाने की मांग करता हूं ।

श्री उमाकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिला के नरकटियागंज डिवीजन के कार्यपालक मुकेश कुमार एवं सहायक अभियंता रोहित कुमार ग्रामीण कार्य विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों के लापरवाही से बेतिया-योगापट्टी रोड से परसा सड़क 4 वर्ष में नहीं बना । इन दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत प्लस-2 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पघारी में वाणिज्य विषय की पढ़ाई नहीं होने से इस क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः मैं सरकार से उक्त विद्यालय में वाणिज्य विषय की पढ़ाई शुरू कराने की मांग करता हूं ।

डॉ0 मुरारी मोहन झा : महोदय, मार्च 2024 में संभावित बी0पी0एस0सी0 टी0आर0ई0 3.0 की परीक्षा में एस0टी0ई0टी0 2024 में अपीयर होने वाले छात्रों को शामिल करने की सदन से मांग करता हूं ऐसा नहीं होने से 3.5 लाख विद्यार्थी रोजगार के अवसर पाने से वंचित रह जायेंगे ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, ग्राम कचहरी सचिवों का वेतन 35,000/- प्रतिमाह एवं संविदा पर बहाल विद्युत मानव बलों को स्थायी करते हुए 30,000/- प्रति माह वेतन देने एवं सेवानिवृत्त चौकीदार, दफादारों के परिवारजनों की बहाली उनके पदों पर करने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : महोदय, कटोरिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बौंसी प्रखंड के कुशयारी धर्मपुर गांव के बीच कुशयारी गांव के पास नदी में पुल निर्माण होने से दो संपर्क पथ जुड़ने के साथ-साथ बौंसी, कटोरिया एवं चांदन प्रखंड आपस में जुड़ेगा ।

अतः सरकार से उक्त नदी पर पुल निर्माण की मांग करती हूं ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, बिहार राज्य में वर्ष 2023 में स्थगित सिपाही भर्ती परीक्षा को जल्द से जल्द कराने की मांग करती हूं ।

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, गया जिला अंतर्गत जी0टी0 रोड–02–बाराचट्टी से मोहनपुर पथ में डंगरा क्वार्टर से डंगरा बाजार, चुआंवार, धरहरा होते हेमजापुर बाजार तक की सड़क वर्षों से जर्जर अवस्था में है । लोग बड़ी ही कठिनाई में आवागमन करते हैं।

अतएव अति महत्वपूर्ण लोकहित में उक्त सड़क का निर्माण हेतु सदन से मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : राम सिंह जी, एक मिनट आप रुक जाइये । आप मेरी पूरी बात को सुन लीजिए । आपका जो शून्यकाल है वह 75 शब्द का है, 50 शब्द की बाध्यता है इसलिए आपके शून्यकाल को अमान्य किया गया है । लेकिन आप एक बार इसको पढ़ दीजिए । लेकिन आगे से ऐसा कीजिएगा तो हम पढ़ने नहीं देंगे ।

श्री राम सिंह : महोदय, ठीक है । अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत दो नहर पर पहले से ही आर0डी0–142 से आर0डी0–0 तक सड़क बनी हुई है जो अत्यंत ही जर्जर स्थिति में है । यह सड़क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को जोड़ता है तथा वाल्मीकिनगर पर्यटन स्थल को भी जोड़ता है, इस जर्जर सड़क के बनने से आम जनता एवं पर्यटकों को आवागमन में सुविधा होगी ।

अतः आर0डी0–142 से आर0डी0–0 तक सड़क बनवाने हतु मैं सरकार से मांग करता हूं । धन्यवाद महोदय ।

टर्न–8/यानपति/23.02.2024

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत खुशनगरी होकर बहने वाली रंगधीया नदी एवं परिहार प्रखंड भांसर गांव होकर बहने वाली मरहा नदी पर पुल नहीं होने से जनता को कठिनाई होती है ।

अतः खुशनगरी एवं भांसर गांव होकर बहनेवाली नदी पर पुल बनाने की मांग करती हूं ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत प्रस्तावित पटना से बेतिया फोरलेन सड़क में सेवराहां चौक से हरसिद्धि प्रखंड कार्यालय गेट होते हुए नेपाल को जोड़नेवाली एन0एच0–28 ए के छपवा चौक तक सड़क चौड़ीकरण जनहित में कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती कविता देवी : महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत फलका प्रखंड के मोरसण्डा पंचायत में स्थित बरंडी नदी कमला घाट पर पुल नहीं रहने के कारण नदी के दोनों ओर आनेजाने में कठिनाई होती है ।

अतएव जनहित में शीघ्र पुल का निर्माण कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं ।

श्रीमती निशा सिंह : महोदय, बिहार में विद्युत कंपनी में निजी एजेंसी द्वारा नियुक्त मानव बलों के सरकार के अनुबंध पर नियुक्त किया जाय जिससे उनका सही ढंग से जीवन यापन एवं जीवन सुरक्षित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह : महोदय, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा-2 प्रखंड के हरनाटांड़ पंचायत के हरनाटांड़-खजूरिया पथ पर बाढ़ से सड़क सह दो पुल 10 वर्षों से क्षतिग्रस्त होने के कारण बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ आमजनों के आवागमन में कठिनाई होती है ।

अत: सड़क सह दोनों पुलों के निर्माण की सूचना देता हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के उदगाड़ा पंचायत वार्ड नंबर-4 स्थित जबरा पोखर से पांच पीर जानेवाली सड़क काफी जर्जर स्थिति में है। जिससे आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अत: मैं उक्त सड़क को अतिशीघ्र बनाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदान पेंशन योजना 2005 दिनांक 01.09.2005 से लागू है जबकि अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान एवं बंगाल में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया है।

अत: कर्मचारियों के भविष्य कल्याण हेतु ओ0पी0एस0 लागू करने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखण्ड के भवानन्दपुर पंचायत के पबडाढ़ाव स्थित बूढ़ी गंडक नदी पर पुल निर्माण कराने हेतु, मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री अनिल कुमार : महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत मेजरगंज प्रखंड के खैरवा से चैनपुर जानेवाली अत्यंत जर्जर सड़क का निर्माण जनहित में करावें ।

श्री सुनील मणि तिवारी : महोदय, राज्य के सभी टोला सेवक 15 वर्षों से अपने कार्यों का निर्वहन करते रहे हैं । सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलाने में इनकी अहम भूमिका है ।

अत: सभी टोला सेवकों के कार्यकाल को देखते हुए प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजन कर विशेष प्रशिक्षण देने की मांग करता हूं ।

श्री महबूब आलम : महोदय, 2013 के उर्दू बांग्ला टी0ई0टी0 परीक्षा के रिजल्ट में 26000 उम्मीदवार पास हुए । फिर तकनीकी खराबी का हवाला देकर 12000 परीक्षार्थियों को फेल कर दिया गया । मुख्यमंत्रीजी के हस्तक्षेप पर लीगल सलाहोपरान्त शिक्षा विभाग ने 5 प्रतिशत मार्क्स कम कर रिजल्ट देने का फैसला लिया । अविलंब रिजल्ट जारी करे सरकार ।

श्री राम रतन सिंह : महोदय, तेघड़ा विधान सभा क्षेत्र के बरौनी प्रखंड अंतर्गत जीरोमाइल एन0एच0-28 से बीहट हॉल्ट स्टेशन जानेवाली सड़क जर्जर अवस्था में है ।

अत: मैं जनहित में उपरोक्त वर्णित सड़क की मरम्मती कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : महोदय, बिहार प्रदेश में पुलिस द्वारा जब्त की हुई गाड़ी जैसे भारी वाहन गैस की टैंकर को वर्षों से वैशाली जिले के महुआ थाना के सड़क किनारे खड़ी पड़ी हुई है जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है ।

भारी वाहनों को वहां से हटाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री ललन कुमार : महोदय, संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं । सरकारी, निजी, संविदा अथवा ऑनलाईन काम के दरम्यान मृत्यु होने पर एक समावेशी और मानवता के तहत भेदभाव को समाप्त करते हुए मैं सरकार से समान मुआवजा का प्रावधान करने की मांग करता हूं ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : महोदय, जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है वैसे उपभोक्ताओं के बिल का एकमुश्त निपटारे के लिए कुल बकाया राशि में से ब्याज की राशि माफ कर बकाया बिल का निपटारा करने की छूट देने की मांग मैं सरकार से करती हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के पथराहा पंचायत में इंडो नेपाल रोड से बांध पर काली मंदिर होते उत्क्रमित उच्च विद्यालय महेशपट्टी तक पक्की सड़क निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत छतियौना में वार्ड नं0-9 ग्राम रेही में जहीर के घर से महादलित टोला वार्ड नं0-11 होते हुए एन0एच0 327 ई पर पूजा पम्ब छतिऔना तक 1.5 किलोमीटर कच्ची सड़क का पक्कीकरण करने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, छठे चरण में बहाल प्राथमिक शिक्षकों की बी0एड0 डिग्री को पटना उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य करने से 22000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है ।

सरकार से इनकी नौकरी बचाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में अपील करने अथवा अध्यादेश लाकर इन्हें 6 से 8 में प्रमोट करने की मांग करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, राज्य भर में बंद बाजार समितियों को फिर से चालू कराने, वर्षा पर आधारित जहानाबाद, नालंदा, नवादा तथा गया जिला में सिंचाई का मुकम्मल व्यवस्था करने तक किसानों को मुफ्त बिजली देने तथा कर्जा माफ करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका जी की सूचना पढ़ी गई है, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री विजय कुमार खेमका, श्री विनय बिहारी एवं श्री नीतीश मिश्रा से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन0डी0एम0ए0), भारत सरकार द्वारा डिजास्टर रिस्क रेडक्शन के अंतर्गत स्वयं सेवा संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से मई 2016 से देश के 25 राज्यों के 30 अति बाढ़ प्रवण जिलों में 200 स्वयंसेवक प्रति जिला के आधार पर कुल 6000 आपदा मित्र (कम्युनिटी वोलंटियर्स) के प्रशिक्षण से संबंधित योजना को प्रारंभ किया गया ।

(क्रमशः)

टर्न-9/अंजली/23.02.2024

श्री प्रेम कुमार, मंत्री (क्रमशः) : इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम बिहार राज्य के दो जिलों यथा-सीतामढ़ी और सुपौल को शामिल किया गया था । इस योजना की समाप्ति दिनांक-31.12.2020 को हो गयी ।

योजना की सफलता को देखते हुए देश के अतिरिक्त 350 जिलों में कुल एक लाख आपदा मित्र को ट्रेनिंग किये जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया । इन 350 जिलों में बिहार के 24 जिलों को शामिल किया गया है, यथा- अररिया, बांका, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सिवान, वैशाली एवं पश्चिम चम्पारण । पूर्व में इस योजना की अवधि दिनांक-06.08.2021 से मार्च, 2023 तक निर्धारित थी, जिसे दिनांक-31.03.2024 तक विस्तारित किया गया है । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य में कुल 9600 आपदा मित्रों के ट्रेनिंग का लक्ष्य दिया गया है । आपदा मित्रों का ट्रेनिंग बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है ।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है जिसमें विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु स्वयंसेवा संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों को जागरूक करने हेतु आपदा मित्रों को ट्रेनिंग किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत आपदा मित्रों के लिए निश्चित मानदेय तय करने अथवा इनकी स्थायी नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है । आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर पर भी आपदा मित्रों को निश्चित मानदेय निर्धारण अथवा स्थायी नियुक्ति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने इतना विस्तार से उत्तर दिया है ।

श्री विजय कुमार खेमका : ठीक है, माननीय मंत्री जी का उत्तर विस्तार से आया है और भारत सरकार की योजना है और ये सब रिलीफ फोर्स हैं जो कि विभिन्न परिस्थितियों में समाज में सेवा करने का काम करते हैं और इनको 12 दिन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है । उसकी भी जो इनकी राशि है एक तो मैं अपने पूरक में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो उनकी बकाया राशि है वह कब तक उनको भुगतान हो जाएगा ? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इनकी राशि, इनकी जो सेवा है, जो-जो सेवा है तो इनकी दैनिक मजदूरी है या मंथली मजदूरी है इस तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं है । 400 से 1200 रुपया तक का इनका निर्धारण किया गया है तो हम मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि एक तो इनका स्पष्टीकरण हो जाय और दूसरा क्या 400 की जगह 1200 रुपया इनका जो राशि देने का है वह भुगतान करने का विचार विभाग रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, पूरे मामले की समीक्षा कराकर निश्चित तौर पर जो प्रावधान होगा, किया जाएगा ।

अध्यक्ष : हो गया ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ आग्रह निवेदन के साथ एक चीज जो हम पूरक के रूप में पूछना चाहेंगे...

अध्यक्ष : आपका तीसरा पूरक है ।

श्री विजय कुमार खेमका : कि जो इनका बकाया...

अध्यक्ष : एक बार में दो पूछ लिये थे आप ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, अंतिम है । इनकी जो बकाया राशि है चाहे वह ट्रेनिंग की हो, चाहे जो ये काम किए हों पूरे बिहार में तो उनका कब तक भुगतान हो जाएगा ?

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक सप्ताह के अंदर सारी बातों की समीक्षा करके समाधान किया जाएगा, बकाया होगा, प्रावधान होगा । निश्चित बकाया भुगतान कराया जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हो गया, अगर नहीं, यदि । अगर-मगर में सरकार का जवाब नहीं होता है । माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह ।

(व्यवधान)

हो गया, आज समय कम है न, शुक्रवार है । बाकी लोगों को मौका दीजिए । माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह ।

श्री अजय कुमार सिंह,श्री विजय शंकर दूबे एवं अन्य पांच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार(ऊर्जा विभाग)की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्षः सूचना पढ़ी हुई है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री आलोक रंजन, अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री आलोक रंजन, श्री कुमार शैलेन्द्र एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री आलोक रंजन : अध्यक्ष महोदय, ''स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के द्वारा सदर अस्पताल एवं इसके नीचे के स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों के रोगी कल्याण समिति का संशोधित

दिशा-निर्देश 2024 का प्रकाशन किया गया है । उक्त शासी निकाय में स्थानीय विधायक को सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि स्थानीय विधायक को इस समिति का अध्यक्ष होना चाहिए । स्थानीय विधायक के प्रति लोगों की अपेक्षा अधिक रहती है । चूंकि विधायक जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है । इस शासी निकाय में नगर निगम/नगर परिषद् एवं जिला परिषद् के पार्षदों को रखा गया है । रोगी कल्याण समिति में विधायक के रहने से स्थानीय कमियां एवं निगरानी भी सही ढंग से हो सकेगी । साथ ही सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन भी शत-प्रतिशत हो सकेगा ।

अतएव लोकहित में रोगी कल्याण समिति के शासी निकाय में संशोधन करते हुए स्थानीय विधायक को उचित प्रतिनिधित्व देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद, अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री सुदामा प्रसाद, श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ''भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से सटे जीरो पथ निर्माण माईल तीन मुहान से आगे केन्द्रीय विद्यालय के पास आरा-सासाराम स्टेट हाईवे लगभग आधा किलोमीटर जर्जर होकर गड्ढे में तब्दील हो गई है । गड्ढे में नालियों का गन्दा पानी भरे रहने के कारण नारकीय स्थिति बन गई है । प्रतिदिन यहाँ दुर्घटनाएँ होती रहती हैं और घंटों महाजाम लगता है, जिसमें स्कूली बस, यात्री बस, एम्बुलेंस एवं पैदल यात्रियों के फँसने से परेशानी हो रही है । हर रोज इस रास्ते से लगभग 10,000 छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं । आरा बस स्टैण्ड से झारखण्ड राज्य के राँची, टाटा, बोकारो, धनबाद व बिहार के अरवल, औरंगाबाद, गया, रोहतास (सासाराम, डिहरी) जिलों के साथ ही पढ़ाई, व्यवसाय, कृषि एवं प्रशासनिक कार्य के लिए भोजपुर के सहार, संदेश, अगिआंव, उदवंतनगर, गड़हनी, चरपोखरी, पीरो, तरारी, जगदीशपुर प्रखंडों के सभी चट्टी बाजारों के लिए वाहन आते-जाते रहते हैं ।

अत: उक्त अति महत्वपूर्ण जर्जर सड़क एवं सड़क के दोनों ओर नालों का निर्माण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आरा-सासाराम एस.एच.-12 पथिक महत्वपूर्ण पथ है जिसकी कुल लंबाई 97 किलोमीटर है जिसमें 0 से 46 किलोमीटर शाहाबाद पथ प्रमंडल आरा के अधीन है । जिसका संधारण ओ0पी0आर0एम0एस0 पैकेज नंबर-34 (B) के अंतर्गत किया जा रहा है । विषयांकित पथांश के दोनों तरफ व्यावसायिक, प्रतिष्ठान, आवासीय कॉलोनी आदि अवस्थित होने तथा पूर्व से निर्मित नाला का आउटलेट नहीं होने के कारण पथ परत से जल निकासी में समस्या होती है । परंतु ओ0पी0आर0एम0एस0 के तहत पथ क्रस्ट पर अस्थायी जल जमाव की निकासी टैंकर एवं पंप के द्वारा की जाती है एवं साथ ही जल जमाव की वजह से उत्पन्न पथ पाट्र्स की मरम्मती की जाती है । पथ पर होने वाले जलजमाव के स्थायी समाधान हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, शीघ्र ही पथ का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा ।

अध्यक्ष : अब हो गया ।

श्री सुदामा प्रसाद : धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : अभी दो मिनट है । शून्यकाल । श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता । चाहे तो आप उपयोग कर लीजिए ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण का क्या हुआ ?

अध्यक्ष : अब आगे बढ़ गए । अगली तिथि को ।

शेष शून्यकाल की सूचनाएं

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, प0 चंपारण जिला अंतर्गत त्रिवेणी नहर पर मैनाटाढ़ प्रखंड के पदमौल, दिउलिया स्थित जर्जर पुलों की रेलिंग तथा रामपुर पुल एप्रोच पथ ध्वस्त हो चुका है । जिससे आये दिन दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं ।

सरकार से उपर्युक्त जर्जर पुलों की रेलिंग एवं एप्रोच पथ यथा शीघ्र मरम्मती की मांग करता हूं ।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड रामनगर एवं गौनाहा में बिजली विभाग द्वारा गलत बिल के कारण अवैध वसूली का शिकार उपभोक्ता हो रहे हैं ।

मैं सरकार से मांग करती हूं कि सुधार किया जाय ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत भैयापट्टी में बछराजा नदी पर लघु जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित स्लूईस गेट पानी के

दबाव के कारण तीन वर्ष पूर्व ध्वस्त हो चुका है । फसल की सिंचाई बाधित है । वहां शीघ्र नया स्लूईस गेट निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री सुर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के बखरी नावकोठी गढ़पुरा डंडारी प्रखंड के सभी पंचायतों में बिजली की जर्जर तार वर्षों वर्ष से नहीं बदला गया जिससे आये दिन बराबर तार टूटने की घटना होती है ।

अतः पुराने बिजली की तार बदल कर नई तार लगाने की सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : शेष शून्यकाल की सूचनाएं शून्यकाल समिति को विचारार्थ सुपुर्द की जाती है ।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/आजाद/23.02.2024

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य लिये जायेंगे । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

वित्तीय कार्य

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या-02, अधिनियम-2023, बिहार विनियोग संख्या-03, अधिनियम-2023 एवं बिहार विनियोग संख्या-04, अधिनियम-2023 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2023-24 में खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं तृतीय व्यय विवरणी उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, ऊर्जा विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	-	59 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	58 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी॰पी॰आई॰ (एम॰एल॰)	-	08 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	03 मिनट
सी॰पी॰आई॰(एम॰)	-	02 मिनट
सी॰पी॰आई॰	-	02 मिनट
ए॰आई॰एम॰आई॰एम॰	-	01 मिनट
कुल	-	180 मिनट

माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''ऊर्जा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 11422,67,80,000/- (ग्यारह हजार चार सौ बाईस करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ये सभी व्यापक हैं । जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार का प्रस्ताव प्रथम है ।

अतः माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अनुपस्थित हैं, इसलिए मैं दूसरे प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन का नाम पुकारता हूँ ।

माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटाई जाए ।''

महोदय, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुन्ना यादव जी मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव अपना पक्ष रखें । आपका समय 22 मिनट है । आराम से बोलना है ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : बहुत-बहुत धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं आपका और अपने दल के मुख्य सचेतक श्री शाहीन जी का और अपने नेता तेजस्वी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सदन में मुझे बोलने का मौका दिया ।

अध्यक्ष महोदय, यह तो पता भी नहीं चलता जो अभी बजट पेश हुआ है, यह तो हम ही लोगों का तैयार किया हुआ बजट है और उसी बजट के खिलाफ में कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलना पड़ रहा है । सच्चाई तो यही है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के समय का बजट है और वे लोग अपना बजट बना दिये और उसी पर अभी हमलोगों को बोलना पड़ रहा है ।

महोदय, जो परम्परा रही है, संवैधानिक परम्परा है, उसमें तो हम आपका विरोध करेंगे ही । चूँकि आपसे हमारा मेल होने वाला नहीं है । अध्यक्ष

महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण विभाग है- ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, गृह विभाग ऐसे करके 12 विभाग है, जिसपर आज कटौती प्रस्ताव है । श्रवण बाबू का क्या है, हमेशा हमको इन्हीं विभाग पर बोलना पड़ जाता है । 8-9 साल से हमको आपके विभाग का पाला पड़ रहा है । लेकिन सदन में कोई बात अगर हमने रख दिया और एक बार हमको आपने कहा भी कि हम इसको आगे ध्यान देंगे, इसको प्रोसिडिंग्स में लायेंगे लेकिन आज तक नहीं हो पाया है ।

अध्यक्ष : पूरा ध्यान देते हैं ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : जी नहीं, हम इनको बता रहे हैं । ग्रामीण विकास विभाग राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह आदि तमाम महापुरूषों ने कहा था कि भारत गांवों का देश है और अब इनको भारत रत्न भी मिल गया है, आपको धन्यवाद । अब कर्पूरी जी को भी भारत रत्न दे दिये हैं, इसको लिए भी आपको धन्यवाद, लेकिन जिन्दगी भर तो आपलोग गाली दिये हैं ।

देश के तमाम महापुरूषों ने कहा कि भारत गांवों का देश है, 70 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है और ग्रामीण विकास विभाग गांवों से जुड़ा हुआ है। हम कई बार कहे जैसे इसमें ग्रामीण विकास विभाग जुड़ा हुआ है । ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा है । जिस समय यू0पी0ए0-1 की सरकार थी और हमलोगों ने .....

अध्यक्ष : आप पहले ऊर्जा से शुरू कीजिए, तब वहां आईयेगा ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय, हम मनरेगा का ही बता रहे हैं, मनरेगा उन्हीं के विभाग का है ।

अध्यक्ष : ऊर्जा से शुरू कीजिए, ऊजा पर दो लाईन ही बोलिए ।

श्री राजीव कमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय, हम ग्रामीण विकास विभाग से ही शुरू करेंगे, श्रवण बाबू से बराबर हमारी भेंट होते रहती है । मनरेगा यू0पी0ए0-1 में जब रघुवंश बाबू सांसद थे, उन्होंने मनरेगा लाया, जिसमें रोजगार गारंटी के तहत 100 दिनों का मजदूरी का प्रावधान रखा और हमको लगता है कि पूरे देश में मनरेगा काफी सफल रहा । मजदूरों का काम हुआ, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई देश में । महोदय, मैंने एक बार प्रस्ताव इनको दिया था कि जिस तरह से रोजगार गारंटी में आप सड़कें या और चीजें जो बनवाते हैं, मजदूर गारंटी का भी आपको प्रस्ताव भेजना चाहिए कि भारत सरकार मजदूर गारंटी लावे और उस मजदूर गारंटी के तहत मजदूर किसानों के खेत में काम करे और किसान अपने देख-रेख में अपना काम करवावे और उसका पैसा जो है, सरकार मुहैय्या

करवावे, तभी हमारा देश, हमारा समाज आगे विकास कर सकेगा । आपने भी कहा था कि मैं इस प्रस्ताव को भेजूंगा लेकिन आज तक उसपर अमल नहीं हुआ । आज यह स्थिति है गांवों में कि हर किसान आज रोता है खेत में काम करने से, फसल उगाने पर रोता है और कहता है कि फसल तो उगा देते हैं लेकिन न तो फसल काटने वाला मिलता है और न उसको पहुँचाने वाला मिलता है । समस्या आज हर किसानों के पास उत्पन्न हो गई है । अध्यक्ष महोदय, हम तो चाहेंगे श्रवण बाबू से कि अब तो डबल ईंजन की सरकार है, फिर आ गये, एक साल हमारे साथ रहते हैं सिंगल ईंजन में और फिर डबल ईंजन जोड़ लेते हैं । हम तो इनसे चाहेंगे कि प्रस्ताव भेजा जाय, इस देश की समस्या का समाधान हो जायेगा और मजदूर गारंटी योजना अगर लागू करवाया जायेगा तो ।

महोदय, अभी जीविका दीदी का भी है । एक करोड़ 30 लाख से ऊपर जीविका सहायता समूह से महिलायें जुड़ गई है और मैं देख रहा हूँ कि जब से जीविका में महिलायें जुड़ी हैं, जीविका दीदियां काम करने लगी है और स्वालंबी भी हुई है । लेकिन उसको जो पैसा मुहैय्या कराया जाता है, उसमें इन्ट्रेस्ट लिया जाता है, उनको जीरो इन्ट्रेस्ट पर पैसा मुहैय्या कराया जाय । इनका जो मानदेय है, उसको बढ़ाया जाय । अब सात निश्चय योजना, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, अभी सभी साथी ने कई जगह बात भी किया कि सात निश्चय योजना की जॉच करायी जाय, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सात निश्चय में हुआ है । कहीं भी आप पता लगा लीजिए, किसी पंचायत में जाकर, कहीं पर इसका रख-रखाव सही से नहीं हो रहा है । अगर मोटर जल गया तो पॉच दिनों तक पानी नहीं चलता है, महीनों दिनों तक नहीं चलता है । एक भी पानी टंकी आज चार साल, पॉच साल से कहीं भी पानी टंकी साफ नहीं हुआ । हमारे यहां मुजफ्फरपुर में दो दिन पहले बच्चियां पानी टंकी का पानी पी है और दर्जन बच्चियां बीमार होकर मेडिकल कॉलेज में पड़ी हुई है । यह स्थिति बनी हुई है सात निश्चय योजना का अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी कहते हैं कि यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है सात निश्चय-1, सात निश्चय-2, गली-नली, ये तमाम चीजों में केवल लूट-खसोट किया जा रहा है और कुछ नहीं है ।

..... क्रमशः .....

टर्न-11/शंभु/23.02.24

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : क्रमशः जल जीवन हरियाली में अभी हमको मिला है तो देखे हैं 11205 कुआं अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है । उसके बाद 15 करोड़ पौधा लगाया गया है, 50 हजार से अधिक नये जल स्रोत सृजित किये गये हैं । अध्यक्ष महोदय, इसकी जॉच करवा दीजिए हमारे यहां भी एक पोखरा का उड़ाही हुआ और मैं समझ रहा हूँ कि उसमें आधा काम भी नहीं हुआ, जे0सी0बी0 लगाकर खद्धा खनकर सारा पैसा उठा लिया और आज तक उसका कोई जॉच नहीं हुआ । हमने एक बार इसकी बात जिला में भी रखा था, शंकरपट्टी में हमारे यहां पोखरा का उड़ाही हुआ तो हम लोग तो देख रहे हैं कि हर जगह लूट रहा है, सरकारी पैसा का बंदरबांट हो रहा है कोई देखनेवाला नहीं है । अब जहां ब्यूरोक्रेट हॉवी हो जायेगा वहां कौन सुनेगा । अब हमलोगों के सदन के नेता हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक कहावत हम कहना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोग कहा है कि काहे ले बोलियेगा । दो लाइन अगर हम कह दें- विश्वास बनकर लोग जिंदगी में आते हैं, विश्वास बनकर लोग जिंदगी में आते हैं ख्वाब बनकर आंखों में समा जाते हैं, पहले यकीन दिलाते हैं कि वे हमारे हैं फिर न जाने क्यों बदल जाते हैं ।

अध्यक्ष : आपके कहने पर मुझे भी दो लाइन याद आ रहा है इकबाल का शेर है बाकी पूरा छोड़िये उसमें आपका समय बर्बाद होगा- धूल चेहरे पर थी, वे रात भर आइना साफ करते रहे । बोलिये, बोला जाय, अपनी बात जारी रखिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : मतलब धूल उनके चेहरे पर था ।

अध्यक्ष : आप बोलते रहिये न ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी ऊर्जा की बात, हमलोगों के गार्जियन हैं। यह सही है कि ऊर्जा का उत्पादन हो, बिजली का उत्पादन चाहे पावरग्रीड स्टेशन लगाना जो भी काम हुआ है वह काम किये, लेकिन एक चीज सदन में बोले थे कि बिहार को महाराष्ट्र से ज्यादा महंगी बिजली मिलती है, सदन में बोले थे सर कि बिहार को महाराष्ट्र से ज्यादा महंगी बिजली मिलती है । अब तो गार्जियन से मेरा आग्रह होगा कि महाराष्ट्र क्या बिहार पिछड़ा राज्य है तो कम से कम इसको तो सस्ती बिजली मिलनी चाहिए और दूसरा है कि जितना भी जर्जर पोल और तार बिहार में है । हमारे क्षेत्र में भी है । सर, बोले थे कि सारे जर्जर पोल और तार को बदल दिया गया है, कई बार हमलोगों ने विभाग में एक्सक्यूटिव

इंजीनियर से लेकर के तमाम लोगों को लिखकर दिया, लेकिन आज तक उसपर कोई कार्रवाई नहीं होती है । हां यह बात सही है कि जब तक प्रत्यय अमृत जी मुजफ्फरपुर के थे वो हमलोग बात करते थे तो काम होता था, लेकिन अब यह स्थिति है कि अगर ट्रांसफार्मर जल जाय तो 15 दिन, महीना दिन से पहले ट्रांसफार्मर भी नहीं बदलता है, गांव का गांव अंधेरे में रहता है और इतना मनमानी हो रहा है कि अगर किसी गांव में दस आदमी के पास बिजली बिल बचा हुआ है, बिजली बिल जमा नहीं कर रहा है तो उस पूरे गांव का ट्रांसफार्मर से लाइन काट दिया जाता है । हमलोग परेशान होते हैं और प्रमोद बाबू तो अभी सत्ता पक्ष में गये हैं इनको परेशानी नहीं होती होगी, हमलोग झेलते हैं ये सब, लोगों को मिट्टी तेल उपलब्ध नहीं होता है, लाइन कट जाता है अंधेरे में कैसे गरीब का बच्चा, परिवार कैसे बसर करता है । इन तमाम चीजों पर मैं आग्रह करूँगा गार्जियन से कि ध्यान देने की जरूरत है और आम आदमी को जो परेशानी हो रही है, ब्यूरोक्रेट जो हॉवी हो रहा है । मैं समझता हूँ कि सदन का कोई भी विधायक ये नहीं बोल सकता कि हम अगर किसी ब्यूरोक्रेट को बोल देंगे तो वह काम हो जायेगा । अब दो-चार लोग होंगे वैसे- सत्ता वाले हैं मुंह नहीं खोल सकते, उनको सबकुछ जानकर भी चुप रहना है । हम विपक्ष में हैं जो सही होगा बोलेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इधर देखकर बोलिये मुन्ना जी, बोलिये अपनी बात ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अभी जो स्थिति है अब मुख्यमंत्री आवास योजना में अभी प्रणव बाबू हमारे यहां तत्कालीन डी0एम0 थे । इनके समय में हमारे मीनापुर का 4500 परिवार चिन्हित हुआ था मुख्यमंत्री आवास योजना में और उस 4500 परिवार में 308 परिवार केवल मीनापुर को भेजा गया है । अब सोच सकते हैं कि 4500 में 308 गया। मुख्यमंत्री आवास में सहायता राशि कि जो पुराने भवन हैं, जो जर्जर है और नहीं बन पाया उसको 50 हजार रूपया देना है । मैं समझता हूँ कि प्रखंड वाइज अगर पता लगा लीजिए तो केवल 10 आदमी को भी अभी पैसा नहीं मिल पाया है । अभी बड़े भाई सम्राट भाई नहीं हैं, उप मुख्यमंत्री जी- उस दिन बोल रहे थे कि 94 लाख लोगों को हम रोजगार देने जा रहे हैं मैं सुना हूँ उनका । महागठबंधन की सरकार जिसमें आदरणीय तेजस्वी जी जातीय गणना करवाये, गरीबी रेखा से नीचे 94 लाख परिवार को जो चिन्हित किया गया जिसके लिए सहायता राशि 2 लाख रूपया देना था । अब उसको कह रहे हैं कि हम 94 लाख को

रोजगार दे रहे हैं तो सारा चीज तो हमारे महागठबंधन का है और गिना रहे हैं कि हमलोग इसमें 2 लाख 78 हजार करोड़ का बजट ले आये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : फिर आप उधर बात कर रहे हैं, इधर बात करिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : 10 दिन में- अरे आप बजट का उपर का पन्ना दिखाइये कि कब टाइपिंग में गया है समझ में आ जायेगा आपको- अरे वह तेजस्वी जी का विजन है, तेजस्वी जी के विजन के कारण उसको दिखा रहे हैं आप । कहां गये थे पहले 2020 में.....

अध्यक्ष : आपका टाइम किल हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : फिर तब हमको बजट से हट जाना पड़ेगा ।

अध्यक्ष : शांति-शांति टोकाटोकी नहीं कीजिए ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : आप 1990 से 2005 की बात करते हैं । आप भूल गये हैं कि मानसिक गुलामी से निकालने वाले बिहार में लालू यादव हैं । जिन्होंने आदमी को मानसिक गुलामी से निकाला है और मानसिक गुलामी से निकालकर के सदन तक पहुंचाया । आप कह रहे हैं 1990 और 2005 ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग बैठिए । मुन्ना जी, इधर देखकर बात कीजिए । सब आपका समय किल कर रहे हैं और आप उसी चक्कर में पड़ गये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी मद्य निषेध के तहत पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने मद्य निषेध में शराब बन्दी कानून को सही ढंग से जमीन पर उतारा, इसके लिए चेकपोस्ट क्या-क्या सब बना दिये । अभी जो स्थिति है 10 लाख 55 हजार 348 व्यक्ति आज गिरफ्तार है । अब मांझी जी हमारे गार्जियन हैं वे भी बोलते थे पहले । इसमें आप पता लगा लीजिए कि 95 परसेंट लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करनेवाले हैं । उनका कोई बेल कराकर निकालनेवाला नहीं है और जो पूंजीपति लोग हैं वे कहां जा रहे हैं । ये 95 परसेंट लोग समाज के गरीब, दलित,

महादलित परिवार का है जो कभी ताड़ी पीकर रोड पर घूम रहा है तो मशीन मुंह में लगा देता है । ऐसे ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में रखा गया है । महोदय, दूसरा एक नंबर है उसको सार्वजनिक नहीं करना है केवल सूचना करेगा- आजकल हो सकता है कि इन लोगों के क्षेत्र में नहीं हो, गांव घर में क्या होता है कि अगल बगल किसी का विरोधी है तो उसका नंबर बता देगा उसको फोन कर देगा और जो शरीफ आदमी है उसके घर पर पुलिस पहुंच जाती है । अब एक बार पहुंच गया कोई बात नहीं है, बार-बार दो से चार बार पहुंचता है हमलोग परेशान होते हैं कि भैय्या हमलोगों को परेशानी हो रही है तो फिर गांव समाज के मुखिया, वार्ड मेंबर इनलोगों से लिखवाकर हमलोग उसको जिला में भेजवाते हैं एस0पी0 के यहां ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलिये न ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में कानून अगर बना है तो जो अपराधी है उसके लिए बना है न कि जो आम आदमी है, शरीफ आदमी है, सही आदमी है उसके घर में अगर 12 बजे, 1 बजे रात में पुलिस रेड मारती है तो उस आदमी की प्रतिष्ठा का हनन होता है और वह आदमी बेचैन होकर हमलोगों को बोलता है । मैं तो आग्रह करूँगा मंत्री महोदय से कि जो आदमी गलत इन्फोर्मेशन करता है वैसे लोगों को भी चिन्हित करके कार्रवाई हो ताकि कोई सही आदमी को गुमराह न करे । अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग का एक रिपोर्ट आया है विधि-व्यवस्था, लॉ ऐंड आर्डर, कानून का राज सारी बात सुनते-सुनते हमलोग देखे हैं कि एन0सी0आर0बी0 का रिपोर्ट है साइबर आर्थिक अपराध के मामले में बिहार टॉप टेन राज्य में शामिल है।

क्रमशः

टर्न-12/पुलकित/23.02.2024

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव (क्रमशः) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले साल आर्थिक अपराध के मामलों में बिहार 6 वें स्थान पर है और पूरे देश में साइबर अपराध में 7वें स्थान पर है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, 1990 का हम आपको बतायेंगे। अध्यक्ष महोदय, सुशासन का राज आज के दौर में, हमारे सभी साथी यहां बैठे हुए हैं अगर किसी

आदमी को रास्ते में रिवॉल्वर दिखाकर उससे पैसा का झोला छीन लिया जाता है, लूट लिया जाता है । अगर वह आदमी थाना में एफ0आई0आर0 कराने जाता है तो थाना वाला कहता है कि लूट मत लिखाइये, कहो कि चोरी हो गया है।

(व्यवधान)

आप बताइये, क्या ऐसा नहीं होता है, खड़ा होकर बोलिये, बिहार की जनता देखेगी। महोदय, जब तक थाना चोरी नहीं लिखता है तब तक एफ0आई0आर0 नहीं होती है। महोदय, किसी की मोटर साईकिल छीन ली जाती है और थाना वाला कहता है कि कहो कि चोरी हो गया है और इसके बावजूद भी अपराध के मामले में बिहार टॉप 10 में है । हमारे ही जिला में 15 दिनों के अंदर में दर्जनों हत्या हो गयी हैं और जब हमने डी0एस0पी0, एस0पी0 से बात की, थाना प्रभारी से बात की तो कहते हैं कि सर, 40 परसेंट तक हमलोग पहुंचे हुए हैं । महोदय, ये 40 परसेंट क्या पहुंचा हुआ है, यह हमको भी नहीं बुझाया और कहते हैं कि क्राइम कंट्रोल हो गया । महोदय, थाना में एफ0आई0आर0 नहीं होती, किसी की बच्ची को अगर अगवा कर लिया जाता है तो कहते हैं कि प्रेम-प्रसंग में चली गयी । जमीनी हकीकत से मत मुकरिये । यह मनोबल बढ़ा हुआ है किसी विधायक की हस्ती नहीं है कि किसी थानेदार को...

अध्यक्ष : मुन्ना जी, अंगुली मत दिखाइये । मुस्कुराकर बोलिये कितना बढ़िया आप बोलते हैं।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय, हम तो भूल गये हैं कि आप विजय बाबू नहीं हैं, अब तो वे डिप्टी सी0एम0 हो गये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अब जो स्थिति है किसी विधायक के कहने पर एक चपरासी बदल सकता है ?

(व्यवधान)

हमको दिक्कत नहीं है, इसी सदन में, इसी जगह पर विजय बाबू बैठे हुए थे ।

(व्यवधान)

बात सुनिये ।

अध्यक्ष : शांत रहिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : विजय बाबू की एक डी0एस0पी0 और इंस्पेक्टर ने बात नहीं मानी । महोदय, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपसे सदन नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलता है विधान सभा । महोदय, हमलोग देखे हुए हैं, हमलोगों को क्या है ?

(व्यवधान)

कानून का राज है । जब हमारे मुख्यमंत्री जी, म्यूज्यिम का उद्घाटन हो रहा था, हमलोग लाइव देख रहे थे । उसमें पदाधिकारी लोग से कहते हैं कि मैं आपलोगों को हाथ जोड़ता हूं कहिये तो मैं पांव पड़ता हूँ, आपलोग काम कीजिए । लाईव टेलिकास्ट हो रहा था, जब हमारे सदन के नेता वही जब झुककर प्रणाम करते हैं तो हमलोग हम चपरासी को भी कहेंगे प्रणाम । कोई प्रोटोकॉल नहीं है ।

(व्यवधान)

सही बात है, वह भी आदमी है आप उससे भी बदतर हैं । आपकी हैसियत नहीं है। महोदय, हमलोग यकीन से मान रहे हैं जहां विधान सभा अध्यक्ष हो, उनका कोई....

अध्यक्ष : मुन्ना जी, सभी माननीय सदस्यों की हैसियत एक समान है ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : नहीं सर ।

अध्यक्ष : यहां कोई असमानता नहीं है ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय, मैं यहां की बात नहीं कर रहा । जो स्थिति हो रही है, किसी सदस्य की हैसियत नहीं है कि एक चपरासी को इधर से उधर कर दें । जनता लूटी जा रही है । हमलोग आंख पर पट्टी बांधकर मजबूरी से बैठे रहते हैं ।

अध्यक्ष : मुन्ना जी, कोई माननीय सदस्य इधर-उधर नहीं करते हैं, यह करना भी नहीं चाहिए। बोलिये, आप बात रखिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : मैं इधर उधर नहीं कह रहा हूं । महोदय, जो स्थिति आज राज्य की बनी हुई है, मैं उस बात को कह रहा हूं, कोई भी ऐसी संस्था बताइये जहां बिना घूस के कोई काम हो जाता है । आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र पहले लोग डरते थे, ये जो कह रहे हैं 2005 से पहले ।

अध्यक्ष : आप अब कंक्लूड करिये । आप इधर-उधर के चक्कर में पड़ गये हैं इसलिए अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : वर्ष 2005 से पहले लोग डरता था, किसी गरीब आदमी से बात करने में, बी0डी0ओ0 और सी0ओ0 के लोग यहां धड़ल्ले से पहुंचते थे लेकिन आज का आम आदमी है जो डरता है किसी पदाधिकारी से बात करने में । जब विधायक लोग डरता है तो आम आदमी की क्या वैल्यू है ।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो स्थिति हुई है अब बहुत सारी चीज है जो आप किसी पर कॉन्ट्रैक्ट पर एन0जी0ओ0 को, किसी को दे दिया गया है । आज पूरे बिहार का मुखिया भी त्रस्त है, जिला में वेंडर बहाल कर दिया गया है । मुखिया जी, लोगों को कहा गया है कि उसी वेंडर से आपको सामान लेना है और उसी का बाउचर लगाना है । महोदय, फिर वहां घूसखोरी बढ़ गयी, अब जो वेंडर बाउचर लगाता है, वह कहता है हमको 10 प्रतिशत पहले दे दो, अब जिसके कारण काम बाधित हो रहा है, अब हर जगह सारा सिस्टम पैरालाइज कर रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय, गृह विभाग में अभी तक चौकीदार कितने मर गये, कितने रिटायर कर गये । अभी चौकीदारों की बहाली नहीं हो रही है । हमारे यहां के कुछ मामले हैं और आप कह रहे हैं समाप्त करिये ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय, एक मिनट का समय दिया जाए, हमारे यहां के कुछ मामले हैं । आप भी एक-दो मिनट बढ़ा लेते थे । हमारे यहां का मामला है कि मीनापुर में आई0टी0आई0 कॉलेज के लिए है । प्रणव बाबू यहां बैठे हुए हैं, कई बार इनको जमीन दिलाई लेकिन अभी तक आई0टी0आई0 कॉलेज नहीं बना । मीनापुर आई0टी0आई0 कॉलेज की स्वीकृति हो गयी, एडमिशन हो गया कॉलेज में लेकिन भवन नहीं बना । महोदय, 500 बेड का छात्रावास और 10+2 स्कूल अब जमीन दिये हैं तो कहते हैं कि 10 करोड़ इसमें भरने में लगेगा । महोदय, 300 करोड़ में आप एयरपोर्ट भरवा रहे हैं । 300 करोड़ का दरभंगा एयरपोर्ट का बजट है । महोदय, 10 करोड़ में भरवाना है तो इंस्टीट्यूट नहीं बना । तीसरा, मामला है प्रमोद बाबू के समय का ये जब मंत्री थे । इनके समय में भष्मी देवी मंदिर का रिपोर्ट तलब । आप जवाब दिये हुए हैं और इसमें दिये हुए हैं 2014 में मंदिर के विकास के लिए 15 करोड़ 75 लाख रुपये की योजना तैयार कर विभाग को भेज दी गयी है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय, एक मिनट । आप जो मेरा 15 करोड़ रुपया भष्मी देवी मंदिर वाला कब दिलवा रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में है, आप कर दीजिए । महोदय, जब आप कह रहे हैं तो अंत में मैं आपको दो शब्द बोलकर छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि भष्मी देवी का मामला था ।

अध्यक्ष : आप मुझे मत छोड़िये, मेरे साथ जुड़े रहिये आप । छोड़ना नहीं है मुझे । हम कहां छोड़ने वाले हैं आपको ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय, पहले तो आप ज्यादा शायरी इधर करते थे, अब तो वहां आ गये ।

अध्यक्ष : किसी भी तरफ रहें, वहां भी, यहां भी, यहां भी ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, अब ये लोग जो करामात कर रहे हैं पूरे देश में, थोड़ा उस पर भी मैं बोल देता हूं ।

अध्यक्ष : जल्दी पढ़िये, टाईम हो गया है आपका ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय,

''बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा ।
नदियों के कुछ नाम रखें, बहती धारों का क्या होगा,
शिव की गंगा भी पानी, आबे जमजम भी पानी है,
मुल्ला भी पिये, पंडित भी पिये, पानी का मजहब क्या होगा,
इन फिरकापरस्तों से पूछते क्या सूरज अलग बनाओगे ।
एक हवा में सांस हैं, सबकी क्या हवा भी नहीं चलाओगे ।
नस्लों का करें जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है
क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है ।''

यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । जय हिन्द ।

अध्यक्ष : आप जब इतनी लम्बी-लम्बी कविता करने लगे तो विनय बिहारी जी का भी मन कर रहा है कुछ कहने का । बोलिये विनय बिहारी जी कुछ, केवल पढ़ना नहीं है, सिर्फ कविता करनी है ।

(व्यवधान)

शांत रहिये ।

श्री विनय बिहारी : जी महोदय ।

''बंद भईल बा मटियातेल, मोमबत्ती मंहगाईल बा,
लाईन काटेला, चौखट पर इंजीनियर खड़ीयाईल बा,
ए सरकार विचार करीं अब जान पे आफत आईल बा ।।

बकरी खोंसी मुरगा बेंचनी, तबो ना भार ओराईल बा,
ढ़ेंकूली-ढ़ेंकी जईसन कुटलस, मय बुद्धि लसराईल बा,
ए सरकार विचार करीं अब जान पे आफत आईल बा ।।

फिरी-फिरी कहिके बंटलस, आज समझ में समाईल बा,
एकहीं घर में अलगे-अलगे, चार-चार गो फाईल बा,
ए सरकार विचार करीं अब जान पे आफत आईल बा ।।

अध्यक्ष : आपकी कविता भी लम्बी है, बंद कर दीजिए ।

(व्यवधान)

एक-एक, दो-दो लाईन का पढ़ेंगे तो ज्यादा आनंद आयेगा, लम्बा-लम्बा पढ़ेंगे तो बोर हो जाता है आदमी ।

माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार ।

श्री प्रमोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले हम अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आसन को, आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

अध्यक्ष : आपका समय 10 मिनट है ।

श्री प्रमोद कुमार : जी । महोदय, कटौती जो प्रस्ताव पेश किया गया है इसके विपक्ष में बोलने के लिए हम खड़े हुए हैं । महोदय, आज ऊर्जा विभाग पर बहस है, श्री कृष्ण बाबू जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब-जब गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में बनी है, तभी ऊर्जा विभाग का विकास हुआ है । चाहे सन् 1977 में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार तो जार्ज फर्नान्डिस ने कांटी में थर्मल पावर लगाया था और अपने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार हुई तो बाढ़ में और कहलगांव में बिजली की योजना लागू हुई थी ।

(व्यवधान)

अटल बिहारी वाजपेयी के समय सुनने का प्रयास कीजिए । महोदय, उसके बाद आज नरेन्द्र मोदी जी भारत की सरकार बनी है तो बिजली विभाग और गांव-गांव और अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज गांव-गांव में विद्युतीकरण हुआ है । महोदय, एक जमाना था कि हमलोग कहते थे बिजली रानी आयेगी, आयेगी और जब आ जाती थी तो कब जायेगी इसका तुरंत कुछ पता नहीं था ।

अध्यक्ष : लेकिन हमलोग तो दूसरी बात कहते थे । हमलोग कहते थे कि कब बिजली आयेगी इसका इंतजार होता था लेकिन अब लोग सोचते हैं कि कब बिजली जा सकती है, जायेगी या नहीं जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार : जी ।

अध्यक्ष : ऐसे बोलिये ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, उस जमाने में हमलोग जब विधायक थे तो अपने विधायक योजना का रुपया लगाकर गांव-गांव में ट्रांसफॉर्मर लगाये थे । धन्यवाद है अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, बिजेन्द्र बाबू का कि आज दो करोड़ उपभोक्ता बिजली विभाग के जो बिहार में हैं और औसतन 23 से 24 घंटे शहर में और 21 से 22 घंटे गांवों में विद्युत आपूर्ति हो रही है । आज बिजली का उत्पादन 7576 मेगावाट तक पहुंच गया है । वर्ष 2024-25 में आठ हजार मेगावाट से अधिक होने की उम्मीद है । महोदय, हर खेत को बिजली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना/परियोजना जो लागू अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया, जिसके तहत आज बिहार के हर खेत को बिजली देने का काम बिजली विभाग ने किया है । इसके तहत आज किसानों की आमदनी दुगुनी हो रही है, सस्ते दर पर बिजली मिल रही है और कृषि के क्षेत्र में पंप चल रहे हैं ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

जहां तक उत्पादन है, आज उपलब्धता लगभग 9 हजार मेगावाट है जिसमें 2486 मेगावाट बिजली नवी एवं नवीकरण नगर से प्राप्त होता है । महोदय, इस प्रकार आपको नॉर्थ कॉम्युनिकेशन निर्धारित है और लगभग 2090 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त हो रही है । जल-जीवन-हरियाली, जिसके बारे में चर्चा हो रही है । जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत ऊर्जा विभाग ने आज राज्य सरकार द्वारा कजरा, लखीसराय, पीरपैंती, भागलपुर विद्युत केंद्र की स्थापना लगभग 450 मेगावाट, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, यह आंकड़ें बता रहे हैं और यह इसी सरकार में हुआ है । महोदय, एक जमाना था कि बिजली का साइन बोर्ड लगा दिया था..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टोका-टोकी मत कीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी धन्यवाद है, बधाई है । महोदय, आज हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम हो रहा है । इस प्रकार जो संरचना है बिजली के क्षेत्र में और इस संरचना के तहत वर्तमान में जो ग्रिड उपकरण, एक जमाना था हमारे मोतिहारी विधान सभा क्षेत्र में ग्रिड छोटा था, उपकेंद्र नहीं थे और बिजली के ट्रांसफॉर्मर के लिए तो समझिए महीना, दो महीने में गांव-गांव में चंदा वसूलाता था । वह समय था कि गांव में चंदा वसूलाता था फिर चेन के लिए पैसा दिया

जाता था और ट्रैक्टर का भाड़ा दिया जाता था और तब यहां से पैरवी होती थी तब बिजली का ट्रांसफॉर्मर जाता था । जब ट्रांसफॉर्मर चल जाता था तो वह रिपेयर, दो-चार-पांच दिन के बाद शॉर्ट लगा तो वह खत्म । आज वैसी स्थिति नहीं है, आज फोन कीजिए 12 घंटे में ट्रांसफॉर्मर पहुंचता है । मैक्सिमम..

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, आज भी तो..

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मुन्ना बाबू, आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, टोका-टोकी नहीं करें ।

श्री प्रमोद कुमार : हम बता रहे हैं, महोदय, इन लोगों की संस्कृति है इसी तरह चंदा वसूल-वसूल कर उपार्जन करना, तो यह काम इन लोगों का पुराना काम है, यह पुराना काम है । विधायक जी के क्षेत्र के लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि हर बात में ये चंदा ही वसूलवाते हैं । क्या कीजिएगा इनकी तो यह संस्कृति है ।

महोदय, ग्रिड उपकेंद्र राज्य में 164, संरचना लाईन कुल लंबाई 9527 सर्किट किलोमीटर और बढ़कर अब 14024 मेगावाट और 2024-25 में सब स्टेशनों की संख्या बढ़कर 176 हो जायेगी । महोदय, खुले तार थे और खुले तार में, बिजली जो है, बिजली के जर्जर तार, जर्जर पोल, आज बिजली के तार का मॉर्डनफिकेशन हुआ है । कवर वायर गया है और आज बिजली के क्षेत्र में जो तरक्की हुई है जिसके कारण आज गांव-गांव में छोटे-छोटे उद्योग का जाल बिछ रहा है । यह सब तरक्की बिजली के क्षेत्र में हुआ है । महोदय, बक्सर थर्मल पॉवर प्लांट का उत्पादन होने वाला है । विद्युत निकलने वाली है और इसके अंतर्गत 400 के0वी0 के और 246 सर्किट किलोमीटर लंबाई और 220 के0वी0 के और 564 सर्किट किलोमीटर लाईन और इस प्रकार लाईन का फस्ट फेज, सेकेण्ड फेज और अब थर्ड फेज में जहां-जहां छूटे हुए हैं उन जगहों को बाजाब्ते प्लांट प्रोजेक्ट बनाकर आज बिजली विभाग काम कर रहा है । इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, हम माननीय मुख्यमंत्री और, इसके लिए पहले धन नहीं था, पहले एक जमाना था कि बड़ा-बड़ा साईन बोर्ड लगाकर गांव में बिजली का 10 के0वी0ए0 का छोटा-छोटा ट्रांसफॉर्मर दे दिया कबूतर की तरह और उसी से गांव को जोड़ दिया और लाईन जोड़ने के साथ...

(व्यवधान)

सुनिए, बात सुनिए । और वह ट्रांसफॉर्मर उपाध्यक्ष महोदय जल जाता था ।..

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की ओर देखकर बोलिए ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, वितरण के क्षेत्र में आज कृषि उपभोक्ता को 3311 के0वी0ए0 के 291 विद्युत उपकेंद्र बने हैं और 1354 पृथक फीडर भी बने हैं । इस प्रकार आज राज्य सरकार द्वारा...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास मात्र दो मिनट समय है ।

श्री प्रमोद कुमार : 1329.61 करोड़ की मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबद्ध योजना 2020 में दी गयी । इस योजना के तहत नि:शुल्क विद्युत संबंध दिये जा रहे हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, इस प्रकार चौथे कृषि रोड मैप के तहत 2023 से 2028 अंतर्गत विद्युत संरचना के निर्माण के साथ-साथ 4.80 लाख कृषक हैंड पंप सेट भी नि:शुल्क दिये गये । महोदय, किसानों को बिजली के साथ पंप सेट नि:शुल्क दिये गये कि किसान की तरक्की हो । चौथे कृषि रोड मैप में यह विषय आया । महोदय, आज मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत 70 पैसे प्रति यूनिट सस्ती दर से बिजली उपलब्ध कराया जाता है, मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना अंतर्गत...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास मात्र एक मिनट समय है ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, आज स्मार्ट मीटर भी लग रहे हैं । जहां-जहां स्मार्ट मीटर के बारे में कंप्लेन होती है उसका भी आज निराकरण हो रहा है, तो बिजली के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं । गृह विभाग, साथी बता रहे थे कि एफ0आई0आर0 नहीं होता है, डी0जी0पी0 बैठे हुए हैं, उनका बाजाब्ते मोबाईल पर चलता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर एफ0आई0आर0 नहीं हो रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और उनका एक्शन होता है और तुरंत एफ0आई0आर0 होता है । नंबर जो है पढ़ लीजिएगा और 112 नंबर..

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है ।

श्री प्रमोद कुमार : सुन लीजिए, यह बता रहे हैं, 112 नंबर पर जहां से फोन कीजिए वहां प्राथमिकी दर्ज करने के लिए..

टर्न-14/हेमन्त/23.02.2024

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, आज अपराधी जितना बड़ा हो, जितना जमीन के नीचे है, उसको निकाला जा रहा है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार : और एक जमाना था कि गृह विभाग, जो अपराधी था वह सी0एम0 हाऊस में मिलता था और ये लोग लाइजिनिंग करते थे, आज वह नहीं है । बस स्टैंड से उतर गये, तो चलकर घर जाना मुश्किल था । रेलवे स्टेशन पर ही रात गुजारनी पड़ती थी ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, आपने जो समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी जी । आपके पास 20 मिनट का वक्त है ।

श्री भूदेव चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस गरिमामयी पद पर आज सर्वसम्मति से आसीन हुए हैं इसके लिए मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आपके प्रति शुक्रगुजार हूं और आपको ढ़ेर सारी बधाइयां देता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, खासकर शाहीन साहब का, जिन्होंने मुझको आज इस बजट के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया है ।

महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बातें हो रही हैं और सम्मानित विधायकों ने अपनी-अपनी तरह से अपनी बातों को रखा है और खासकर सरकार की तरफ से विधायकों ने जो अपनी बात रखी है उसमें सरकार की तारीफ की है, उपलब्धियों को गिनाया है, लेकिन मुझे एक शेर याद आता है कि-

''जिंदगी ने सवाल बदल डाले हैं,
वक्त ने हालात बदल डाले हैं,
हम तो आज भी वहीं हैं, जहां कल थे,
बस लोगों ने अपने जज्बात बदल डाले हैं ।''

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस बिजली की चर्चा हो रही है, इस बिजली का आविष्कार अमेरिका में 1752 ई0 में हुआ । उस समय जो दार्शनिक थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रेंकलिन, जिन्होंने प्रयोग किया और साबित किया कि आकाश में प्रकाश की चमक बिजली का ही रूप है, जबकि विद्युत प्रकाश का निर्माण सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक हम्फ्री डैवी ने किया था । वहीं, विद्युत बल्ब के निर्माण का श्रेय थॉमस एडिसन को जाता है । आजादी के पहले इस देश में सबसे पहले कलकत्ता में बिजली आयी थी, 1879 ई0 में । आजादी के पहले 1879 ई0 में इस भारत की धरती पर सबसे पहले कलकत्ता में बिजली आयी थी और बिहार में, बिहार उस समय अखंड बिहार था, झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था, तो आजादी के 10 वर्ष पहले एक बुदिया परिवार को इसका लाइसेंस दिया था 1935 ई0 में । तब से इस बिजली की महत्ता बढ़ गयी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब बिजली की बात होती है, तो मैं उस वैज्ञानिक की उस भाषा को सुनने के लिए उनकी किताब को पढ़ता हूं, तो उन्होंने कहा था कि बिजली का मकसद, बिजली उत्पादन का मकसद कि जहां भी बिजली जायेगी, वहां कल-कारखाने लगेंगे । एक सुई से लेकर हवाई जहाज का निर्माण, एक पिस्टल से लेकर स्टेन गन का निर्माण सिर्फ बिजली के माध्यम से ही हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है । लेकिन आज पीठ थपथपा रहे हैं और खासकर लोग कह रहे हैं कि गांव में बिजली चमकने लगी है, बल्ब जलने लगे हैं, 24 घंटा बिजली का प्रवाह होने लगा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस सदन में कह सकता हूं कि उस आविष्कारक की आत्मा अगर पढ़ती होगी बिहार पर, तो उनको पछतावा होता होगा कि मेरे मकसद ने कामयाबी हासिल नहीं की, मेरा मकसद यह नहीं था कि बिजली से आप घर को चमकाओ, चार के बदले आठ बल्ब लगाओ, मरकरी लगाओ, ए0सी0 लगाओ, पंखे चलाओ, उनका यह मकसद नहीं था । उनका मकसद था कि जिस इलाके में बिजली चली जायेगी, उस इलाके में खुशहाली आयेगी, वहां कल-कारखाने लगेंगे, वहां उद्योग धंधे चलेंगे और इसी उद्देश्य से बिजली का आविष्कार हुआ था ।

महोदय, बड़ी तारीफ होती है और खासकर एनडीए के लोग बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है । वाह, डबल इंजन की सरकार है, यह हम भी मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार है । लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, चूंकि मैं बिहार का हूं इसलिए व्यथा होती है, पीड़ा होती है, एन0डी0ए0 के लोगों, जो यह आप तारीफ करते हो, करो, मैं नहीं कहता हूं कि आप तारीफ नहीं करो, लेकिन वस्तुस्थिति से भी आपको पीड़ा होगी, आपको जानकर दुख होगा कि आज दिल्ली में बिजली 3 रु0 प्रति यूनिट, महाराष्ट्र में 3.44 रु0 प्रति यूनिट, गुजरात में 3.10 रु0 प्रति यूनिट, यूपी में 3.35 रु0 प्रति यूनिट, मध्य प्रदेश में 3.25 रु0 प्रति यूनिट, राजस्थान में 3 रु0 प्रति यूनिट और बिहार में, आपको जानकर दुख होगा कि बिहार में आज भी जो बिजली मिलती है वह 4.36 रु0 प्रति यूनिट मिलती है । यह कितना बड़ा दुख है । जब आप स्वीकार करते हैं, बिहार की सरकार स्वीकार करती है, केंद्र की सरकार स्वीकार करती है कि बिहार गरीब राज्य है, बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, तो इन विकसित राज्यों की तुलना में बिहार में आज भी बिजली महंगी क्यों है ? इस पर कौन चिंतन-मनन करेगा ? बिहार में जो सरकार आरूढ़ है, विद्यमान है, जो विराजमान है उसको चिंता करने की जरूरत है ।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार कृषि प्रधान राज्य है । यहां 76 प्रतिशत लोग, ग्रामीण जनता, किसान के रूप में जाने जाते हैं । किसान जी-तोड़ मेहनत करते हैं,

फसल उत्पादन करते हैं, लेकिन उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है । खेती करने के लिए बिजली पर आश्रित हैं । तो क्या होता है, हम लोग तो गांव में रहते हैं, गांव में बिजली तो रहती है, लेकिन किसानों के खेत में जब जरूरत होती है बिजली की, तो लाईन नहीं रहती है । चार-पांच घंटे किसी तरह उनको उपलब्ध होती है और जब लाईन कट जाती है, तो वह किसान टेलीफोन पर बोलते हैं कि भूदेव जी, कैसे खेती करें, आधा खेत भी नहीं पटा है और आजकल तो परिपाटी हो गयी है उपाध्यक्ष महोदय, जब से प्राईवेट कंपनी को इसकी जिम्मेवारी दी गयी है, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि जो पहले मीटर चेक करने वाले थे, जो डील करते थे, मीटर चेक करते थे, उन सबको नजरअंदाज कर दिया, उनको हटा दिया । वह अपनी कंपनी के माध्यम से, जो रीडर हैं, जो रीड करते हैं, मीटर रीडर, उनकी बहाली हुई है, वह अंजान आदमी है, उसको टार्गेट दिया है । ऐसा कोई दिन नहीं है कि वह एक दर्जन लोगों के यहां जाकर बिजली के माध्यम से एफ0आई0आर0 नहीं करता हो, फाईन न लगाता हो । ऐसे-ऐसे घरों में बिजली काट दी जाती है और एफ0आई0आर0 होती है और इतना ज्यादा फाईन लगा देते हैं कि वह बेचारा अगर घर भी बेच देगा, जो बिजली का फाईन है, जुर्माना है उसका भुगतान नहीं हो सकता है । क्या करता है किसान ? किसान अप्लाई करता है, मीटर के लिए अप्लाई करता है, कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है, लेकिन क्या कहा जाय उपाध्यक्ष महोदय, वह महीनों-दिन दौड़ता है । महीनों-दिन दौड़ने के बाद पता नहीं ऑनलाईन के बाद क्या रिपोर्ट मिलती है कि आपका खाता गलत है, आपका खेसरा गलत है, आपने आधार कार्ड का एक नम्बर छोड़ दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से विनती करता हूं, विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से वह बिजली चोरी के आरोप में उनके ऊपर एफ0आई0आर0 करता है, गिरफ्तार करता है, उनको आप हिदायत दें कि आप जाओ और जाओ, तो उसका मीटर लेकर जाओ । जाओ, तो उसको कनेक्शन दे दो, उसको समझा दो, उसको वार्निंग दे दो । गांव के किसान लोग बड़े निरीह होते हैं, बड़े गरीब होते हैं, बेसहारा होते हैं, जुबान पर बातें नहीं होती हैं । वह तो छोटे-छोटे अफसर के भी पांव पड़ लेते हैं कि मुझको माफ कर दो । होता क्या है कि कोई लोकल मिस्त्री होता है, जब उसका तार गलकर नीचे चला जाता है, सड़ जाता है, तो वह आग्रह करता है, वह लगा देता है और वही कह देता है कुछ पैसे लेकर कि आप चलाओ, मैं देखूंगा । लेकिन जब उसको पैसे समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो फिर वह शिकायत करते हैं और वहां से टीम आती है और धड़ल्ले से उसके ऊपर एफ0आई0आर0 कर दी जाती है । मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार से कि

अगर किसानों के हित में आपको काम करना है, तो यह आपको निर्देश देना पड़ेगा कि एफ0आई0आर0 करने के पहले आप उसको कनेक्शन दे दो, उसको मीटर दे दो । मीटर के अभाव में, मीटर के लिए रोज दौड़ते हैं । किनको मीटर मिल रहा है, जो कुछ-न-कुछ रिश्वत देते हैं ऑफिस में जाकर । बिना रिश्वत के आपको मीटर उपलब्ध नहीं होता है ।

(क्रमशः)

टर्न-15/धिरेन्द्र/23.02.2024

(क्रमशः)

श्री भूदेव चौधरी : महोदय, वह गरीब, निरीह, वह किसान, वह बेचारा दूसरों के माध्यम से अनुरोध करता है, आग्रह करता है, दौड़-धूप करता है, थक जाता है और फिर स्थानीय मिस्त्री उसका कनेक्शन जोड़ देता है और उससे कुछ रिश्वत या पैसा ले लेता है और बाद में जब पता चलता है तब किसान के घर में जाकर, उसके खेतों में जाकर उसको बिजली के माध्यम से उस पर चोरी के आरोप में एफ॰आई॰आर॰ करता है । क्या करता है, वह चोरी क्या करता है सरकार से ? वह तो फसल उगाने के लिए यह रिस्क लेता है अगर फसल नहीं उगेगा, खेत में धान नहीं होगा, गेहूँ नहीं होगा तो हमलोग, आपलोग, देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या खायेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में उनको राहत देने की जरूरत है । उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार में जाति गणना की शुरूआत हुई, सम्पन्न भी हुई और इस जाति गणना से निष्कर्ष क्या निकला ? जाति गणना से निष्कर्ष निकला कि इस बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का आकलन हुआ । इसमें कौन लोग आयें ? अधिकांश दलित आयें, महादलित आयें, पिछड़ा आयें, अति पिछड़ा आयें, इन्हीं लोगों की आज स्थिति खराब है । हम सरकार से माँग करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि दलितों का, महादलितों का, पिछड़ों का, अतिपिछड़ों का उत्थान हो तो निश्चित तौर पर आप उनको 100-200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे । अगर आप कहते हैं कि मैं सुशासन की सरकार हूँ और इनके अनुयायी हूँ, इनके लिए मैं चिंतित हूँ तो निश्चित तौर पर जो जाति गणना हुआ और जाति गणना के आधार पर जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन हुआ, उसके आकलन को देखते हुए निश्चित तौर पर आप उनको बिजली की राहत देने की कृपा करें, यह मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि खासकर यह जो आपका स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया चली है । स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया में जो गरीब किसान लोग हैं, उनको राहत नहीं मिल रही है । या तो दलालों के माध्यम से, या जो वहाँ बड़े-बड़े

फैक्ट्री के मालिक हैं या व्यापारी हैं उनके माध्यम से पैसे वसूल करते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाँच से दस हजार स्मार्ट मीटर जो लगा है वे खराब पड़े हैं, उनको ठीक करने के लिए रोज आग्रह किया जाता है, आवेदन दिया जाता है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कोई कंसीडर नहीं होता है, उसको सीधे-सीधे शब्द में कहता है कि जो जा रहा है पहले वाला बिल, जाने दो उसी के मुताबिक दे दो, पर मुझको तो शंकाएं होती हैं कि किसी दिन आकर उसके ऊपर, बड़े-से-बड़े लोग आकर उसके ऊपर पैसे का इतना दबाव दे देंगे कि बेचारा घर-बार छोड़कर भाग जायेगा । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर के संबंध में आप गंभीरता से विचार कीजिये । बहुत से लोग तो स्मार्ट मीटर की क्या रूपरेखा है उस पर भी वे अवगत नहीं हैं, उनको प्रशिक्षण देने की जरूरत है । आप कहते हैं कि मैं किसानों के लिए बिजली आपूर्ति कर रहा हूँ, आप कैम्प लगायें, पंचायत में जायें, उन किसानों को मालूम नहीं है कि क्या इसकी प्रक्रिया है ? कैसे बिजली मिलेगी ? जरूरत है कैम्प लगाने की, पंचायत में कैम्प लगाकर किसानों को यह आगाह किया जाय, प्रशिक्षित किया जाय, जानकारी दी जाय कि सरकार ने इस तरह से आपके लिए बिजली का काम शुरू किया है । दुःख के साथ कहना पड़ता है, बिहार में अपनी सरकार के माध्यम से, बिहार की सरकार के माध्यम से तीन-चार जगह यूनिट खड़ा किया गया था जिसमें बरौनी था, कांटी था, नवीनगर था । उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़ा ही व्यथित होकर कहना पड़ता है, व्यथित हूँ कि तीनों, चारों जो थर्मल पॉवर थे, वे एन॰टी॰पी॰सी॰ को सुपुर्द कर दिये गये हैं । बिहार में अब अपना कोई यूनिट नहीं है, बिजली के उत्पादन का कोई स्रोत नहीं है तो मुझको लगता है कि निश्चित तौर पर जो बिजली की चर्चा हो रही है, उन आविष्कारक की जो मानसिकता थी, जो उनकी विश्वसनीयता थी, उस पर आँच आ रही है । पूज्य बापू महात्मा गांधी जी जब देश के कोने-कोने में पहुँचे थे और निराशा हाथ लगी थी, निराशा हाथ लगने के बाद जब वे बिहार की धरती पर आये थे तब बिहार की ताकत ने, बिहार की सांस ने, बिहार के युवाओं ने कंधे सहलाकर उनको आश्वस्त किया था कि जंग-ए-आजादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती है बल्कि बिहार की मिट्टी में इतनी ताकत है कि जंग-ए-आजादी की लड़ाई जीती भी जा सकती है लेकिन आज बिहार क्यों उपेक्षित है, आज बिहार का क्यों अपमान हो रहा है ? आप कहते हैं कि पिछले, जब भी आप कुछ बात करते हैं तो आप सीधे उदाहरण देते हैं वर्ष 2000, वर्ष 1990 के पहले बिहार कैसा था । कैसा था बिहार ? बिहार तो ऐसा सुनहरा बिहार था कि इसी बिहार का इतिहास भारत का इतिहास है । दुनिया में जब सम्मेलन हुआ कि कहाँ विश्वविद्यालय बनाया

जाय तो भारत में सबसे पहले जब चुनाव हुआ तो बिहार की धरती में हुआ, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय बना, विक्रमशीला विश्वविद्यालय बना । तक्षशिला भी बना था जो अभी पाकिस्तान मे चला गया । दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवि रामधारी सिंह दिनकर यहीं पैदा हुए थे, दुनिया का सबसे गणितज्ञ इसी बिहार में पैदा हुए आर्यभट्ट तो बिहार का सम्मान वर्ष 1990 के पहले नहीं था क्या ? आप इतिहास को जानें, वर्ष 1990 के पहले इतिहास था, नहीं था वह बात नहीं है ।

लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं,
मंजिल नहीं मिलती तो मुकद्दर को दोष देते हैं ।
खुद तो संभल कर चलते नहीं यारों,
ठेस लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं ।।

इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछली बातों को नजरअंदाज कर आपको जो दायित्व मिला है, आपको जो जवाबदेही मिली है और यह सदन जब चलता है तो खासकर बिहार के गरीब, दलित, मजदूर, अतिपिछड़ा इनकी नजर इस पर पड़ती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक सरकार से यहीं माँग करता हूँ कि अगर आप जानते हैं और चाहते हैं, जाति गणना के बाद जो 94 लाख लोगों को आपने गरीबी रेखा से नीचे दर्शाया है तो उन 94 लाख लोगों को बिजली मुफ्त करने की आप कृपा करिये ताकि उन गरीबों का उत्साह, उमंग और समर्थन आपको मिल सके और यही मैं कहना चाहता हूँ कि

जिसका गुमान नहीं था वही बात हो गयी,
यह शहर, शहर न रहा रात हो गयी ।
अच्छे दिन तो इस देश में आये नहीं,
मगर भाजपा के बुरे दिनों की शुरूआत हो गयी ।।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझको लगता है....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास मात्र दो मिनट का वक्त है ।

श्री भूदेव चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और भी, मद्य-निषेध विभाग पर भी मुझको कुछ बातें कहनी हैं । मद्य-निषेद विभाग में शराबबंदी, शराबबंदी है शराब तो अभी भगवान हो गया है, जैसे ईश्वर को कोई देखता नहीं है लेकिन भगवान है, उसी तरह से शराबबंदी पर शराब को कोई देखता नहीं है लेकिन गाँव घरों में आप जाएं, अब तो होम डिलेवरी होने लगा है....

(व्यवधान)

सुनने में तो हम आपके साथ ही बोलते रहते हैं और आपकी ही बात बोलते रहते हैं । और ठीक ही कहा मुन्ना जी ने लाखों लोग जेल की सलाखों के अंदर बंद हैं,

लाखों लोग, उसमें से अधिकांश निरीह लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग जो दो जून की रोटी भी ठीक से नहीं कमा सकता है । वह मर्द, वह पुरुष जेल चला गया, अब उसकी माँ और उसके बुढ़े बाप, उसकी पत्नि....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री भूदेव चौधरी : महोदय, सब बीमार हैं । अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ चूंकि आपने निर्देश दिया है । मैं अधिक आपका समय जाया नहीं करना चाहता हूँ और मुझको लगता है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी किसानों के हित में, पिछड़ों के हित में, दलितों के हित में और खासकर समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं उन जातियों के प्रति भी बिजली फ्री में आपूर्ति करेगी ।

गैरों के दंभ हम चलते नहीं,
जो मेरे अपने हैं उनके हाथ कभी फिसलते नहीं ।
कुछ टूट कर गए हैं मेरी खामियां बताने,
मेरे सामने पड़ते ही अपनी आवाज निकालते नहीं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री भूदेव चौधरी : महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझको बोलने का अवसर दिया है, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल जी । आपके पास 10 मिनट का वक्त है।

टर्न-16/संगीता/23.02.2024

श्री ललित नारायण मंडल : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हम गौरवान्वित हैं कि आपके सामने पहली बार आपके उपाध्यक्ष रहते हुए मुझे बोलने का मौका मिला है और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे समय दिया है । हम शुक्रगुजार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम शुक्रगुजार हैं माननीय ऊर्जा मंत्री का, हम शुक्रगुजार हैं दोनों उप मुख्यमंत्रियों का और हम शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं हमारे मुख्य सचेतक श्रवण बाबू का जो हमको 10 मिनट का समय विधान सभा में सरकार के पक्ष में बोलने के लिए मौका मिला है । हम शुक्रगुजार हैं सुल्तानगंज विधान सभा की जनता का भी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग द्वारा आज जो बजट पेश किया गया है उसकी जितनी बड़ाई की जाय वह कम पड़ेगा, आज लगभग 2 करोड़ उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति की जा रही है । शहरी इलाकों

में 23 से 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 21 से 22 घंटे विद्युत उपलब्ध है । विद्युत की मांग आसमान छूते जा रही है और लगता है कि 25 जुलाई जबकि 25 जुलाई 2023 को 7576 मेगावाट तक पहुंच गया है, इसकी डिमांग जिससे 2024-25 तक 8500 मेगावाट से अधिक होने की संभावना है । उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत की खपत अधिक हुई है इसका उदाहरण हमलोग अपने विद्यार्थी जीवन से देते हैं । हमलोग जब पढ़ते थे 1973 से 1980 के बीच में तो उस वक्त हमलोग आंदोलन करते थे प्रिंसिपल के पास और वी0सी0 के पास जाकर कि हमको किरासन तेल दो, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है । बिजली भागलपुर और मुंगेर जैसे शहरों को भी नहीं मिल पाती थी और हॉस्टल में बिजली नहीं रहती थी । हमलोग लाइन लगकर किरासन तेल खरीदते थे, और किरासन तेल में, लैंप में किरासन तेल देकर हम अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज का जमाना देखिए, आज विद्यार्थी हमको तो लगता है कि बहुत सारे बच्चे किरासन तेल का नाम नहीं जानते होंगे, भूल गए होंगे किरासन तेल भी कुछ होता है या लैंप भी कुछ होता है, भूल गए होंगे कि लालटेन भी कुछ होता है । उपाध्यक्ष महोदय, किरासन तेल की जरूरत नहीं है तो लालटेन की भी जरूरत नहीं है । हम कहना चाहते हैं कि पहले हमलोग जब कुछ छोटे थे आज से 10-20 साल पहले तो राजनीतिक दल के साथ जब गांव-घर जाते थे हम वोट मांगने के लिए तो गांव वाले कहते थे, बिजली नहीं तो वोट नहीं । आज एक भी घर, गांव की बात तो छोड़ दिया जाय, शहर की बात छोड़ दिया जाय सर, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसको विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है...

(व्यवधान)

उस पर भी हम आयेंगे । पहले उपलब्धता की बात हम करना चाहते हैं इसके लिए हम अपने माननीय मंत्री बिजेन्द्र बाबू का और अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के शुक्रगुजार हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आज आप जानते हैं कि बैटरी और इन्वर्टर का मार्केट खत्म हो गया है इसीलिए कि हमारे बिजली विभाग के जो मंत्री हैं इन्होंने विद्युत की आपूर्ति इतनी अधिक कर दी है कि अब लोग इन्वर्टर और बैटरी खरीदना भूल गए हैं...

(व्यवधान)

चिन्ता क्यों करते हैं, हमलोग एन0डी0ए0 के...

उपाध्यक्ष : माननीय ललित बाबू, आप आसन की ओर देखें ।

श्री ललित नारायण मंडल : ठीक है महोदय । उनको कहते हैं कि चिन्ता नहीं करिए, हमारे नेता राष्ट्रीय नेता मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और हम 400 के पार जाने वाले हैं

2024 में और 2025 में भी 200 के पार जाने वाले हैं इसलिए चिन्ता नहीं कीजिए, हमलोगों में लड़ाई लगाने की चिन्ता मत कीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी विद्युत उपलब्धता 9000 मेगावाट है जिसमें 2486 मेगावाट बिजली नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होता है । भविष्य में बाढ़, बक्सर और नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पॉवर स्टेशन की दो-दो निर्माणाधीन इकाइयों से बिहार को लगभग 2099 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी । उस वक्त हमको बिजली बिहार से बाहर भेजना पड़ेगा, उस दिन को भी आपलोग देखिएगा । उपाध्यक्ष महोदय, जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार का कजरा एवं पीरपैंती में जो विद्युत केंद्र है उसके स्थान पर लगभग 450 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन की एक परियोजना का निर्णय लिया है और लगाया है । हम जानते हैं कि हरित ऊर्जा की मदद से भी हमलोग ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं । राजगीर, बोधगया एवं पटना शहर के कुछ हिस्सों में परंपरागत बिजली के स्थान पर चौबीसों घंटा हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । जो आज आप सुनते हैं कि पर्यावरण की मार पूरे हिन्दुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया सह सही है और हमारे पटना और हमारे भागलपुर की स्थिति भी पर्यावरण के मामले में गड़बड़ा रही है । इस मामले में यह हरित ऊर्जा और सौर ऊर्जा हमको बहुत मदद करेगी और हमारे बच्चों को भी उनका भविष्य बनाने के लिए काम करेगा । इसके लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 210 मेगावाट हरित ऊर्जा आपूर्ति हेतु एकरारनामा किया गया है । केवल विद्युत उत्पादन की बात नहीं है, विद्युत उत्पादित हो और उसको जगह-जगह, घर-घर उपभोक्ता के पास भेजने की भी व्यवस्था हो ऐसा बिहार सरकार ने किया है । वर्तमान में राज्य में कार्यरत ग्रिड उपकेन्द्रों की संख्या 164 है और संचरण लाइनों की कुल लंबाई 19 हजार 527 किलोमीटर है जिससे विद्युत निकासी क्षमता बढ़कर 14 हजार 24 मेगावाट हो गई है । उपाध्यक्ष महोदय, 134 पृथक कृषि फीडर और 33/11 के0वी0 के 291 विद्युत उपकेंद्र की स्थापना हुई है। 01 हजार 329.61 करोड़ की मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना स्वीकृत हुई है । कृषि विद्युत संबंधों की संख्या लगभग 3.75 लाख हो गई है । कृषि उत्पादकों को और उपभोक्ता को सस्ते दर पर 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती है। यह बहुत बड़ी बात है, यह भारत सरकार और बिहार सरकार के चूंकि हम किसान के बच्चे हैं, बहुत ही कृतज्ञ हैं कि आपने किसानों को...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है ।

श्री ललित नारायण मंडल : ठीक है सर, दो मिनट बहुत है हमारे लिए । उपभोक्ताओं की संख्या 2 करोड़ है । बिहार देश का पहला राज्य है जहां बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था की गई है । निजी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया जा रहा है । अब तक कुल 2166 निजी भवनों में ये लगाए जा चुके हैं । उपाध्यक्ष महोदय, बोलना तो बहुत है, सरकार ने बिजली के लिए इतना काम किया है...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री ललित नारायण मंडल : जी, एक सेकेंड सर । अंत में अपने क्षेत्र की बात हम कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कुछ किसानों को उसके बोरिंग पर अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं हुआ है । बहुत जगह कनेक्शन हुआ है लेकिन जो बचा हुआ है उनको भी बिजली कनेक्शन मिले ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती प्रतिमा कुमारी ।

श्री ललित नारायण मंडल : धन्यवाद सर ।

टर्न–17/सुरज/23.02.2024

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा लाये गये बजट के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ी हुई हूं, जिसके लिये मैं अपनी पार्टी के मुख्य सचेतक आदरणीय राजेश राम जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अपने क्षेत्र राजापाकर की सम्मानित जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूं और साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई और शुभकामना देती हूं । बिहार सरकार इस बार ग्यारह हजार चार सौ बाईस करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार के वर्तमान बजट का प्रावधान किया है । परंतु वस्तुस्थिति यह है कि अभी तक अनेकों गांवों में बिजली आपूर्ति दूर है । बिजली आपूर्ति के अभाव में लगभग लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचाई से वंचित है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि बिजली विभाग की नाकामियों की वजह से हमारे विधान सभा क्षेत्र राजापाकर में पोहियार पंचायत की दलित बस्ती में विगत तीन महीनों से बिजली नहीं है । लगातार दूरभाष एवं लिखित पत्राचार के बावजूद भी महनार अनुमंडल के बिजली विभाग के एस0डी0ओ0 के द्वारा कोई सुध नहीं ली गयी । उसके बाद तीन महीनों के अथक प्रयास के बाद जब बिजली आयी तो वहां के महादलितों को तीन महीने का बिजली चार्ज उनसे लेने के लिये बिजली बिल भेज दिया गया । मैं यह कहना

चाहती हूं सरकार से आसन के माध्यम से कि आज से लगभग 10 साल पहले जब आबादी कम थी, वहां जो ट्रांसफार्मर लगाये गये थे 16 के0बी0 के आज आबादी बढ़ गयी है, जनसंख्या बढ़ने के बाद बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है और जहां इस देश में गांव-गांव तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चले गये हैं, बिजली के अभाव में उनको उपकरण चलाने में असुविधा हो रही है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलायी जा रही है, उसमें बहुत बड़ी खामियां हैं । खासतौर से दलित, महादलित टोलों में तीन हजार रुपये वसूले जाते हैं, जिसकी वजह से वे कर्ज लेकर तीन हजार रुपये देते तो हैं लेकिन जब उन तक पैसे आते हैं तब तक उनका सारा पैसा सूद में चला जाता है, जिसकी वजह से वह आवास नहीं बना पाते हैं । लेकिन कागजों पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है कि सब महादलितों को आवास मिल गया है । अभी तक हमारे विधान सभा क्षेत्र के जहांगीरपुरशाम, पोहियार, भिखनपुरा तमाम ऐसे पंचायत हैं जहां पर शौचालय निर्माण के बाद भी महादलितों को उनकी राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है । सरकार सदन में जो नियम और कानून बनाती है निश्चित रूप से जनसरोकार के लिये और जनहित में बनाया जाता है लेकिन मैं शराबबंदी पर बोलना चाहती हूं । शराबबंदी 2016 में हुआ और उसके बाद से आज तक कोई बहुत बड़ा माफिया सलाखों के पीछे नहीं गया, बल्कि दलित, महादलित, गरीब, पिछड़े, दो वक्त की रोटी कमाने वाले, रोज मजदूरी करने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा जेलों में भरकर नंबर बढ़ाये जा रहे हैं और अपनी पीठ थप-थपायी जा रही है । इसका एक जीता-जागता उदाहरण मैं देना चाहती हूं । हमारे वैशाली जिले के सराय थाने पर कुछ महीने पहले की बात है वहां के थाना प्रभारी द्वारा शराब तो पकड़ा जाता था लेकिन शराब को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता था । उस शराब को उन्होंने माफियाओं के हाथ से बेचने के लिये रखा था, जो पकड़ाने के बाद, उनका नाम विदुर कुमार हैं और उनकी सेवा समाप्त भी की गयी । लेकिन ऐसे लाखों विदुर कुमार हैं, थाना प्रभारी जो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को प्रताड़ित कर रहे हैं शराबबंदी के नाम पर । हमारे क्षेत्र में ऐसे-ऐसे थाने के अधिकारी हैं जो ब्रेथ एनालाइजर लेकर घुमते हैं और बोलते हैं कि आपने शराब पिया है । यदि कोई कह दिया कि हां हमने शराब पिया है तो बोलते हैं जल्दी पैसा निकालो । तो मैं कहती हूं कि शराब पीने वाले यदि शराब पीते हैं तो शराब बिक कहां रहा है । यदि शराब बिक रहा है तो शराब माफियाओं को पकड़िये । शराब माफियाओं को जेल भेजिये लेकिन अभी तक कोई शराब माफिया जेल नहीं गया । करोड़ों-करोड़ का शराब आ रहा है बिहार में, पकड़े भी

जा रहे हैं लेकिन शराब माफिया कौन है, ये करोड़ों रुपये का शराब खरीदने वाला कौन है, पीने वाला लोग पकड़ा रहा है । आज जो लोग कहते हैं जंगलराज, जंगलराज अब एकदम मंगलराज है । जैसे ही वे विपक्ष में गये 2022 की बात मैं कर रही हूं तो पहली घटना मशरख में हुई, शराब पी करके लोग मर गये । लेकिन जब ये इधर होते हैं तब कहते हैं कि शराबबंदी खराब है, जब उधर जाते हैं तो बोलते हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छी है । लेकिन मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह कहना चाहती हूं कि कोई भी कानून पक्ष हो, विपक्ष हो जनहित में बनता है और बिहार की जनता के हित में बनता है । आप कहीं भी रहिये सत्य बोलिये और बिहार के विकास के लिये बोलिये । पुलिस विभाग की स्थिति देख लीजिये । मसौढ़ी में एक लड़की कोचिंग करने जा रही थी, इतना अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि जबरदस्ती उस लड़की के सिर में गोली मार दिया । मसौढ़ी में लड़की जब मजदूरी करने, लकड़ी चुनने जाती है तो महादलित की लड़की को मार दिया जाता है, मारकर फेंक दिया जाता है । ये अपराधी इतना हिम्मत लाते कहां से हैं । जंगलराज की बात करने वाले लोग महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं देते हैं । महिलायें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं । आये दिन कहीं न कहीं महिलाओं पर अप्रिय घटना घट रही है । दूसरी बात, पुलिस प्रशासन के लोग ट्रिपल लोडिंग के नाम पर, जो ग्रामीण इलाका है । गांव में कभी-कभार लोग ट्रिपल लोडिंग होकर जाते हैं चूंकि मुख्य सड़क पर नहीं जाते हैं, एन0एच0 पर नहीं जाते हैं, शहर में नहीं जाते हैं । पुलिस विभाग उनको समझाने और चेतावनी देने के बजाय...

उपाध्यक्ष : आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त है ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट । उनको वे कहते हैं कि पैसा लाओ नहीं तो चालान काटेंगे । इस तरह से पुलिस का अत्याचार बढ़ा हुआ है । महोदय, मैं भवन निर्माण पर दो शब्द कहना चाहती हूं कि भवन निर्माण में जितनी खामियां हैं, जितने घटिया मेटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, उसका जीता-जागता उदाहरण बिहार विधान सभा के सदस्यों के लिये बनाया गया आवास है । कोई भी जाकर के देख सकता है । एक कमेटी गठित करके आप उसकी जांच करवा सकते हैं क्योंकि अभी ही वहां पर डैम्प लग रहा है, बिजली की स्थिति खराब है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : जी माननीय उपाध्यक्ष महोदय बस दो मिनट । हमारे विधान सभा क्षेत्र में आई0टी0आई0 कॉलेज का कल उद्घाटन हुआ । जैसा कि आप भी एक सदस्य

हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय और बिना विधायक के अनुशंसा के कोई काम नहीं होता है लेकिन अपराधियों के निकम्मापनी, अपराधियों की मनोवृति सही नहीं है जनप्रतिनिधि के लिये ...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जायें ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : ये लोग क्या करते हैं कि विडियो कॉन्फ्रेसिंग से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन इसलिये करवाते हैं कि उसकी कमियों को उजागर नहीं किया जाय । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री जय प्रकाश यादव जी ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि आप निर्विरोध निर्वाचित होकर इस आसन को ग्रहण किये हैं । तत्पश्चात् मैं सदन के नेता, अपने दोनों उप मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचेतक जनक सिंह जी को धन्यवाद देता हूं और अपने क्षेत्र की महान जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अमूल्य वोट देकर मुझे इस सदन में भेजा है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन मेरे लिये सौभाग्य का दिन है कि आज जो यह बजट मंत्री जी पेश किये हैं वह सन् 1990 में पहली बार इस सदन में जीतकर के आये उस वक्त मैं वहां पर थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित था और आज लगातार 34-35 वर्षों तक इस सदन के सदस्य रहे हैं और विभिन्न विभागों को संभालते हुये तब से ही ऊर्जा विभाग को संभालते आ रहे हैं । चाहे आदरणीय लालू जी का शासनकाल रहा हो या एन0डी0ए0 का शासनकाल रहा हो या महागठबंधन का शासनकाल रहा हो । सभी कालों में निर्विवादित व्यक्तित्व के एवं ईमानदार छवि के द्योतक माननीय मंत्री जी की सोच, दूरदर्शिता एवं दीर्घकालिक योजना बनाने के लिये माननीय मंत्री जी प्रसिद्ध हैं, द्योतक हैं और आज का यह बजट जो ऊर्जा विभाग का बजट है वह भी इनके दूरदर्शी दृष्टि एवं दीर्घकालिक योजना के आधार पर आने वाले समय में बिहार को आत्मनिर्भर बिजली के उत्पादन में बनाने वाला यह बजट है । माननीय उपाध्यक्ष जी इस बजट में प्राकृतिक ऊर्जा का स्त्रोत जो अक्षय भंडार हमारा सोलर लाईट है, उनको प्राथमिकता एवं बढ़ावा दिया गया है । (क्रमशः)

टर्न-18/राहुल/23.02.2024

श्री जय प्रकाश यादव (क्रमशः) : कजरा, लखीसराय में सोलर ऊर्जा पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है और इंटीग्रेटेड रूफटॉप पावर प्लांट को भी स्थापित करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है । खासकर के निजी क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा दी गयी सहायता

राशि के साथ-साथ 25 परसेंट सब्सिडी बिहार सरकार भी दे रही है तो इस तरह से यह बजट दूरगामी बजट है और इसकी प्रशंसा मैं जितनी करूं वह बहुत कम है । हमारे माननीय मंत्री जी ऊर्जा विभाग के साथ-साथ गृह विभाग के भी प्रभारी मंत्री हैं और माननीय मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के कारण गृह विभाग में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ढांचेगत विकास पर बहुत सारे कार्य किये गये हैं । सरदार पटेल भवन देश का उत्कृष्ट पुलिस मुख्यालय बना है जिस पर से हवाई जहाज उड़ने की भी पूरी व्यवस्था है । इसी प्रकार राजगीर में 137 एकड़ के भूखंड पर देश की सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट पुलिस एकेडमी बनी है जहां पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है । पुलिस आधुनिकीकरण के भी बहुत कार्य हुए हैं । एन0टी0सी0सी0 परियोजना के तहत हर चीज को ऑनलाईन किया गया है । आज हम एफ0आई0आर0 से लेकर के सनाह और केस की प्रगति की भी जानकारी उस एप से डाउनलोड करके ले सकते हैं । प्राय: सभी थानों को इस परियोजना से जोड़ दिया गया है और यही नहीं इस परियोजना का लाभ आम लोगों को मिले इसके लिए जनसेवा मिशन स्टार्ट किया गया है जिसकी तरह नागरिकों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर के इसका लाभ उठाने का, जहां से हम आप करेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, हम आप पारंपरिक लोगों का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको इस तरह से किया जा रहा है । एक मुस्कान एप पर भी सरकार काम कर रही है जिसके तहत खोये हुए मोबाईल, चोरी हुए मोबाईल को बरामद करके वापस किया जा रहा है इसी तरह से पुलिस विभाग के द्वारा एक चक्रा एप बनाया गया है जिसमें जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका डिजिटल डोजियर तैयार किया गया है और सारे क्रिमिनल्स का डिजिटल डोजियर उसमें रखा गया है । अगर आप सी0सी0टी0वी0 कैमरे पर कहीं किसी अपराधी को देखते हैं तो उसकी फोटो डाउनलोड करके अगर आप उस एप पर डालते हैं तो क्रिमिनल्स की सारी डीटेल्स आपको मिल जायेगी । इस तरह से हमारे विभाग द्वारा गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे कार्य किये गये हैं । आप वर्ष 2005 के बाद की स्थिति देखें । उस वक्त से काफी पद सृजित करके बहालियां की गयी हैं और पुलिस बल की संख्या उस समय में 42 हजार थी और आज पुलिस बल की संख्या 1 लाख 10 हजार हो गयी है तो जितने भी थानों में बढ़ोतरी हुई है महिला थाना हर जिले में बनाया गया है, अनुसूचित जाति-जनजाति थाना हर जिले में बनाया गया है, साइबर थाना हर जिले में बनाया गया है, जन थाने भी बनाये गये हैं तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पुलिस के आधुनिकीकरण पर काफी खर्च किया गया है । बहुत प्रयास किये गये हैं और अपराध कंट्रोल भी हुआ है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त है ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं विधान सभा के पिछले सत्र में भी बोला था कि हमारे राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के नाम पर श्रीकृष्ण आरक्षी बाल विद्यालय बना था जो अब झारखण्ड में चला गया तो क्या जो हमारे एक लाख आरक्षी कर्मी हैं उनके बच्चों को, उनके परिवार के पढ़ने के लिए वह विद्यालय फिर से नहीं गठित किया जा सकता है ? मैंने डी0जी0पी0 साहब से भी इस संबंध में बात की थी तो उन्होंने बताया था कि काफी जटिलता है, भूखंड का एलॉटमेंट कराना होगा और उसका प्रारूप बनाना होगा...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, एक मिनट । मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह पुलिस मैन्युअल अधिकृत करता है और मैं माननीय मंत्री जी को 1196 पुलिस मैन्युअल रूल और परिशिष्ट-91 दिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा कि उसमें किस तरह से हर चीज वर्णित है कि यह निधि हमारे पुलिस विभाग की निधि है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री जय प्रकाश यादव : आरक्षी कल्याण समिति द्वारा, निधि द्वारा वह चलता है, उसे फिर से चलाया जा सकता है । माननीय मंत्री जी इस ओर आप ध्यान दें । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संदीप सौरभ जी । आपके पास 8 मिनट का समय है ।

श्री संदीप सौरभ : उपाध्यक्ष महोदय, आज ऊर्जा विभाग पर चर्चा हो रही है और आज समूचे बिहार को यह चिंता है कि क्या मौजूदा बिहार सरकार इतनी ऊर्जाहीन हो गयी है कि सदन में तीन-तीन बार घोषणा करने के बावजूद एक पदाधिकारी, एक अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहा है । यह बड़ी इंपोर्टेंट चीज हो चुकी है । जब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई बात सदन में कह देते हैं तो वह सदन की संपत्ति होती है और उसको लगातार दरकिनार करते हुए अधिकारी अपना काम कर रहे हैं तब तो हम सरकार को ऊर्जाहीन ही कहेंगे । दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो बची-खुची ऊर्जा सरकार की है उन्होंने शायद जनता के जो सबसे बड़े मुद्दे थे, जिन विभागों में जनता के सबसे ज्यादा सवाल आते थे उनको गिलोटिन में डाल दिया गया है । हमने देखा कि इस बार सत्र के अंदर शिक्षा विभाग को गिलोटिन में डाला गया, स्वास्थ्य विभाग को गिलोटिन में रखा गया और आज जब गृह विभाग पर चर्चा होनी चाहिए थी । समूचे देश के अंदर गृह विभाग और जो देश का गृह मंत्रालय है उसकी क्या स्थिति है । आज उसको भी गिलोटिन में रखा गया है । बहरहाल पिछली सरकार ने इसी सदन में कहा था, माननीय मंत्री जी यहीं पर हैं

इन्होंने कहा था कि बिहार का दुर्भाग्य है कि केन्द्र सरकार बिहार को सबसे ज्यादा महंगे दाम पर बिजली मुहैया करवाती है और आज पलट कर के उधर चले गये हैं तो हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या इस पलटने से उस बिजली की कीमत में थोड़ी-सी घटोत्तरी हुई है, क्या कुछ सस्ती हुई है ? यह बिहार की जनता का जेन्यूइन सवाल है । महोदय, बिजली विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मांगें हैं, सरकार के बिजली विभाग के अंदर जो विद्युत मानव बल काम कर रहा है उनको आउटसोर्सिंग एजेंसियों से मुक्त किया जाय और यह सरकार की ही रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों से मुक्त करके अगर सरकार उनको अपने विभाग के तहत समायोजन कर लेती है और सरकार का विभाग अगर उनको भुगतान करता है तो सरकार को बड़े पैमाने पर इससे आर्थिक बचत होगी लेकिन एजेंसियों को फायदा पहुंचाने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों को रखा गया है । दूसरी मांग है कि गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाय । पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि आर्थिक-समाजिक गणना की जो रिपोर्ट है वह बिहार की स्थिति को दिखा रही है । बिहार के अंदर 34 प्रतिशत आबादी ऐसी है, परिवार ऐसे हैं जिनको 6 हजार से कम आमदनी हो रही है तो वैसे तमाम जो गरीब परिवार हैं उनको 200 यूनिट मुफ्त बिजली सरकार दे । दिल्ली में यह हो सकता है, पंजाब में हो सकता है तो बिहार में भी हो सकता है । यह हम सरकार से कहना चाहेंगे । एक महत्वूपर्ण मामला हम लोगों के क्षेत्र से है और पूरे बिहार का ही मसला है कि बिहार के अंदर यह जो नल-जल योजना चल रही है, कई बार गरीब गांव में, दलित टोलों में शिकायत आती है कि नल-जल योजना जिस बिजली से चल रही थी उसका बिजली बिल बकाया है इसलिए उसका कनेक्शन काट दिया गया है तो सरकार और ऊर्जा विभाग इसका इंतजाम करे कि सरकार अपनी तरफ से उस नल-जल योजना को बिजली मुहैया कराये ताकि गरीबों को पानी पीने के अधिकार से कम से कम न रोका जाय । यह बात हम सरकार से कहना चाहते हैं । महोदय, 15 अगस्त, 2022 स्वाधीनता दिवस था और उस दिन हमने देखा कि देश के अंदर बिलकिस बानो का एक मामला था जिसमें 2002 के दंगों के बाद उनके जो बलात्कारी थे, उनके जो हत्यारे थे उन सबको जेल से बरी किया गया और न केवल बरी किया गया बल्कि माला पहनाकर के उनका स्वागत भी किया गया और उसको गुजरात मॉडल कहा गया ।

टर्न–19/ मुकुल/23.02.2024

उपाध्यक्ष : आप विषय वस्तु पर आइये ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, मैं विषय वस्तु पर ही आ रहा हूं ।

उसको गुजरात मॉडल कहा गया और उसके समानांतर बिहार में हमलोगों ने बिहार मॉडल खड़ा किया था । जहां पर सामाजिक न्याय की बात होगी, जहां पर युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसी की चिंता सबसे ज्यादा दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को हुई कि बिहार मॉडल बहुत ज्यादा चर्चित है तो किसी और मामले के चलते नहीं बल्कि बिहार मॉडल की मांग की मांग सब जगह होने लगी है इसलिए साजिश करके बिहार में सरकारें बदल रही हैं । महोदय, गृह विभाग की बात चल रही है, गृह विभाग का सबसे बुनियादी असूल होता है डैमोक्रेसी और आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री मदर ऑफ डैमोक्रेसी एक शब्द सुने हैं उसको प्रचारित करने में लगे हुए हैं । लेकिन 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चण्डीगढ़ के अंदर जो मेयर का चुनाव हो रहा था, उसमें लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश हो रही थी और यहां पर लोग चिल्ला रहे हैं कि 400 पार, अगर चण्डीगढ़ के मॉडल पर यह देश चलने लगेगा तो 400 पार हम क्या कहें, 543 सीट ये लोग जीत सकते हैं उस पैमाने पर ही अगर चलाना है तो । महोदय, कल एक खबर और आई, ट्विटर का ऑफिसियल ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स उसने पूरी दुनिया को और 8 मिलियन लोग यह देख चुके हैं, उसने पूरी दुनिया को बताया कि भारत की सरकार ट्विटर को लगातार यह धमकी दे रहा है कि आप फलां–फलां विषय ऊपर जो भी ट्विट जाता है या फलां–फलां व्यक्ति जो ट्विट करते हैं उनको डिलीट कीजिए वरना आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको जेल में डाल देते हैं । ट्विटर यह कह रहा है कि हम न चाहते हुए भी कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जा रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष की तमाम आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है । हमने देखा कि किसान आंदोलन, वहां केवल सरकार की तरफ से हमले नहीं चल रहे हैं, सब गृह विभाग का मामला है, हमले केवल नहीं चल रहे हैं बल्कि उसको बदनाम करने की भी लगातार साजिश चल रही है । कल जब देश पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे, क्योंकि जब कश्मीर में उनका कार्यकाल चल रहा था उस समय उन्होंने देश में 300 करोड़ रुपये के एक घोटाले को उजागर किया था और इसलिए जो व्यक्ति अस्पताल में है उसके घर पर सी0बी0आई0 का छापा पड़वाया गया । महोदय, आज की खबर है कि जो

इलेक्टॉरल बॉन्ड का जो खेल इस देश में चल रहा था, उसमें एक रिपोर्ट सामने आई है कि 30 वैसी कम्पनियां जिनके ऊपर ई0डी0 और सी0बी0आई0 की जांच चल रही थी, जांच के दौरान.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषय वस्तु पर आइये ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, मैं विषय वस्तु पर ही आ रहा हूं । जांच के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 335 करोड़ रुपये इलेक्टॉरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा में दिये और फिर ई0डी0 और सी0बी0आई0 हट गया । सामान्य प्रशासन विभाग चूंकि एक मसला है तो दो महत्वपूर्ण सवाल हम सामान्य प्रशासन विभाग में रखना चाहते हैं । एक तो यह है कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास मात्र 2 मिनट का समय है ।

श्री संदीप सौरभ : जी महोदय । सरकार ने बी0पी0एस0सी0 की जो अपर एज लिमिट रखी हुई है वह 37 साल है । पूरे देश के अंदर बिहार एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पर बी0पी0एस0सी0 में इतनी कम उम्र सीमा रखी गई है । कोरोना के बाद सभी राज्यों में इसको बढ़ा दिया गया है, 40 साल, 42 साल और 45 साल तक गया हुआ है । बिहार में कोरोना से पहले की जो 37 साल उम्र सीमा रखी गई थी वही रखी गयी है। इसलिए लिए हम सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि बी0पी0एस0सी0 की जो उम्र सीमा है उसको बढ़ाया जाय । इसी तरीके से बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वर्ष 2014 की बहाली है और सीटों को खाली रखने के बावजूद 1778 योग्य अभ्यर्थी अभी सड़कों पर भटक रहे हैं उनके साथ न्याय किया जाय, हम यह मांग रखना चाहते हैं । महोदय, गृह विभाग से संबंधित एक मामला है कि गृह विभाग में एक मामला सरकार का ही गजट है संकल्प संख्या-524, जिसके तहत जे0पी0 सेनानियों को सम्मान देने के लिए सरकार ने सलाहकार परिषद् गठित करने की बात की थी, लम्बे समय से बिहार के अंदर कोई सलाहकार परिषद् का गठन नहीं हुआ है, इसके चलते जो जे0पी0 सेनानी हैं, भूमिगत अथवा फरार जे0पी0 सेनानी हैं या आंदोलन में उनके सहयोग करने वाली जो महिलाएं हैं इनको प्रशस्ति पत्र नहीं मिल रहा है और इनको सम्मान नहीं मिल रहा है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अब अपनी बात को समाप्त कीजिए ।

श्री संदीप सौरभ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल अपना आखिरी मुद्दा रखना चाहता हूं । हमने पिछले साल सदन के अंदर एक बात रखी थी कि दानापुर दियारा, उसके तीन पंचायत को छपरा में सिफ्ट कर दिया गया है, काशीमचक, मानस और पानापुर जबकि जिला समाहरणालय सोनपुर के पत्रांक-280/21 इसके अनुसार इन तीनों पंचायतों को ओ0पी0 बनाकर के दानापुर में शामिल किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, सरकार ने उस समय भी आश्वासन दिया था और हम आज भी सरकार से कह रहे हैं कि उन तीनों पंचायतों को दानापुर में सिफ्ट करवा दीजिए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती संगीता कुमारी ।

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । महोदय, आज ऊर्जा विभाग, समाज कल्याण विभाग अन्य ऐसे विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । मैं अगर ऊर्जा विभाग की बात करूं और सरकार इतना बड़ा बजट लेकर ऊर्जा विभाग में आती है तो मैं एक बात जरूर कहूंगी कि मोहनिया विधान सभा की और सुरक्षित सीट की मैं विधायक हूं और मेरे पास ऊर्जा से संबंधित ऐसे मामले आते हैं, ज्यादा मामले बिजली बिल की समस्या को लेकर आते हैं । मैं ऐसे निर्धन परिवार की व्यथा को सुनती हूं जो एक झोपड़ी में रहते हैं और उनको जो बिजली बिल आती है वह लाख/डेढ़ लाख की आती है । मैं उनको जानती हूं और उनकी व्यथा को समझती हूं और देखती हूं कि ये तो अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे हैं तो कहां से ये इतना बिजली का बिल देंगे तो मैं सरकार से यह मांग करती हूं कि जो बी0पी0एल0 कार्डधारी हैं, जो अत्यंत निर्धन परिवार के हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलॉन्ग करने वाले परिवार के लोग, वैसे लोग जिनका बिल इतनी ज्यादा राशि में आई हुई है उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि उनके प्रति सहिष्णुता और दया दृष्टि दिखाते हुए उनका जो बिजली का बिल है उसके माफी के लिए अगर सरकार की तरफ से कोई प्रावधान आता है, अगर कोई काम किया जाता है तो यह निश्चित तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी और कहीं न कहीं मानवता भी यहां पर प्रस्फुटित और पल्लवित होगी । मैं बात करना चाहती हूं मोहनिया विधान सभा में सरकार की जो योजना है मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत जो अशोक बिल्डकॉन ने जो काम किया है, मैं इस कम्पनी के काम की जांच कराने की भी मांग करती हूं कि आधे-अधूरे काम को क्षेत्र में छोड़ दिया गया है और जब मैंने विभाग के पदाधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैडम हो जायेगा, हो जायेगा । इसलिए मैं सरकार से यह मांग करना चाहती हूं कि जितने लोग हमारे यहां पर काम कर रहे हैं और अभी फिडर की बाइफरकेट का जो काम चल रहा है बजाज कम्पनी के द्वारा, वहां पर वह काम इतना स्लो चल रहा है, मन मुताबिक चल रहा है और गलत काम किया जा रहा है । इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूं कि इन कम्पनियों के काम की जांच कराई जाय और उसके अनुसार काम किया

जाय । महोदय, समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग में अगर मैं मनरेगा के काम की बात का जिक्र करना चाहूं तो मुझे लगता है कि मनरेगा सिर्फ, मजदूरों की बात करनी चाहिए तो मजदूरों से जाकर पूछ लिया जाय कि उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जमीनी हकीकत है, चाहे आवास की बात हो, जब हमलोग गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि पक्के मकान वाले को मकान दिया गया है और दलित महिला और निर्धन महिला हमारी ऊंगली पकड़कर अपनी झुग्गी-झोपड़ी दिखाती है और कहती है कि हमने अप्लाई किया है लेकिन हमारे पास उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है वैसे लोगों का नहीं किया गया । इसलिए मैं यह भी मांग करना चाहती हूं कि इसकी जांच की जाय कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो आवास मुहैया कराया गया है इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है और वैसे निर्धन परिवार को छोड़ दिया गया है । अगर मैं शौचालयों की बात करूं तो शौचालयों में तो यही आता है कि उन्हें शौचालय बनाने के लिए कहा गया लेकिन वे गांव की महिलाएं उनकी राशि के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाती रहती हैं और दर-दर भटकती रहती हैं और कहती हैं कि हमें शौचालय का तो पैसा ही नहीं मिला और जो इंट्रेस्ट पर सूद पैसा ली होती हैं उसके लिए वे भटक रही होती हैं और कहती हैं कि उस पैसे को हमने सूद पर लिया हुआ था और उसका इंट्रेस्ट बढ़ता जा रहा है, यह स्थिति गरीबों, दलितों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है और समाज कल्याण विभाग का भी है । समाज कल्याण विभाग में आंगनबाड़ी सेंटर्स की हम बात करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आंगनबाड़ी के जो पदाधिकारी हैं, जो सी0डी0पी0ओ0 हैं उनका मन बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है । अगर मैं पोषाहार की बात करूं, मैं कहना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी का काम है कि जीरो से 6 वर्ष तक के बच्चे कुपोषण के शिकार न हों इनके लिए सरकार के द्वारा यह योजना चलाई जाती है । लेकिन न तो गर्भवती महिलाओं के लिए कोई काम किया जाता है, सेंटर्स नहीं चलाये जाते हैं । सी0डी0पी0ओ0 के द्वारा सिर्फ और सिर्फ भारी अनियमितता बरती जाती है, यह पूरे बिहार की यथास्थिति है और अगर मैं मोहनिया विधान सभा का जिक्र करना चाहूं तो मेरे मोहनिया और कुदरा प्रखंड में जब हम आये दिन आंगनबाड़ी सेंटर्स का अवलोकन करते हैं, हमारे यहां के पदाधिकारी भी जाते हैं, मीडिया की सुर्खियां बनती हैं कि सेंटर्स नहीं खुला, बच्चों का मैन्यू के अनुसार खाना नहीं बनता है ।

टर्न–20/यानपति/23.02.2024

श्रीमती संगीता कुमारी (क्रमशः) : महोदय, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि यह सब ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिनपर समाज के अंतिम पायदान के लोगों को लाभान्वित करने के लिए ये योजनाएं चलती हैं । तो मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि सरकार इन चीजों की जांच भी कराये और इन चीजों पर कड़ा ऐक्शन भी ले ताकि यह मैसेज जाये पूरे बिहार में कि इस तरह की हरकत कोई पदाधिकारी न कर पाये और जब पदाधिकारी नहीं करेंगे तभी शासन और व्यवस्था सुदृढ़ होगी । मैं गृह विभाग की अगर बात करना चाहती हूं कि अल्पसंख्यक कल्याण भी हो गया ऐसे कब्रिस्तान हमारे यहां क्षेत्र में हैं जब मैं वर्कर की बात करूं कि जो विवाद होते रहते हैं, आयेदिन विवाद होते रहते हैं तो मैं सरकार से यह मांग करती हूं कि कब्रिस्तान घेराबंदी में सेन्सिटिवली उसको काम कराया जाय, कोई ऐसा विवाद न हो, उससे पहले ही यह काम करा लिया जाय । बस, यही कहूंगी और हमारे यहां जो मद्य निषेध काम करता है मैं चेकपोस्ट की बात करूं ऐसे ही प्रतिमा जी ने सही बात कही कि जितने शराब पकड़ा जाता है सभी थाने में रखे होते हैं उसके बाद पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जो वहां पर जो काम करते हैं चेकपोस्ट पर उनके द्वारा भी भारी अनियमितता जताई जाती है । मैं सुरक्षित सीट से आती हूं, मुझे लगता है कि पदाधिकारियों को कोई सुध नहीं होती है, न कोई डर होता है और अगर अनुसूचित जाति और जनजाति की मैं बात करना चाहूं तो इतना जरूर कहूंगी कि हमारे क्षेत्र में हमारा कैमूर जिला और जो 19 प्रतिशत की दलितों की आबादी जो जातीय जनगणना में सामने आई है, विद्यालयों की भी स्थिति देख लीजिए जितने आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजातियों के, विद्यालयों में लोग रखे जा रहे हैं जो गार्ड और स्वीपर का काम करते हैं जो उनकी पेमेंट, उनकी भारी शिकायत, आप जांच करवा लीजिए कैमूर जिले में उनकी पेमेंट जितनी है उससे पांच हजार तक ही दिया जाता है । और जब यह आते हैं आउटसोर्सिंग के काम पर कैमूर जिले में मैं कहूंगी कि जांच करायी जाय । महिलाओं के लिए, दलित परिवार की बच्चियों के लिए, इसलिए आग्रह करना चाहती हूं कि समाज के अंतिम पायदान के लोगों के लिये सरकार का एक दृष्टिकोण हो और यह हिमाकत कोई न करे कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति के बच्चों को जो आप प्रावधान दे रहे हैं उसपर हमारे यहां कुदरा में भी विद्यालय अनुसूचित जाति का विद्यालय बना है जिसके भवन की जांच कराने की मैं मांग करती हूं, जांच कराकर देख लीजिए उसके भवन की क्या दिक्कतें हैं, मैटेरियल की कमी है वहां पर जो राशन मिलता है, वहां पर जो खाना मिलता है,

बच्चों को सही रूप से खाना नहीं दिया जाता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहूंगी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के साथ अगर सरकार इतनी बड़ी राशि देती है और इसका यदि सही रूप से कार्यान्वयन नहीं होता है तो निश्चित तौर पर वह कहीं न कहीं पिछड़ेंगे और दलितों की स्थिति समाज में, देश में क्या है और दलित कितने डरे-सहमे रह रहे हैं यह कहीं से छिपी हुई नहीं है । तो मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि कहीं भी देश में उनकी विश्वसनीयता, चाहे समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों उनकी विश्वसनीयता पर किसी भी प्रकार का, सरकार को किसी भी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए और दलितों का उत्थान किये बिना न देश तरक्की करेगा, न हमारा समाज तरक्की करेगा । किस भारतीयता की बात करते हैं आप, किस राष्ट्रीयता की बात करते हैं और किसी भी जाति को किसी भी भारतीय व्यक्ति को सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है । एक किसी का शेर है कि :-

''यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है
यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है,
इसकी नदी-नदी ये गंगा है, इसके कण-कण में शंकर है,
हम जियेंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिये,
और मरने के बाद जब गंगा नदी में हमारी अस्थियां बहेंगी
तो कान लगाकर सुनेंगे तो एक ही आवाज आएगी,
भारत माता की जय-भारत माता की जय ।''

तो इसलिए किसी की भी भारतीय व्यक्ति के किसी भी जाति किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति की भारतीयता का सर्टिफिकेट कि देश में ऐसा माहौल न किया जाय और जो हमारे गुलदस्ते हैं अनुसूचित जाति-जनजाति के हों, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लोग हों या मुस्लिम कम्युनिटी से लोग हों सबको समान भाव से देखा जाय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा जी, आपके पास 10 मिनट का वक्त है ।

श्री मुरारी मोहन झा : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आज आपको उपाध्यक्ष चुने जाने पर मैं अपनी पार्टी की ओर से आपको हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आज मैं ऊर्जा विभाग के द्वारा पेश किये गये बजट के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया गया इसलिए मैं अपने सभी शीर्षस्थ नेता जिन्होंने मुझे टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का अवसर दिया उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और जनक सिंह जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने मुझे यहां बोलने का मौका दिया । आज उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद आता है वह समय

1990 से 2005 के बीच में और आज का समय तो मुझे एक शेर याद आ गया :-

''बदल दिया बिजली ने जीवन, आगे बढ़ा समाज है
मिली जो बिजली आज है, उसपर बिहार को नाज है ।''

महोदय, वह समय था 1990 से लेकर के 2005 तक का जो बिजली आने का लोग इंतजार करते थे और पूरे लालटेन युग में बिहार को धकेलने वाले, सामाजिक न्याय की बात करनेवाले जिन्होंने समाज के लिये न्याय नहीं किया, अपने और अपने बाल-बच्चों के प्रति जरूर न्याय किया । कारण, उस समय की जो स्थिति थी बिजली की, जिसका जितना भी वर्णन किया जाय, सारे समाज और बिहार के लोग भी अन्यत्र जो रहते थे वह कभी बिहार आना नहीं चाहते थे । कारण, यहां रहने के लिये न उनको पंखा मिल पाता था, न सड़क मिल पाती थी । किसी भी महकमे में आप चले जाइये, लोग सुरक्षित नहीं थे । लाखों के लाख लोग यहां से पलायन कर गये उनके शासनकाल में जो बाहर चले गये वह सामाजिक न्याय की बात करते हैं । महोदय, मैंने देखा है, पूरे समाज ने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है पूरे देश ने देखा है कि जो लोग अपने को गरीब का नेता बताकर झूठा जनाधार प्राप्त कर और जो बिहार के साथ छल करने का काम किया मैं जिस जाति की बात करता हूं और जिस जाति के लोगों ने उनको अपने कपार पर बैठाया मैं उन जाति को सतर्क करना चाहता हूं । महोदय, आज जो एक चौकीदार के घर में रहते थे और मुख्यमंत्री बनाने का मौका यहां की बिहार की जनता ने दिया और उसका नतीजा है कि आज वह 50,000 करोड़ के मालिक हैं महोदय ।

(व्यवधान)

हम जाति के लोग को सतर्क कर रहे हैं, जाति के लोग को जगा रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय-वस्तु पर अपनी बात रखें ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, आज चहुंओर विकास झलक रहा है । महोदय, चाहे ऊर्जा के मामले में हो, बिजली 24 घंटे पूरे प्रदेश में खासकर जिला हेडक्वाटर में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है और देहातों में भी मैंने देखा है कि 20 से 22 घंटे बिजली निरंतर उपलब्ध होती है । महोदय, आज समाज में खुशी का वातावरण है, खुशी का माहौल है । निश्चित रूप से लोग जिस शासन का इंतजार कर रहे थे ।

टर्न-21/अंजली/23.02.2024

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप आसन की ओर देख कर बोलिये ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, कुछ उपलब्धियों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा । महोदय, राज्य में आर्थिक विकास में ऊर्जा का विशेष महत्व है । महोदय, मुझे आप सबों को जानकारी देते हुए यह खुशी हो रही है कि वर्ष 2012 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड पुनर्गठन के उपरांत ऊर्जा विभाग निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है । महोदय, घर-घर बिजली के लक्ष्य की उपलब्धि के साथ-साथ कृषि कार्य हेतु विद्युत संरचनाओं का निर्माण हुआ है जिस कारण बड़ी संख्या में नए कृषि पंप सेटों तथा पुराने डीजल चलित कृषि पंप सेटों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है । महोदय, फिलहाल प्रदेश में दो करोड़ उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति की जा रही है । महोदय, वर्तमान में राज्य के शहरी क्षेत्रों में औसतन 23 से 24 घंटे बिजली उपलब्ध है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्धता से लोगों का जीवनस्तर ऊपर उठा है । राज्य के आर्थिक विकास के साथ-साथ विद्युत की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है । विद्युत की अधिकतम मांग नई ऊंचाइयों को छूते हुए विगत 25 जुलाई, 2023 को 75 से 76 मेगावाट तक पहुंच गया है जिसे वर्ष 2024-25 तक 8500 मेगावाट से अधिक हो जाने की संभावना है । राज्य सरकार के सात निश्चय-2 में शामिल हर खेत तक सिंचाई का पानी को सफल बनाने की दिशा में ऊर्जा विभाग द्वारा कृषि कार्य हेतु विद्युत संरचना के निर्माण के साथ-साथ डेडिकेटेड फीडर का निर्माण किया जा रहा है तथा सिंचाई हेतु कृषि पंप सेटों को विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है । चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 के अंतर्गत लगभग 4.80 लाख नए कृषि विद्युत कनेक्शन देने की योजना है । उपभोक्ताओं को त्रुटिरहित विपत्र उपलब्ध कराने की दिशा में स्मार्ट प्री-पेड मीटरों का अधिष्ठापन किया जा रहा है । महोदय, बिहार में विद्युत की उपलब्धता लगभग 9 हजार मेगावाट है जिसमें 2486 मेगावाट बिजली नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है । भविष्य में बांध का एक एवं बक्सर तथा नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर स्टेशन की दो-दो निर्माणाधीन इकाइयों से बिहार को लगभग 2099 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी । महोदय, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा, लखीसराय एवं पीरपैंती भागलपुर में ताप विद्युत केंद्र के स्थान पर लगभग 450 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण का निर्णय लिया गया है । वर्तमान में कजरा में 1810.37 करोड़ की लागत से बैटरी स्टोरेज प्रणाली के साथ 185 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा परियोजना का अधिष्ठापन किया जा रहा है । इसके

अतिरिक्त राज्य में नहरों के किनारे एवं ऊपर भी सौर ऊर्जा, विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है । एक नई पहल के तौर पर राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल राजगीर, बोधगया, पटना शहर के कुछ हिस्सों को परंपरागत ऊर्जा के स्थान पर 24 घंटे हरित ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । इसके लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 210 मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति हेतु एकरारनामा किया गया है । इसके अंतर्गत दिन में सौर ऊर्जा के माध्यम से तथा सूर्यास्त के बाद अगली...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री मुरारी मोहन झा : एक मिनट महोदय । मंत्री महोदय से मैं कुछ कहना चाहता हूं-

''कुछ गड़बड़ियां सितम न ढाए,
हर गरीब यह सेवा पाए,
ब्याज का पैसा माफ हो जाय,
समय-समय से बिजली घर आए,
कहां कोई एतराज है ।''

एक और है महोदय ।

''बिजली से जो जान गंवाए,
उस पर शासन रहम दिखाए,
चार लाख वह रकम उठाए,
अपना उजड़ा चमन बसाए,
जन-जन की यह आवाज ।''

धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति देवी । तीन मिनट का समय आपके पास है ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि हमारा कुछ और समय बढ़ाया जाय क्योंकि अनुदान सत्र है इसमें बहुत ऐसी बातें हैं जो सरकार को शामिल करना चाहिए जिससे सरकार के विकास में गति मिले इसलिए हमें समय देने की कृपा की जाय । हम थोड़ा ही बोलेंगे, कुछ सरकार की उपलब्धि की कॉपी है उसे आप सब्मिट कर लीजिए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सरकार के द्वारा अनुदान बजट के पक्ष में उपर्युक्त विषयों पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे 2010 में लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में लाने का काम किया, साथ ही मैं आज अपने दल के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी एवं दल के

राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं और अपने क्षेत्र की जनता को भी मैं हृदय से नमन करती हूं । महोदय, राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु निम्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं । आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 66 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अभी तक 21 विद्यालय संचालित हैं, कुल क्षमता 25600 है जिसमें अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए पठन-पाठन, पोषण, खान-पान के साथ-साथ सभी दैनिक जरूरतों की आपूर्ति की जा रही है । सामान्य विद्यालयों में विभाग द्वारा अलग से छात्रावास का भी निर्माण हो रहा है । वर्ष 2024-25 में 18 करोड़ रुपये का बजट प्रावधानित है । महोदय, पूरे बिहार में अब तक महादलितों के विकास हेतु 2021 से 2022-23 तक का कुल लक्ष्य 5513 के विरुद्ध अब तक 4378 सामुदायिक भवन सह वर्क शेड का निर्माण कराया जा चुका है । यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है । महोदय, मैं सरकार के और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने के विकास मित्रों में एवं टोला सेवकों का मानदेय बढ़ाकर के हमारे महादलित समाज का गौरव बढ़ाया है । महोदय, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के अंदर तथा राज्य के बाहर सरकारी शिक्षण संस्थान मान्यता प्राप्त है । गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को योजना के तहत अब तक कुल 350 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है । छात्राएं सरकार के इस पहल से काफी खुश हैं । महोदय, संभवतः विद्यार्थियों के लिए यह योजना 2011 से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लागू की गई थी । सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि वर्ष 2011 एवं वर्ष 2018 के बीच में जितने भी छात्र-छात्राओं ने राज्य के बाहर एवं राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण किये हैं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उन्हें अभी तक प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति भुगतान नहीं किया गया है, जल्द से जल्द उन्हें भुगतान कराने की कृपा की जाय । इस संबंध में मैं पूर्व में भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करा चुकी हूं । निर्वाचन विभाग, महोदय, इस विषय पर मैं आपकी अनुमति से कहना चाहती हूं कि 2005 के पहले समाज के अत्यंत घर कमजोर वर्गों के लोग चुनाव के वक्त अपने-मनपंसद को उम्मीदवार को अपना मत नहीं दे पाते थे । (क्रमशः)

टर्न–22/आजाद/23.02.2024

..... क्रमशः .....

श्रीमती ज्योति देवी : असामाजिक तत्वों के लोग उन्हें बूथ तक जाने ही नहीं देते थे और यदि किसी ने हिमाकत की तो उन्हें भुगतना पड़ता था । किन्तु निर्वाचन आयोग की शक्ति और वर्तमान सरकार की नीति और सुशासन की वजह से लोग अब निर्भीक होकर मतदान करते हैं और अपना मनचाहा उम्मीदवार चुनते हैं । किन्तु अभी भी वैसे तत्व जीवित हैं । सुषुप्ता अवस्था में सावधान रहने की आवश्यकता है । महोदय, मैं कुछ आवश्यक सुझाव देना चाहती हूँ और सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इसे गंभीरता से लें । आज भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि स्थानीय लोग साजिश के तहत इस गांव के महादलित को दूर तीन–चार कि0मी0 दूर के बूथ पर .....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती ज्योति देवी : थोड़ा सा है सर । इस बूथ पर और गांव के महादलित के इस बूथ पर नाम जोड़वा दिया गया है । अगर पत्नी का नाम इस बूथ पर है तो पति का नाम किसी और बूथ पर है । इस तरह से महादलितों को छितर–बितर कर दिया गया है । इसपर मैं आपके माध्यम से निर्वाचन पदाधिकारी महोदय से और सरकार से निवेदन करती हूँ कि इसको तत्काल जॉच करके इसमें सुधार किया जाय ।

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, इसको आप प्रोसिडिंग्स का पार्ट बनवा दीजिए, लेकिन कुछ सुझाव है सर, इसपर मैं आग्रह करती हूँ जिसको सुन लिया जाय । मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2–2 लाख रू0 देने का प्रावधान है, कम समय सीमा रहने के कारण आय बनाने में समय लग गया, बहुत लोग नहीं बना पाये हैं । इसलिए मैं आग्रह करती हूँ कि महादलितों को .....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप बैठ जायं । माननीय सदस्य श्री अजय कुमार अपना भाषण प्रारंभ करें ।

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, आप इसे प्रोसिडिंग्स का पार्ट बना दीजिए, मैं आपसे आग्रह करती हूँ । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस सदन की ओर बिहार की पूरी जनता देख रही है । चूँकि एक हास्यास्पद विषय बन गया है, जनता इसको समझना चाहती है कि कार्यपालिका ऊपर है या विधायिका ऊपर है । विधायिका जो नियमन देती है, कार्यपालिका उसको कार्यान्वित करती है । लेकिन

बीते दो दिनों से हम देख रहे हैं कि विधान सभा सदन के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री जी विधायिका के तरफ से नियमन दे रहे हैं, सरकार अपना आदेश जारी कर रही है लेकिन कार्यपालिका ठेंगा दिखा रही है । मतलब क्या है, क्या बिहार की जनता इसको इस रूप में समझें कि मैच फिक्सिंग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते रहे और उसको यह कह दिये कि जो तुमको मर्जी हो, वह करो । बिहार के अन्दर अराजकता का माहौल पैदा हो जायेगा । कुछ नहीं बचेगा, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में अगर सीमा नहीं रहेगी, कुछ नहीं बच सकता है, मैं इसको संज्ञान में आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को कहना चाहता हूँ कि सदन की गरिमा को बचाने के लिए आपको सामने खड़ा होना होगा ।

महोदय, आज ऊर्जा विभाग का जो कटौती प्रस्ताव है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । बिहार जो है, एकदम बिल्कुल गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य है लेकिन इस वक्त जो बिजली का रेट है, वह रेट हम समझते हैं कि 1 से 100 तक 7.57 रू0 देने पड़ेंगे अभी बढ़ने के बाद और फिर 101 से लेकर के उससे ऊपर जो है 9.10 रू0 प्रति यूनिट देने पड़ेंगे । इससे गरीब लोग कैसे बिजली का उपयोग करेंगे । जिस गरीब लोगों के पास खाने के लिए दाना नहीं है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि हर घर को बिजली देना चाह रहे हैं । यह बिजली लोगों के पहुँच से दूर हो जायेगी । दूसरी बात हम कहना चाहते हैं बिजली के क्षेत्र में, आपने स्मार्ट मीटर लगाकर के क्या बताना चाहते हैं, बिजली अधिकार नहीं है क्या? बिजली विभाग को आप पूरे तौर से एक दुकानदार के तौर पर खड़ा कर दिये, मोबाईल से रिचार्ज करो, रिचार्ज जब खतम हो जायेगा, वह बंद हो जायेगा । मतलब क्या है, मतलब है कि आप बिजली आम जनता को और गरीबों को नहीं देना चाहते हैं । जिनके पास पैसे रहेंगे, वो सिर्फ बिजली का इस्तेमाल करेंगे । जिनके पास पैसा नहीं रहेंगे, वे बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे । इसलिए इस सरकार की जो समझदारी है, जो चरित्र है, गरीबों के बारे में में उनकी समझदारियां सही नहीं है, यह उजागर होती है ।

महोदय, आज गृह विभाग के बारे में बताना चाहता हूँ । गृह विभाग का अपना रिपोर्ट है । उनका यह रिपोर्ट है, पटना का हम पढ़ना चाहते हैं पिछले दिनों इनका एक .....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय अब हो गया है ।

श्री अजय कुमार : सर, मैं 30 सेकेंड ले रहा हूँ । सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पटना का जो आपका रिपोर्ट है, पिछले जुलाई में 31 दिनों के अन्दर 30 हत्याएँ हुई और उसके बाद वाहन चोरी के 421 मामले हुए, लूट के 16 मामले हुए, डकैती के 2

मामले हुए, बिहार में सुशासन का राज है क्या ? यह कैसे हो सकता है और आखरी बात मैं कहकर मैं अपनी बात खतम करना चाहता हूँ कि जब बिहार के अन्दर दलितों का, आदिवासियों की हत्या होगी और सरकार सोयी रहेगी तो सरकार के बारे में क्या कहना है ? राजेश हॉसदा, मधेपुरा, मुरलीगंज थाना कांड सं0-451/23, उनकी अपराधियों ने इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वे सिलिंग से फाजिल जमीन जिसका पर्चा उनको मिला हुआ था और वे जोत रहे थे और भू-माफिया ने न सिर्फ उनकी हत्या किया, एक साल पहले उनके पिता जी की हत्या की और अपराधी घुम रहे हैं। सभी अपराधी घूम रहे हैं और वे जिन्दगी और मौत की गुहार लगाकर के उनकी पत्नी जो है, वो घूम रही है । इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ एक आखिरी कि साईबर क्राईम बिहार के अन्दर आज देश में सबसे ज्यादा बढ़ गया और उसके शिकार बिहार में सबसे ज्यादा आज गरीब हो रहे हैं, आम जनता शिकार हो रही है । इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप इसपर नियंत्रण के लिए ध्यान दें । धन्यवाद सर ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुर्यकांत पासवान, आपके लिए दो मिनट का वक्त है ।

श्री सुर्यकांत पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से । महोदय, आज बिजली विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आज बिजली में आपने क्रांति जरूर लाया है लेकिन महोदय, जो व्यवस्था है आपका, आप जिस दिन से बिजली प्राइवेट सेक्टर को दिये हैं, हमारे जो गरीब लोग मानव बल में काम करते हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वे मानव बल जब बिजली के पोल पर चढ़कर के लाईन को ठीक करने का काम करते हैं, उस समय अगर करेन्ट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है तो महोदय, विभाग कहती है कि आप सरकारी सेवक नहीं हैं, आपको किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिलेगी । मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि उसकी मृत्यु उपरान्त उसके आश्रितों को मुआवजा मिलनी चाहिए । महोदय, मैं कुछ पदाधिकारियों की ओर इशारा करना चाहता हूँ, मेरे विधान सभा क्षेत्र बखरी में कार्यालय रहते हुए मंझौल डिविजन से हमारा काम चलता है, मंझौल में अनुमंडल भी है और बखरी में भी अनुमंडल है और बिजली विभाग का ऑफिस भी है लेकिन पदाधिकारी मंझौल में बैठकर के काम करते हैं, कर्मचारी मंझौल में बैठकर के काम करते हैं । हमारे बखरी के आम-अवाम को इससे काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । चाहे बिल से संबंधित सवाल हो या पैसा जमा करने से संबंधित सवाल हो, वहां पर पदाधिकारी जमे हुए हैं .....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, एक मिनट । आपका संरक्षण चाहिए । महोदय, मैं पर्यटन विभाग की बात करना चाहता हूँ, मेरे बेगूसराय जिला में एक कांवर झील है, एशिया महादेश का सबसे मीठे जल का यह झील है । यहां पर पर्यटक आते हैं और यहां पर पर्यटक स्थल की असीम संभावना है महोदय । वहां हजारों-हजार बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी, इसलिए वहां पर पर्यटक स्थल का निर्माण करावें । बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती नीतू कुमारी, आपके पास 5 मिनट का वक्त है ।

श्रीमती नीतू कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऊर्जा विभाग के लिए 11422 करोड़ 68 लाख रू0 का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्थापना मद में 9836 करोड़ 16 लाख रू0 और योजना मद में मात्र 1586 करोड़ 52 लाख रू0 का प्रावधान है । इससे स्पष्ट है कि योजना मद से बिजली में ज्यादा राशि स्थापना मद में सरकार खर्च करना चाहती है ।

..... क्रमशः .....

टर्न-23/शंभु/23.02.24

श्रीमती नीतु कुमारी : क्रमशः महोदय, राज्य में बिजली उपभोक्ताओं में काफी वृद्धि हुई है और बिजली की खपत भी बढ़ गयी है, लेकिन हमें बिजली के लिए केन्द्रीय सेक्टर पर निर्भर रहना पड़ता है । राज्य का अपना कोई पावर प्लांट नहीं होने के कारण हमें एन0टी0पी0सी0 से ही महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है । अतः इसका बोझ गरीब लोगों पर पड़ता है इसपर ध्यान देने की जरूरत है । आऊटसोर्सिंग के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें बहुत तरह की ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है । कृषि फीडर का जो काम चल रहा है कहीं भी पूर्ण नहीं हुआ है, पांच वर्ष से यह काम चल रहा है, लेकिन किसानों को बिजली नहीं मिल रही है । महोदय, स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है उसका अपना कोई औफिस बिहार में नहीं है इसके चलते जो मीटर में कंप्लेन होता है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है । मेरा क्षेत्र हिसुआ है मैं हिसुआ की विधायिका हूँ । वहां मंझवे एक पंचायत है जहां पान की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन वहां गांव में बिजली नहीं है । मैं कई बार प्रयास की कि वहां बिजली जाय पोल गड़ा गया है लेकिन तार के चलते वहां पर बिजली गांव में नहीं जा रहा है उसपर काम होना

चाहिए । जहां ग्रामीण क्षेत्र है पहले 63 के0वी0ए0 का जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था अब कन्ज्यूमर बढ़ गया है जिससे बिजली का बोझ बढ़ गया है इसलिए उसकी एक कमिटी से जॉच कराकर जहां 63 का है वहां 63 रखा जाय और जहां कन्ज्यूमर बढ़ गया है वहां 100 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाने का प्रावधान किया जाय । पिछले बजट सत्र में ही संयोग ऐसा है कि यहां माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बैठे हुए हैं उन्होंने ही कहा था कि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली हमारे बिहार राज्य में मिलती है । मैं भाजपा के लोगों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि अब तो डबल इंजन की सरकार हो गयी है बिहार में तो अब हमलोगों को, किसान भाइयों को, मजदूर लोगों को, गरीब लोगों को कब तक सस्ती बिजली मुहैय्या करायी जायेगी इसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए । ऐसे तो छोटे पदाधिकारी के द्वारा क्षेत्र में बहुत कंप्लेन मिलता है आउटसोर्सिंग द्वारा जो काम कराया जा रहा है उसमें जे0इ0, एक्सक्यूटिव, एस0डी0ओ0 हैं उनके द्वारा अनाप-शनाप बिल दिया जाता है । जब गरीब आदमी का बिल ज्यादा मिलता है हमलोगों के पास आता है तो जब हमलोग फोन एस0डी0ओ0 और एक्सक्यूटिव को करते हैं तो बिल में कुछ कटौती की जाती है । मेरे नरहट का एक मामला है एक नीलू देवी महिला है, वह एक महीना पहले आटा चक्की बैठायी और वह बार-बार लोगों से बोली कि हमको मीटर दे दिया जाय, एक महीना पहले उसको मीटर भी मिला वह अपना मीटर लगा ली, कुछ मीटर में प्रोब्लम हुआ, वह कंप्लेन की तो चुराकर या कैसे बिजली जला रही थी, कई बार वह कंप्लेन कर दी कि मेरे मीटर में प्रोब्लम है इसको देख लिया जाय और छापा मारकर उस गरीब महिला पर साढ़े 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है । मैं चाहूंगी कि इस मामले की अपने स्तर से जॉच कराकर जो दोषी है उसपर कार्रवाई होनी चाहिए । आपलोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान साहब ।

श्री अख्तरूल ईमान : सर, इधर प्रशंसक हैं इधर आलोचक हैं मैं मशवरा देना चाह रहा हूँ और माननीय बड़े गंभीर मंत्री हैं बिजली में तरक्की हुई है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बिजली सबसे ज्यादा महंगी बिहार में बिक रही है और बिजली के नीचे स्तर के जो पदाधिकारी हैं इनमें काफी करप्शन है, बिल में काफी गलती होती है उसको सुधारा जाय । मानव बल जो 24 घंटा ड्यूटी देता है उसके बारे में अगर संवेदनहीनता हो तो ये गरीबों के साथ इंसाफ नहीं है । मेरे क्षेत्र के कुछ मुद्दे हैं अमौर प्रखंड में एक भी एग्रीकल्चर फीडर नहीं है । वहां पर मीरपुर में प्रस्तावित है पहले से हमारा एक पी0एस0एस0 उसको बनवा दिया जाय, जे0इ0 के अवैध

वसूली को बंद कराया जाय और बिजली को सस्ते रेट में किसानों को दिया जाय । अकलियती फलां का जहां तक मामला है अभी जातीय आधारित गणना के मुताबिक सबसे नौकरी में हिस्सेदारी मुसलमानों की है तो इसमें बजट में कुछ हिस्सा ही नहीं बढ़ा और अकलियतों के साथ- सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ तरक्की का दावा अधूरा है । उर्दू का मामला बिहार में दूसरी सरकारी जबान है उर्दू डायरेक्टोरेट में उर्दू मुशविरति कमिटी, उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली अब तक बंद है इसको जारी कराया जाय । जहां तक मामला है लॉ ऐंड आर्डर का बिहार में सिचुएशन बहुत ही गंभीर है चोरी डकैती अपनी जगह पर है, शराबखाने तो शहरों में बंद हो गये हैं, घर-घर मयखाना बन गया है और अफसोस तो इस बात का है कि हमारे छोटे मोटे 5 क्लास के बच्चे 3 क्लास के बच्चे स्मोक करने लगे हैं इसको गंभीरता से देखने की जरूरत है कि बिहार मुस्तकबिल तबाहो-बर्बाद न हो जाय । अभी हमारे पार्टी के दो लीडरों का पिछले दिनों में आरिफ जमाल का सिवान में और असलम मुखिया अबदुस्लाम का मर्डर हुआ है, निर्मम हत्या हुई है । पिछले दिनों औरंगाबाद में माइनोरिटी के लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हुई है । अभी मूर्ति भसान पूजा का काम पवित्र काम है, ईद हो, होली हो लोग गले मिल जाएं, लेकिन ऐसे में कुछ समाज विरोधी लोग होते हैं जो तनाव पैदा करते हैं । अभी जमुई में हुआ या दरभंगा में जो कुछ हुआ है या जो कुछ मोतिहारी में हुआ है इन चीजों पर काबू पाने की जरूरत है। महोदय, मैं दो तीन बात कहूंगा अपने माननीय मंत्री से बड़े गंभीर हैं कि मैं जब सुपौल से होकर गुजरता हूँ तो सुपौल की बिजली देखकर दिल कहता है कि ऐ काश पूरे बिहार में बिजली ऐसे हो जाती तो सुपौल में तो बिजली की तरक्की हुई है । हमलोगों के यहां बिजली के मामले में बहुत पीछे हैं सर, हम चाहेंगे कि इस मामले में जरा डायरेक्शन दिया जाय ताकि इधर का भला हो जाय और मैं अपने कॉमरेड साथी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूँ कि आज गरीबों के मामले में परकैपिटा इनकम जहां ज्यादा है पंजाब में ज्यादा है, दिल्ली में ज्यादा है वहां तो गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिले और जहां 94 लाख परिवार यानी 5 करोड़ आबादी 13 करोड़ में गरीबी की रेखा से नीचे हो वहां के लोगों को आप उनके घर में चिराग नहीं जलना देना चाहते हैं तो फिर गरीबों का उत्थान कैसे होगा । आपने मुझे सच बात को कहने का मौका दिया बहुत-बहुत शुक्रिया ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री लखेन्द्र कुमार रौशन जी ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको बधाई देता हूँ और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ । महोदय,

अपने सदन के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी को और अपने सचेतक जनक सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बोलने का समय दिया । महोदय, आज बिजली का जो बजट है 11422 करोड़ रूपया से अधिक का बजट है और इस बजट के माध्यम से बिहार के लगभग 2 करोड़ उपभोक्ताओं से अधिक को इस बजट के राशि से बिजली एवं अन्य सुविधा मिलती है, लेकिन आश्चर्य इस बात की है कि विपक्ष के साथी केवल कटौती और बजट के विरोध में बोलने के अलावा सकारात्मक सोच लेकर नहीं आते हैं । मैं केवल यह कहूंगा विपक्ष दलों को शिकायत की लत है, विपक्ष दलों को शिकायत की लत है, वर्ना एन0डी0ए0 के राज में सब खैरियत है । महोदय, हम पातेपुर विधान सभा वैशाली जिला के सुदूर देहात से आते हैं और हम समझ रहे हैं जो भी माननीय विधायक यहां हैं कहीं न कहीं सुदूर देहात के इलाके से ही आते हैं । 1990 के दशक में जब बिजली की सुविधा नहीं थी बिहार में कैसी जिंदगी हमलोग जी रहे थे । जो किसान है, जो गरीब है किसी भी समाज का लोग क्यों नहीं हो, जो अपने पदाधिकारी है वे नौकरी तो यहां करते थे, जो किसान थे किसानी कहकर मेहनत करके समर्थ बनते थे, लेकिन बिजली की सुविधा जब अपने बिहार में नहीं थी 1990 के दशक में तो अपने बच्चों को गांव देहात में नहीं रखते थे उसको राज्य से बाहर पढ़ाने के लिए भेजते थे । महोदय, आज बिजली की सुविधा गांव में हो जाने से- मैं धन्यवाद देता हूँ विद्युत विभाग के मंत्री जी को आज बिजली की सुविधा बिहार में हो जाने से गांव देहात में बच्चे की पढ़ाई की सुविधा भी अच्छी हो गयी है, स्कूल की सुविधा अच्छी हो गयी है, लोगों के जीवन बसर करने की सुविधा अच्छी हो गयी है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

लेकिन जब हम सभी विधायक सोकर उठते हैं तो निश्चित रूप से हर विधायक के दरवाजे पर 10-20 ऐसे कार्यकर्त्ता रहते हैं जो कहते हैं कि विधायक जी हमारे यहां ट्रांसफार्मर तो लगा है 16 के0वी0ए0 का अब सरकार ने सुविधा दे दिया है 63 के0वी0 के, 73 के0वी0 के, 100 के0वी0 का, तो ट्रांसफार्मर बदलवा दीजिए और विधायक जी बिजली विभाग के पदाधिकारी को फोन करते हैं कि अमुक जगह का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सरकार ने सुविधा दे दी है बिजली का 100 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगा दीजिए और 24 घंटा के अंदर महोदय ट्रांसफार्मर लग जाता है ।

क्रमशः

टर्न–24/पुलकित/23.02.2024

(क्रमशः)

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : यह बिहार सरकार की उपलब्धि है बिहार के अंदर । महोदय, ये 90 के दशक में जीते थे, 90 के दशक में इनको लालटेन दिखाई दे रहा था । आज बिहार में लालटेन की बत्ती भी दिखाई नहीं देती । अगर किसी विधायक को कह दें कि अपने घरों में लालटेन खोजिये तो धोखे से भी लालटेन मिलने वाला नहीं है इसलिए अब 90 का दशक नहीं है, अब नरेन्द्र मोदी जी का जमाना है । एन0डी0ए0 के एक साथी कह रहे थे यह डबल इंजन की सरकार है और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार के कारण बिहार में चारों ओर विकास हो रहा है । एक साथी कृषि एग्रीकल्चर, कृषि फीडर के विषय में बोल रहे थे, अभी किसानों को 70 पैसा प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली दी जा रही है । मैं बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि अभी कैम्प लगाकर पूरे बिहार में कृषि विद्युत योजना फेज–2 के तहत आज से चार रोज पहले ही बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हमको लैटर भेजा है, उसमें पंचायतवाईज कैम्प लगाकर सरकार कनेक्शन दे रही है और सभी विधायकों को हम समझते हैं ऐसी चिट्ठी गयी होगी कि पंचायतों के अंदर कैम्प लगाकर कृषि विद्युत योजना फेज–2 के तहत कनेक्शन दिया जा रहा है, जो बच गया और किसान को मात्र 70 पैसे बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है । महोदय, जो बी0पी0एल0 धारी है उन्हें मुफ्त में बिजली का कनेक्शन बिहार में दिया गया है । आज दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के माध्यम से जो भी ट्रांसफॉर्मर हैं जो जला हुआ है, जिसका तार जर्जर है, जिसका पोल जर्जर है, उन सब ट्रांसफॉर्मर को चेंज किया जा रहा है । आर0डी0एस0एस0 योजना के तहत, यह बिहार सरकार की योजना है उसके तहत जो भी ट्रांसफॉर्मर, तार में जहां भी गड़बड़ी है, माननीय विधायक जो भी खबर विभाग को करते हैं, वह सबको बतलाई जा रही है । अभी बिहार के अंदर जो भी किसानों को स्मार्ट मीटर लगाकर के बिजली की दर की खपत कैसे कम हो इस पर भी सरकार का एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी निर्णय है । महोदय, बिहार के अंदर हम सब चाहते हैं कि बिहार के किसानों के बच्चे अपने गांवों में पढ़ें, हम सब चाहते हैं कि गरीब के बच्चे अपने गांव में पढ़ें । वे तभी पढ़ेंगे जब उनको सुविधा मिलेगी, जब गांव में बिजली की सुविधा होगी । इसके लिए बिहार सरकार, बिहार के दो करोड़ उपभोक्ताओं को बिजली की समुचित सुविधा शहर में 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 21 घंटे की बिजली देने की सुविधा देने पर आज सरकार

ग्यारह हजार चार सौ बाईस करोड़ से अधिक का बजट लाई है तो विपक्ष के साथी उसका विरोध कर रहे हैं । बजट के विरोध में है क्या आप नहीं चाहते हैं ?

(व्यवधान)

क्या आप नहीं चाहते हैं कि बिहार के गरीबों को बिजली की सुविधा मिलें । आप नहीं चाहते हैं कि बिहार के किसानों को, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश के अंदर केवल चार जाति है । देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में चार जाति है वह है गरीब, दूसरी जाति है किसान, तीसरी जाति है महिला और चौथी जाति युवा है । उन्होंने चार जातियों का नारा दिया और सभी का समुचित विकास हो, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री और एन0डी0ए0 की डबल इंजन की सरकार में लोगों को समुचित सुविधा मिलें ।

अध्यक्ष : अब कंक्लूड करिये ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : अगर कम से कम जनता का हित चाहते हैं तो जो बिजली बिल आया है कम से कम उसका समर्थन कर दें । यदि बिजली बिल का समर्थन नहीं करते हैं तो कल अगर आपके यहां ट्रांसफार्मर खराब होता है, तार बदलना होता है तो आप किस मुंह से पदाधिकारी को कहियेगा । जब आप पैसा ही नहीं दीजियेगा तो किस मुंह से कहियेगा मेरे मित्र ।

(व्यवधान)

अभी एक साथी कह रहे थे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब कंक्लूड करिये ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : महोदय, सिर्फ दो मिनट दिया जाए । अभी एक साथी कह रहे थे अजय भाई । बिहार के लोगों को और देश के लोगों को बिजली से पहले अन्न चाहिए ।

(व्यवधान)

महोदय, जिस साथी ने बोला, बिजली के साथ अन्न चाहिए । आज देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में 81 करोड़ लोगों को और बिहार में 8 करोड़ 53 लाख लोगों को मुफ्त में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अन्न दिया जा रहा है । महोदय, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया गया और बिहार में 53 लाख 34 हजार लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है । महोदय, गरीबों का मुफ्त में इलाज, मुफ्त में घर,

माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी चूंकि ग्रामीण विकास का भी विषय है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के माध्यम से 57 हजार लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है । मैं साथी से निवेदन करता हूँ कि वास्तव में बिहार का विकास चाहते हैं, उज्ज्वल भविष्य के बिहार की कामना करते हैं और 90 के दशक का लालटेन लोगों को याद मत दिलाइये । जो भी आप बचे हैं आप नीतीश कुमार जी और नरेन्द्र मोदी जी के डबल इंजन के एन0डी0ए0 की सरकार है । अब वेपर लाईट का युग आ गया है लालटेन तो अब समाप्त ही हो गया और जो भी बचाकुचा हुआ है वह भी 2024-25 आते-आते बिहार से लालटेन समाप्त हो जायेगी । आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा, अपना पक्ष रखें ।

(व्यवधान)

कोई यहां झूठ नहीं बोलता है । असत्य बोलता है, झूठ कोई नहीं बोलता है । ये जो कह रहे हैं इनको मालूम नहीं है क्या, झूठ बोले कौआ काटे होता है ?

श्री रत्नेश सादा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं ऊर्जा विभाग के बजट भाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समय से पहले 2019 के नवंबर में काम पूरा करके दिखलाया । ऊर्जा ही नहीं, बिहार में जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी विभाग हैं, सब विभाग पर नजर रखकर के ये जो काम करते हैं इसके लिए मैं माननीय मंत्री श्री बिजेन्द्र बाबू जी का धन्यवाद देता हूँ, ग्रामीण कार्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय मंत्री संसदीय कार्य एवं शिक्षा विभाग और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, ऊर्जा वह शक्ति है, छोटे जीव से लेकर के, पेड़-पौधा से लेकर के मानव जीवन और पशु-पक्षियों में सब में ऊर्जा की जरूरत होती है । चाहे मोटर व्हीकल कार हो सब में ऊर्जा की शक्ति होनी चाहिए । अगर जिस चीज में पेड़-पौधे में शक्ति नहीं होगी, मनुष्य में शक्ति नहीं होगी तो वह चीज चल नहीं पायेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरे बिहारवासियों को कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास में, ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम हुआ है । पहले हमलोग ग्रामीण इलाके में रहते थे और वर्ष 2005 से पहले हमलोग डिबिया में पढ़ते थे, लालटेन तो बहुत कम, डिबरी जलाकर पढ़ते थे । आज माननीय नीतीश कुमार और

ऊर्जा मंत्री जी की देन है कि वर्ष 2005 के बाद ग्रामीण इलाके में बिजली पहुंचाकर और हर गरीब परिवार को लाईट से ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में तब्दील हो गया है । आज वर्ष 2023-24 में शहरी क्षेत्र में 23-24 घंटे बिजली रहती है और ग्रामीण क्षेत्र में 21-22 घंटा बिजली रहती है ।

(क्रमशः)

टर्न-25/अभिनीत/23.02.2024

..क्रमश..

श्री रत्नेश सादा : महोदय, विद्युत की अधिकतम मांग की नई ऊंचाइयों को छूते हुए 25 जुलाई, 2023 को 75-76 मेगावाट की क्षमता पहुंच गयी है । 2024-25 में 885 मेगावाट से अधिक बिजली होने की संभावना है । सात निश्चय-2 के तहत हर खेत तक सिंचाई की पानी की व्यवस्था चतुर्थ कृषि रोड मैप में 2023 से लेकर 2028 तक 7.80 लाख नये कृषि विद्युत संबंध देने की योजना है । महोदय, त्रुटि रहित, जो बिल में गड़बड़ी होती है बिजली उपभोक्ता को उसको सुधार करने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने का काम किया जा रहा है । महोदय, बिहार में लगभग बिजली की उपलब्धता 9 हजार मेगावाट नवीनगर से प्राप्त होती है । महोदय, भविष्य में बक्सर नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर से दो फेज निर्माणाधीन इकाइयों का है । महोदय, 2099 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी । महोदय, जल-जीवन-हरियाली में सौर ऊर्जा के उत्पदन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य भर में कजरा, पीरपैंती ताप केंद्र की स्थापना लगभग 450 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण का निर्णय लिया गया है । वर्तमान में कजरा में 1810.37 करोड़ की लागत से बैट्रिक स्ट्रैक्चर प्रणाली के साथ 185 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है । महोदय, राज्य के विभिन्न भवनों के छत पर कैंपस मॉडल के तहत 9.90 मेगावाट क्षमता का ग्रिड कनेक्शन सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापना का कार्य किया जा रहा है । महोदय, जल-जीवन-हरियाली फेज-1 के अंतर्गत राज्य में लगभग 408 प्रखंड कार्यालयों में, 292 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, 482 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन, 33 आई.टी.आई. एवं 781 पंचायत सरकार भवनों तथा अन्य सरकारी भवनों पर कुल लगभग 220 मेगावाट क्षमता का ग्रिड कनेक्शन सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापित किया गया है ।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज गृह विभाग भी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 1974 के आंदोलन में जे0पी0 सेनानियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की और इतना ही नहीं बिहार में अल्पसंख्यक समाज में जो आपसी भाईचारा का

माहौल बिगड़ता था, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से पूरे बिहार में साढ़े आठ हजार कब्रिस्तान की घेराबंदी की गयी है । महोदय, इतना ही नहीं हज यात्रियों के लिए हमारी सरकार ने, नीतीश कुमार ने, पहला राज्य है जिसने हज यात्रियों के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की है ।

(व्यवधान)

पढ़ा हुआ क्यों मान लिया जायेगा । महोदय, आज अल्पसंख्यक समाज को बेहतरीन करने के लिए, उनके मदरसा बोर्ड, जो भी काम है उसके लिए कर रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री ने एस0सी0, एस0टी0 के लिए जो काम किया है वह काबिले-तारीफ है । महोदय, आज बिहार में 40 हजार टोला सेवक को 22 हजार रुपये देकर 5 लाख परिवारों का भरण-पोषण करने का काम किया । शिक्षा से जोड़ने का काम किया और साढ़े 12 हजार विकास मित्र को 25 हजार वेतन देने का काम किया । माननीय मुख्यमंत्री अभियान बसेरा-2 के तहत पांच डिसमिल जमीन क्रय नीति के तहत सरकारी जमीन देने की व्यवस्था की है जो मार्च के बाद से चालू होगा । महोदय, इतना ही नहीं 1 लाख 20 हजार मुख्यमंत्री इंदिरा आवास के तहत उसको जमीन खरीद कर या सरकारी जमीन उपलब्ध कराकर घर बनाने का काम कर रहे हैं । महोदय, हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार का एस0सी0, एस0टी0 समाज को शिक्षा से, उच्चतर शिक्षा पाने के लिए 50 एस0सी0, एस0टी0 आवासीय विद्यालय का निर्माण करने का लक्ष्य है, जिसमें हमारे कार्यकाल में 10 आवासीय विद्यालयों को 720 बेड का निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान किये है । यह हमारे माननीय मुखिया की देन है । ये लोग कहते हैं 1990 की, 2005 की सरकारें, हमारे भूदेव भाई ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति साहब यहीं के हैं, आर्यभट्ट साहब यहीं के हैं तो भाई 1990 के बाद की जो सरकारें थीं बिहार का नाम रौशन किया था ? 1990 के बाद 2005 तक आप जितने भी महान विभूति थे उनके नाम पर पानी फेरने का काम किये हैं । यह आपकी उपलब्धि है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कंक्लूड कीजिए । सरकार का उत्तर भी होना है ।

श्री रत्नेश सादा : इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 18 विद्वान सदस्यों ने अपनी भावनाओं को इस सदन में अपनी बुद्धि और कौशल के अनुसार, अपनी जानकारी और अपने तजुर्बे के अनुसार रखने का काम किया, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं । महोदय,

बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजों का जिक्र भी हुआ इस पर मैं कुछ बाद में बोलूंगा ।

मुझे सदन में यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के बिजली उपभोक्ता एवं आप सभी के सहयोग से वितरण कंपनियों ने वर्ष 2022-23 में पहली बार 215 करोड़ का लाभ अर्जित किया । 58 साल के बाद पहली बार कंपनी प्रॉफिट में गयी है । प्राप्त जानकारी के अनुसार 2022-23 में बिहार की वितरण कंपनियां देश की पांच लाभ अर्जित करने वाली वितरण कंपनियों में शामिल हो गयी । देश की केवल पांच कंपनियां ही, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस रफ्तार से सरकार बिजली के क्षेत्र में काम कर रही है उससे वर्तमान वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में भी वितरण कंपनियां लाभ में रहेंगी । ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस की भरपाई हेतु वितरण कंपनियां राज्य सरकार से अलग से राशि की मांग करती रही हैं, किंतु इस वर्ष वितरण कंपनियों द्वारा सरकार से ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस के मद में प्रावधानित 1740 करोड़ राशि की मांग नहीं की गयी है जो राज्य के खजाने में बचेंगे और अन्य विकास की योजनाओं पर ये पैसे खर्च होंगे । मैंने पिछले वर्ष बताया था कि बिहार में विगत एक दशक में रात्रि कालीन (Night Time Light-NTL) में 474 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसे इसरो ने प्रकाशित किया था । कोई अलग से नहीं इसरो के द्वारा आकाश से जो फोटो छपी थी उसका मैं जिक्र कर रहा हूं । महोदय, वर्ष 2023 के लिए वितरण कंपनियों की कंज्यूमर सर्विस रेटिंग प्रकाशित की गयी है जिसमें साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ग्रेड डी से बढ़कर बी तथा नॉर्थ बिहार पावर का ग्रेडिंग सी0 से बढ़कर बी0 हो गया है । राज्य की संचरण कंपनियों को पिछले तीन-चार वर्षों से ए श्रेणी की अव्वल रेटिंग प्राप्त हो रही है । राज्य में शहरी क्षेत्र में औसतन 23 से 24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 22 से 23 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है ।

महोदय, सरकार किसानों के हित में काम कर रही है । सरकार का निश्चय है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 18 अक्टूबर, 2023 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर-कमलों द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया जो 2023 से 2028 तक चलाया जायेगा । इसके लिए ऊर्जा विभाग ने राज्य के इच्छुक किसानों को आगामी तीन वर्ष में निःशुल्क कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने की योजना बनाई है । राज्य सरकार ने 9 नवम्बर, 2023 को ही 2 हजार 190 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना स्वीकृत कर ली है जिसमें 4 लाख 80 हजार..

(क्रमशः)

टर्न-26/हेमन्त/23.02.2024

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री(क्रमशः) : किसानों को निःशुल्क कृषि विद्युत संबंधन दिया जायेगा । कृषि विभाग के साथ-साथ संयुक्त रूप से ऊर्जा विभाग द्वारा पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर किसानों से आवेदन लेने हेतु शिविर लगाये जा रहे हैं । आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने-अपने क्षेत्र में किसानों को उत्साहित करें कि वह आवेदन दें । पिछली योजना तीन लाख पचहत्तर हजार किसानों को निःशुल्क विद्युत संबंध दिया गया था । सरकार कृषि फीडरों के माध्यम से कम-से-कम आठ घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति कर रही है और किसानों की आवश्यकता को देखते हुए 16 घंटे तक भी विद्युत की आपूर्ति की गयी है । कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की भी योजना बनायी गयी है, जिससे ऊर्जा की बचत होगी और किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली की आपूर्ति होती रहे ।

महोदय, आप सभी जानते हैं कि राज्य में बिजली के क्रय की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार महंगी दर पर बिजली खरीदने के बावजूद राज्य के ग्रामीण उपभोक्ताओं को किफायती दर पर बिजली दे रही है । किसानों के लिए अतिरिक्त निधि देते हुए मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही विपत्र दिया जाता है । इसका सीधा लाभ किसानों और गरीब उपभोक्ताओं को मिल रहा है । मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के अंतर्गत उपभोक्ता अनुदान के रूप में राज्य सरकार बहुत बड़ी राशि का भार उठा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली मिले । वर्ष 2021-22 में यह राशि 6,578 करोड़ रुपये थी, जो 2022-23 में बढ़ाकर 7,801 करोड़, सस्ती बिजली की जो माननीय सदस्य बात कर रहे हैं उसका मैं जिक्र कर रहा हूं, 2023-24 में 13,114 करोड़ रुपये की गयी है । महंगी दर पर बिजली खरीदकर इतना सब्सिडी और जो उपभोक्ताओं को दिया जाता है, उसमें लिखा हुआ है सरकार की सब्सिडी कितनी है ।

महोदय, एक नयी योजना, जो कुछ माननीय लोग शिकायत कर रहे हैं । कहीं तार टूटा हुआ है, कहीं कोई बात हो रही है । वितरण कम्पनियों के परिचालन क्षमता एवं वित्तीय स्थिरता में सुधार हेतु केंद्र सरकार द्वारा पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना लागू की गयी है । इसके अन्तर्गत लॉस रेडक्शन एवं मॉर्डर्नाइजेशन कार्य हेतु 15,498.62 करोड़ रुपये की कार्य योजना स्वीकृत की गयी है । वर्तमान में लॉस रेडक्शन घटक के कुल 7305.05 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दी गयी है, जिस पर युद्धस्तर पर कार्यान्वयन किया जा रहा है । इस योजना में मुख्य रूप से कृषि कार्य हेतु डेडिकेटेड फीडर का निर्माण, लम्बे फीडरों का विभाजन तथा

एल0टी0 लाईन के खुले तारों को एरियल बंच्ड केबल से बदला जाना है । योजना को पूरे राज्य में युद्धस्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है ।

जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पर्यावरण के संतुलन हेतु राज्य सरकार ने, महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने जल-जीवन-हरियाली योजना जो प्रारंभ की, उसका मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण का संतुलन बनाया जाय । उसको मद्देनजर रखते हुए पांच वर्ष पहले ही वर्ष 2019 में जल-जीवन-हरियाली अभियान प्रारंभ किया था । इस अभियान के तहत सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा की बचत करने का लक्ष्य रखा गया था । इस पर कार्य करते हुए अब तक करीब 3,416 सरकारी भवनों पर लगभग 43 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा चुका है ।

आप जानते हैं कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने भी देश के सभी सरकारी भवनों पर सोलर सिस्टम लगाने की बात कही है । बिहार में आगामी दो वर्षों में लगभग 9,000 सरकारी भवनों पर 65 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगा दिया जायेगा और दूसरे चरण में प्राथमिक विद्यालय से लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी सोलर प्लांट लगाया जायेगा । महोदय, यह बिहार की योजना है, भारत सरकार ने भी इसको अडॉप्ट किया ।

ऊर्जा विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं अन्य विभागों से संपर्क कर राज्य के चौर क्षेत्रों में, जलाशयों में तथा नहरों एवं नदियों के किनारे सोलर प्लांट लगाने की योजना बनायी गयी है । लखीसराय जिले के कजरा में 1810 करोड़ रुपये की लागत पर 185 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता एवं 253.85 MWh बैटरी में सौर ऊर्जा का भंडारण, जो देश में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण की क्षमता है, की परियोजना पर काम प्रारंभ कर दिया गया है । इसकी निविदा निर्गत की जा चुकी है ।

महोदय, बड़े पैमाने पर हो रहे कार्यों को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने उद्योग विभाग से भी समन्वय किया है ताकि राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिले ।

राज्य में पहली बार बिजली के विभिन्न उपकरणों की निर्माता कम्पनियों के साथ ऊर्जा निवेश के नाम से राउण्ड टेबल मीटिंग दिनांक 05 फरवरी, 2024 को की गई जिसमें मीटर निर्माता, ट्रांसफार्मर एवं विभिन्न प्रकार के पैनल तथा कन्डक्टर बनाने वाली लगभग 78 कम्पनियों ने भाग लिया । यह बिहार के इतिहास में पहली घटना है । इसी प्रकार सौर ऊर्जा में सोलर पैनल, बैटरी तथा इन्वर्टर बनाने वाली निर्माता कम्पनियों का पहला ''सोलर-शो'' दिनांक 10 फरवरी, 2024 को

आयोजित किया गया जिसमें सौर ऊर्जा के विभिन्न सामग्रियों के निर्माण से जुड़ी लगभग 23 कम्पनियों ने भाग लिया ।

महोदय, वितरण कम्पनियों की कार्यशैली में सुधार - बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल त्रुटिपूर्ण होने एवं कई-कई महीनों तक बिजली बिल नहीं बनने की समस्या रहती थी । राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने की योजना देश में पहली बार बिहार में लागू की गई जिससे उपभोक्ताओं को सही बिजली बिल सही समय पर मिलना शुरू हो गया । महोदय, बार-बार माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत मिलती थी कि हमारा बिल ज्यादा हो गया । मुख्यमंत्री जी की यह कल्पना दो साल पहले ही हुई कि नहीं, सभी जगह स्मार्ट मीटर लगाया जाय और बिहार देश का पहला राज्य है, जहां 28 लाख अभी तक स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाये जा चुके हैं और राज्य इस क्षेत्र में अभी तक देश में प्रथम स्थान पर है ।

वितरण कम्पनियों द्वारा नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिसके कारण बिलिंग इफिसिएंसी, जो वर्ष 2019-20 में 75.41 प्रतिशत थी, वह वर्ष 2022-23 में बढ़कर 81.08 प्रतिशत हो गई । इसी प्रकार ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस उक्त अवधि में 35.12 से घटकर 24.11 प्रतिशत हो गया ।

देश एवं राज्य में विद्युत की मांग तेजी से बढ़ रही है । इसलिए एक ओर जहां हम सौर ऊर्जा में काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भागलपुर जिले के पीरपैंती में, जिस पर सौर ऊर्जा लगाने का निर्णय लिया गया था, वहां अब कोयला भंडार नजदीक होने के कारण 800 मेगावाट की तीन यूनिट विद्युत केंद्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है । इसके लिए कोयला मंत्रालय के साथ बातचीत की जा रही है ।

वितरण कम्पनियों के द्वारा लगातार मुनाफे की ओर बढ़ने के कारण मैंने वितरण कम्पनियों को कहा है, इसको सुनिये गौर से, कि राज्य सरकार के संसाधनों पर निर्भरता को कम करें । साथ ही, स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिये मैंने वितरण कम्पनियों को एक योजना बनाने के लिए कहा है । ऐसे उपभोक्ता, जो 2000 रुपया से अधिक का रिचार्ज कराते हैं और कम-से-कम तीन माह की खपत के बराबर का रिचार्ज एकमुश्त कराते हैं, उन्हें 5.15 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायेगा, जो जमा करेंगे । ऐसे उपभोक्ता जो तीन माह से लेकर छः माह की अवधि का एकमुश्त रिचार्ज कराते हैं, उन्हें उस राशि पर 5.40 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायेगा तथा छः माह से अधिक की अवधि का एकमुश्त रिचार्ज कराने वाले उपभोक्ताओं को 5.65 प्रतिशत की दर

से ब्याज दिया जायेगा । इस प्रकार स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने वाले हमारे उपभोक्ताओं को बैंक द्वारा दिये जाने वाले 2.70 प्रतिशत से कहीं अधिक का ब्याज प्रोत्साहन के रूप में वितरण कम्पनियां देंगी । इसका मतलब जो एडवांस देंगे तीन महीने का, छः महीने का, एक महीने का, उसको छूट कीजिए इसके लिए हम नियम-कानून बना रहे हैं ।

महोदय, कुछ विद्वान सदस्यों ने जिसमें भूदेव बाबू हैं, कहा कि बिहार की अपनी बिजली, अपनी बिजली क्या होती है यह मेरी समझ में नहीं आता है ? नवीनगर हो या कहीं भी हो, कोयला है भारत सरकार के पास, रेल भारत सरकार के पास, एक्स्पर्ट उनके पास, 80 प्रतिशत बिजली हमारी एग्रीमेंट करके नवीनगर और जितने हमारे पावर प्लांट हैं, भारत सरकार को दे दिये और आज हमारी स्थिति अच्छी है । कहीं-कोई दिक्कत नहीं हो रही है । आज साढ़े तीन लाख करोड़ बकाया है एनटीपीसी का अन्य राज्यों पर, बिहार ऐसे राज्यों में नहीं है । यह लाभ हुआ है हमारा स्मार्ट मीटर लगाने से । लेकिन महोदय, बिजली बिल गलत के सुधार के लिए मैंने 18000 करोड़ की योजना का....

(व्यवधान)

महोदय, एक जिक्र मैं करना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

बैठिये, बैठिये । मेरे कन्स्टीचुयेंसी में एक महिला बूढ़ी आयी...

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि...

अध्यक्ष : क्यों कहना चाहते हैं, बोलने दीजिए मंत्री जी को । बैठिये । बोलिये, मंत्री जी ।

श्री सत्यदेव राम : बिहार में आर्थिक सर्वे हुआ और हम माननीय मंत्री से मांग करते हैं कि 200 यूनिट फ्री दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, ये सुनने को तैयार नहीं हैं कि साढ़े चौदह हजार करोड़ रुपया, इसलिए महोदय, एक महिला आयी...

(व्यवधान)

टर्न-27/धिरेन्द्र/23.02.2024

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इसलिए महोदय, एक महिला आयी....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अच्छी बात सुनिये ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, गरीबों का सवाल है । सरकार को आज घोषणा करनी चाहिए । माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इस पर वे अपनी बात रखें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, एक महिला आयी, उसने कहा कि मेरा दो बल्ब जलता है और दो हजार का बिल आया । 07 बजे मैं उनके यहाँ चला गया, वे हमको देखी तो भाग खड़ी हुई और उसके यहाँ जब हमने देखा तो वे लौट कर भी नहीं आयी । बिजली का दुरूपयोग भी रोकने के लिए हमलोगों को इंतजाम करना चाहिए । दिन में भी लाईन जलता रहता है....

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप लोगों को निकल कर जाना है और पहले से जानते नहीं थे, आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं न कि मुफ्त में नहीं दिया जायेगा और बहुत कम पैसे में हमलोग देते हैं और इसीलिए देते हैं कि वह सुरक्षित रहे । कितना कम पैसा में देते हैं । कितना पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में और कितना कम पैसा में देते हैं । आप सब लोग रहे हैं, एक-एक बात जानते रहे हैं, अब आज बोल रहे हैं और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे और हम तो शुरू से यहाँ बोलते रहे हैं, बाहर बोलते रहे हैं, यहाँ तक कि चुनाव के दौरान, जब भी चुनाव होता था, वहाँ पर भी हम खड़ा हो कर बोल देते थे कि यह सब की सुरक्षा के लिए है । अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का-सा पैसा लग रहा है तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं, हम तो सब की सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं । तब आपलोग कुछ सोचिये, चुपचाप बैठिये और ये तो बिल्कुल ही ईमानदार आदमी हैं और खूब बढ़िया से काम कर रहे हैं । इनकी बात सुन लीजिये । बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आप एक मिनट सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांत रहिये । माननीय मंत्री जी बोलिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, बगल के राज्यों का बिल भी ये लोग देखें, बिहार के कंज्यूमर का बिल भी देखें, अगर अन्य राज्यों से ज्यादा महंगा होगा तो हम निश्चित रूप से सस्ता करेंगे और नहीं तो अनावश्यक कुछ बोलते रहना है, अनाप-शनाप बोलते रहना है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

जैसा मैंने कहा महोदय, तीन लाख करोड़ रुपये बकाया है । यह फ्री बिजली कब तक चलेगी, कहाँ से आयेगा पैसा । पैसा कोई घास में फलता नहीं है, पैसा तो कहीं-न-कहीं से पब्लिक पर ही जायेगा । इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से यह कान्सेप्ट रहा है कि फ्री बिजली के हम खिलाफ हैं, किसी चीज में सस्ती बिजली, उन्होंने घोषणा भी की थी कि गरीब-गुरबा, गाँव के गरीब सभी को मुफ्त में, फ्री बिजली नहीं लेकिन उसके बिल में लिखा हुआ होगा कितना, मैंने जैसा कहा कि 14 हजार करोड़ से अधिक....

अध्यक्ष : सब्सिडी लिखा रहता है कि कितना सरकार सब्सिडी दे रही है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक हमलोग उसमें सब्सिडी देते हैं । अब इससे अधिक क्या सुविधा चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में साधारण कंज्यूमर को और ज्यादा है । बाहर से सस्ती बिजली मिलती है । इसलिए महोदय, अब स्वाभाविक है, पार्टी है, अपनी-अपनी विचारधारा है । आज से 10-15 दिन पहले महागठबंधन की सरकार थी तो चार लाख नौकरी मिली तो उसका श्रेय ले रहे हैं और बिजली में प्रॉफिट में कंपनी गयी तो उसका श्रेय मुख्यमंत्री जी को नहीं है, इसका श्रेय उनको है । महोदय, संविधान में व्यवस्था है- To add and advice, there shall be council of Minister मुख्यमंत्री के सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद में कोई कोरम नहीं होता है, कोई वोटिंग नहीं होता है । इसलिए आज अगर नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है तो बिहार में नीतीश कुमार जी की कंस्टीच्यूशनल रिस्पांसब्लिटी की सुविधा है लेकिन संविधान से इन लोगों को क्या मतलब है । क्या मतलब है संविधान से ? पलटीमार कहते हैं । जरा बताइये, वर्ष 1997 में आये थे, वर्ष 1995 में आये थे काँग्रेस के खिलाफ न आये थे । वर्ष 1997 में जब आर॰जे॰डी॰ बनी तो किसके समर्थन से सरकार बनी थी ? जो काँग्रेस इनके पिता जी को बंद किया, हमलोगों को भी जेल में बंद किया, उसके साथ ये कैसे चले गए ? वैशाली में कहा था कि मेरी लाश, घुटनाटेक मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मेरी लाश पर बिहार का बंटवारा होगा और जब काँग्रेस ने समर्थन दिया....

अध्यक्ष : मै तो गवाह भी था ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : तो कैसे राबड़ी जी की सरकार को बचाने के लिए झारखंड के मामले में सहमति हो गयी ? तो बोलते कुछ हैं और आचरण कुछ है, आज राजनीति की विरासत यह है महोदय कि बोली में और कर्म में महान अंतर वाले जो लोग हैं वही अपने को क्रांतिकारी मानते हैं, जो काम करता है, परिणाम देता है तो उसकी चर्चा लोग नहीं करते हैं । हमारे यहाँ मिथिला में एक कहावत है-

हर बहे से खर खाये, बकरी खाये आचार ।

तो जो काम नहीं करे, वे पूरा वातावरण, परिवार, अब नीतीश जी की कृपा से ही दो बार जो उप मुख्यमंत्री बने और बड़ा भारी क्रांतिकारी नेता हो गये । नौवां पास भी नहीं है, नौवां की परीक्षा तो होती नहीं है लेकिन इनकी कृपा से दो बार उप मुख्यमंत्री बने, पिता जी की कृपा से नहीं । पिता जी की कृपा से नहीं, पिता जी की कृपा से जरूर उनकी माँ बनी लेकिन यहाँ क्रांतिकारी भाषण दे रहे हैं तो अद्‌भुत चीज है । वचन, कर्म में महान अंतर, आज देश की राजनीति की विरासत के लिए खतरनाक स्थिति है महोदय, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आचरणहीन नहीं चला सकता है और महोदय, बिहार का, मैं फिर निवेदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि बिहार गंगा-यमुनी सभ्यता में सबसे अधिक आबादी घनत्व है, हिमालय के बेसिन में होने से, सात नदियाँ पेरेलियन रिवर है जो बारहमासी नदी कहलाती है, बर्फ जब गर्मी में पिघलता है अन्य नदियाँ सुख जाती है, बिहार की नदियां बर्फ के पिघलने से भर जाती है, हल्की बारिश या वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है और सबसे अधिक गंगा-यमुनी सभ्यता होने के कारण स्वच्छ पानी की आसानी से उपलब्धता और हवा उपलब्ध होना, इसके लिए ज्यादा-से-ज्यादा आबादी गंगा-यमुना इलाके में बसी । इसलिए मैं फिर से सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की कृपा करें या विशेष पैकेज देने की कृपा करें ताकि बिहार का समुचित विकास और आगे हो और ज्यादा, अब गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर उठे हैं बिहार में, रिकॉर्ड है महोदय, सबसे ज्यादा तो काम नहीं हुआ है तो यह कहाँ से और महोदय, मैं एक बात और निवेदनपूर्वक कहना चाहूँगा कि गरीब लोग बिजली बिल निर्धारित समय पर पेमेंट करते हैं, वी॰आई॰पी॰ लोग ही गड़बड़ करते हैं । अगर आप इलाका देखें, मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ । ग्रामीण क्षेत्र में घाटे में बिजली नहीं है, वी॰आई॰पी॰ इलाके में ही कड़ाई करनी पड़ी है । अब यहाँ जो सिस्टम डेवलप किये हैं कि ट्रांसफॉर्मर में कितना मेगावाट पावर जा रहा है, बिजली बिल कितना आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, गंगा में जा रहा है क्या या धरती में जा रहा है क्या ? इसलिए इस सिस्टम को ठीक करने के लिए यह कड़ाई की गई है और ए॰टी॰ एण्ड सी॰ लॉस घटा है । अब पाँच कंपनियों में बिहार आयी है । इसलिए महोदय, अब ये लोग तो चले गए, अब इन लोगों से क्या निवेदन करना है और कितना भी निवेदन कीजिये....

अध्यक्ष : आप निवेदन का प्रयास ही कीजिये, उससे आगे मत कीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह आदत सुधरेगी नहीं । महोदय, इसलिए अंत में मैं निवेदन सभी से करना चाहूँगा कि इस मॉग को पारित करने की कृपा करें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''ऊर्जा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 11422,67,80,000/- (ग्यारह हजार चार सौ बाईस करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माँग स्वीकृत हुई ।

टर्न-28/संगीता/23.02.2024

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगें गिलोटीन के माध्यम से ली जायेंगी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए :-

मांग संख्या-01, कृषि विभाग के संबंध में 3600,92,08,000/-

(तीन हजार छः सौ करोड़ बानवे लाख आठ हजार) रुपये,

मांग संख्या-02, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 1631,34,61,000/-

(एक हजार छः सौ इकतीस करोड़ चौंतीस लाख इकसठ हजार) रुपये,

मांग संख्या-03, भवन निर्माण विभाग के संबंध में 5012,65,48,000/-

(पांच हजार बारह करोड़ पैंसठ लाख अड़तालीस हजार) रुपये,

मांग संख्या-04, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 467,24,73,000/-

(चार सौ सड़सठ करोड़ चौबीस लाख तिहत्तर हजार) रुपये,
मांग संख्या–06, निर्वाचन विभाग के संबंध में 848,32,52,000/–
(आठ सौ अड़तालीस करोड़ बत्तीस लाख बावन हजार) रुपये,
मांग संख्या–07, निगरानी विभाग के संबंध में 45,59,71,000/–
(पैंतालीस करोड़ उनसठ लाख इकहत्तर हजार) रुपये,
मांग संख्या–08, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 259,99,90,000/–
(दो सौ उनसठ करोड़ निन्यानवे लाख नब्बे हजार) रुपये,
मांग संख्या–11, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के संबंध में 1687,29,61,000/–
(एक हजार छः सौ सत्तासी करोड़ उनतीस लाख इकसठ हजार) रुपये,
मांग संख्या–12, वित्त विभाग के संबंध में 1088,53,82,000/–
(एक हजार अठ्ठासी करोड़ तिरेपन लाख बयासी हजार) रुपये,
मांग संख्या–15, पेंशन के संबंध में 31777,04,89,000/–
(इकत्तीस हजार सात सौ सतहत्तर करोड़ चार लाख नवासी हजार) रुपये,
मांग संख्या–16, पंचायती राज विभाग के संबंध में 11025,84,21,000/–
(ग्यारह हजार पच्चीस करोड़ चौरासी लाख इक्कीस हजार) रुपये,
मांग संख्या–17, वाणिज्य कर विभाग के संबंध में 237,95,86,000/–
(दो सौ सैंतीस करोड़ पंचानवे लाख छियासी हजार) रुपये,
मांग संख्या–18, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 1250,19,91,000/–
(एक हजार दो सौ पचास करोड़ उन्नीस लाख इक्यानवे हजार) रुपये,
मांग संख्या–19, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 853,02,79,000/–
(आठ सौ तिरेपन करोड़ दो लाख उनासी हजार) रुपये,
मांग संख्या–20, स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 14932,09,34,000/–
(चौदह हजार नौ सौ बत्तीस करोड़ नौ लाख चौंतीस हजार) रुपये,
मांग संख्या–21, शिक्षा विभाग के संबंध में 52639,02,61,000/–
(बावन हजार छः सौ उनतालीस करोड़ दो लाख इकसठ हजार) रुपये,
मांग संख्या–22, गृह विभाग के संबंध में 16323,83,06,000/–
(सोलह हजार तीन सौ तेईस करोड़ तिरासी लाख छः हजार) रुपये,
मांग संख्या–23, उद्योग विभाग के संबंध में 1833,08,64,000/–
(एक हजार आठ सौ तैंतीस करोड़ आठ लाख चौंसठ हजार) रुपये,

मांग संख्या–24, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंध में 254,23,97,000/–
(दो सौ चौवन करोड़ तेईस लाख संतानवे हजार) रुपये,
मांग संख्या–25, सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 278,43,63,000/–
(दो सौ अठहत्तर करोड़ तैंतालीस लाख तिरेसठ हजार) रुपये,
मांग संख्या–26, श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 1226,41,83,000/–
(एक हजार दो सौ छब्बीस करोड़ इकतालीस लाख तिरासी हजार) रुपये,
मांग संख्या–27, विधि विभाग के संबंध में 1315,13,23,000/–
(एक हजार तीन सौ पंद्रह करोड़ तेरह लाख तेईस हजार) रुपये,
मांग संख्या–29, खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 63,11,43,000/–
(तिरेसठ करोड़ ग्यारह लाख तैंतालीस हजार) रुपये,
मांग संख्या–30, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 648,65,89,000/–
(छः सौ अड़तालीस करोड़ पैंसठ लाख नवासी हजार) रुपये,
मांग संख्या–31, संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 9,87,11,000/–
(नौ करोड़ सतासी लाख ग्यारह हजार) रुपये,
मांग संख्या–32, विधान मंडल के संबंध में 284,30,12,000/–
(दो सौ चौरासी करोड़ तीस लाख बारह हजार) रुपये,
मांग संख्या–33, सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 1025,11,46,000/–
(एक हजार पच्चीस करोड़ ग्यारह लाख छियालीस हजार) रुपये,
मांग संख्या–35, योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 2216,48,35,000/–
(दो हजार दो सौ सोलह करोड़ अड़तालीस लाख पैंतीस हजार) रुपये,
मांग संख्या–36, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 1848,22,19,000/–
(एक हजार आठ सौ अड़तालीस करोड़ बाईस लाख उन्नीस हजार) रुपये,
मांग संख्या–37, ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 9532,31,38,000/–
(नौ हजार पांच सौ बत्तीस करोड़ इकत्तीस लाख अड़तीस हजार) रुपये,
मांग संख्या–38, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 674,55,28,000/–
(छः सौ चौहत्तर करोड़ पचपन लाख अठ्ठाईस हजार) रुपये,
मांग संख्या–39, आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 9542,85,21,000/–
(नौ हजार पांच सौ बयालीस करोड़ पचासी लाख इक्कीस हजार) रुपये,
मांग संख्या–40, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 1871,48,31,000/–
(एक हजार आठ सौ इकहत्तर करोड़ अड़तालीस लाख इकत्तीस हजार) रुपये,
मांग संख्या–42, ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 14296,71,15,000/–

(चौदह हजार दो सौ छियानवे करोड़ इकहत्तर लाख पन्द्रह हजार) रुपये,

मांग संख्या-43, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 1072,30,98,000/-

(एक हजार बहत्तर करोड़ तीस लाख अंठानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या-44, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 1802,72,84,000/-

(एक हजार आठ सौ दो करोड़ बहत्तर लाख चौरासी हजार) रुपये,

मांग संख्या-45, गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 123,79,95,000/-

(एक सौ तेईस करोड़ उनासी लाख पंचानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या-46, पर्यटन विभाग के संबंध में 462,43,52,000/-

(चार सौ बासठ करोड़ तैंतालीस लाख बावन हजार) रुपये,

मांग संख्या-47, परिवहन विभाग के संबंध में 451,46,06,000/-

(चार सौ इक्यावन करोड़ छियालीस लाख छः हजार) रुपये,

मांग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 11298,72,44,000/-

(ग्यारह हजार दो सौ अंठानवे करोड़ बहत्तर लाख चौवालीस हजार) रुपये,

मांग संख्या-50, लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 1030,95,48,000/-

(एक हजार तीस करोड़ पंचानवे लाख अड़तालीस हजार) रुपये,

मांग संख्या-51, समाज कल्याण विभाग के संबंध में 8238,56,50,000/-

(आठ हजार दो सौ अड़तीस करोड़ छप्पन लाख पचास हजार) रुपये,

मांग संख्या-52, खेल विभाग के संबंध में 183,19,92,000/-

(एक सौ तिरासी करोड़ उन्नीस लाख बानवे हजार) रुपये,

से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-23 फरवरी, 2024 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-45 (पैंतालीस) है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-27 फरवरी, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।